



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

No. 152]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 29, 2012/आषाढ़ 8, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 29, 2012/ASADHA 8, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 जून, 2012

विषय : चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" के आयातों के बारे में लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा—अंतिम जांच परिणाम।

क. पृष्ठभूमि:

सं. 15/18/2010-डीजीएडी.—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा-शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे पाटनरोधी नियमावली कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए चीन जन.गण. (जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के या वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयात पर 14 जुलाई, 2000 की अधिसूचना सं. 17/1/99-डी जी ए डी के तहत मूल रूप में निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की गई थी। यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) द्वारा की गई निर्णायक समीक्षा के बाद प्राधिकारी ने 5 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना सं. 15/9/2003-डीजीएडी के तहत निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश की थी और चूंकि केन्द्र सरकार ने 15 जून, 2006 को अपनी अधिसूचना सं. 61/2006-सी.शु. जारी की थी।

2. यतः मै. आरती इंस लि. और मै. यूनीकम लेबोरेटरीज लि. (भारत) ने चीन जन. गण. के मूल के या वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" के पाटन का आरोप लगाते हुए अधिनियम और पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत् पुष्टिकृत आवेदन दायर किया है और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसमें संशोधन करने तथा उसे जारी रखने का अनुरोध किया है। आवेदकों ने दावा किया है कि वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपना उत्पादन पहले ही बंद कर दिया है। अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन बनता है।

3. और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9(5) के अनुसार प्राधिकारी ने लागू शुल्क को सतत रूप से लागू रखने की जरूरत की समीक्षा करने और इस बात की जांच करने के लिए कि क्या ऐसे शुल्क को समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करते हुए 30 मई, 2011 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया।

और यतः 15 जून, 2006 की अधिसूचना सं. 61/2006-सी.शु. के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिनियम की धारा 9(क)(5) के अनुसार 15 जून, 2011 की अधिसूचना सं. 48/2011-सी.शु. के तहत बढ़ाकर 14 जून, 2012 कर दी गई थी।

4. तथापि, यह नोट किया जाता है कि मै. आरती ड्रग्स लि. ने जांच अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 तक के दौरान *** मी.ट. के कुल आयातों में से शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत *** मी.ट. संबद्ध वस्तु का आयात किया है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि ये आयात उनकी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक थे।

5. विरोधी हितबद्ध पक्षकार ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए अपने अनुरोध दायर किए हैं कि मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से अलग रखा जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने भी इस विषय पर अपने अनुरोध दायर किए हैं। मै. आरती ड्रग्स लि. को शामिल करने/अलग रखने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से अलग रखना उचित नहीं होगा। इसके परिणामस्वरूप मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज संबद्ध वस्तु की एकमात्र शेष उत्पादक होने के कारण घरेलू उद्योग बन जाएगी और इस प्रकार वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करती है।

ख. प्रक्रिया

6. इस कार्रवाई में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:

- i. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(2) के अनुसार भारत स्थित संबद्ध देश के दूतावास को जांच की शुरुआत के बारे में सूचित किया गया था।
- ii. प्राधिकारी ने 30 मई, 2011 की जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना की प्रतियां संबद्ध देश के दूतावास, उसके पास उपलब्ध सूचना के अनुसार संबद्ध देश के ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों, ज्ञात आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों तथा घरेलू उद्योग को भेजीं। इस जांच के पक्षकारों से अनुरोध किया गया था कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दायर करें और लिखित में अपने विचारों से अवगत कराएं। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावलियों की प्रतियां इस अनुरोध के साथ ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों की सूची सहित संबद्ध देश के दूतावास को भी भेजी गई थीं कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावलियों का उत्तर देने के लिए संबद्ध देश के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें।
- iii. संगत सूचना मांगने के लिए पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं :

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	मै. ग्रेट चांग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि., शेनडॉंग, चीन जन.गण.
2.	मै. चायनो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक इंप. एंड एक्स. जियामेन कंपनी, चीन जन.गण.
3.	मै. जियांगशू वूओ टाई इंट. ग्रुप कं. लि., चीन जन.गण.
4.	मै. हुबेई होगी मेडिकल एंड कैमिकल इंड कंपनी लि., चीन जन.गण.
5.	मै.हुआंगगांग योंगान फार्मास्युटीकल कं. लि., चीन जन.गण.
6.	मै. क्विंगडाओ डेकोन ट्रेडिंग कं. लि., चीन जन.गण.
7.	मै. चेंगझोऊ गुडजॉब बायोकेमिकल कं. लि., चीन जन.गण.
8.	मै. क्विंगडाओ डेकोन ट्रेडिंग कं. लि., चीन जन.गण.
9.	मै. सीबाओ बायोटेक इंप., चीन जन.गण.
10.	मै. क्विंगडाओ फ्रेंकन इंट. ट्रेडिंग कंपनी लि., चीन जन.गण.
11.	मै. जियांगशी डांगशू कैमिकल टेक्नोलॉजी कंपनी लि., चीन जन.गण.
12.	मै. शंघाई फाइन कैमिकल्स कंपनी लि., चीन जन.गण.
13.	मै शीजियाझुआंग विचर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रेडिंग कं. लि., चीन जन.गण.
14.	मै. शेनडॉंग मिंगयूआन इंप एंड एक्स. कं. लि., चीन जन.गण.
15.	मै. गुआंगझोऊ साइनि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कं. लि., चीन जन.गण.
16.	मै. शिजियाझुआंग हुईकांगयुआन मैडिसिन कं. लि., चीन जन.गण.

इसके प्रत्युत्तर में मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण. जो संबद्ध देश का एक निर्यातक/उत्पादक है, ने प्रश्नावलियों का उत्तर दायर किया है।

iv. आवश्यक सूचना मांगते हुए भारत स्थित संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात घरेलू उत्पादकों, आयातकों, प्रयोक्ताओं और एसोसिएशनों को प्रश्नावलियां भेजी गई थीं:

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1.	मै. आरती ड्रग्स लि., मुंबई
2.	मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज, मुंबई

3.	मै. यूनीक केमिकल्स, मुंबई
4.	मै. एरे ड्रग्स एंड फार्मा लि., थाणा, मुंबई
5.	मै. एडवेंट फार्मा प्रा. लि., मुंबई
6.	मै. एसी लेबोरेटरीज लि., दिल्ली
7.	मै. एल्केम लेबोरेटरीज लि., मुंबई
8.	मै. अमोली आर्गनिक्स प्रा.लि., मुंबई
9.	मै. कन्सेप्ट फार्मा लि., मुंबई
10.	मै. डोस फार्मा क., मुंबई
11.	मै. डी डब्ल्यू डी फार्मा लि., मुंबई
12.	मै. फ्लेमिंगो फार्मा लि., मुंबई
13.	मै. इंडो फार्मा, मुंबई
14.	मै. लार्क केमिकल्स (प्रा.) लि., मुंबई
15.	मै. लितिका फार्मा लि., पुणे
16.	मनीश फार्मा प्रा.लि., मुंबई
17.	मै. मेडी फार्मा ड्रग हाउस, मुंबई
18.	मै. मरकरी लेबोरेटरीज लि., मुंबई
19.	मै. न्यू जेनेरिक ड्रग हाउस, मुंबई
20.	मै. पेनासिया बायोटेक लि., नई दिल्ली
21.	मै. श्रीजी भवन, मुंबई
22.	मै. शुभम फार्मा केम (प्रा.) लि., मुंबई
23.	मै. स्मृति आर्गनिक्स लि., मुंबई
24.	मै. यूनीबायोज लेबोरेटरीज लि., मुंबई
25.	मै. यूनीक फार्मा लैब्स, मुंबई

- v. जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के उत्तर में,
- vi. वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस), कोलकाता से अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि तथा पूर्ववर्ती तीन वर्षों के लिए भारत में संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरे प्रदान करे ।
- vii. नियम 6 (7) के अनुसार, प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण प्राधिकारी द्वारा रखी गई सार्वजनिक फाइल के जरिए उपलब्ध कराया और उसे हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षणार्थ खुला रखा ।
- viii. प्राधिकारी ने सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जी ए ए पी) के आधार पर घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना की संभव सीमा तक जांच की है ताकि क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना का विश्लेषण किया जा सके और भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत एवं क्षति रहित कीमत निकाली जा सकें और यह सुनिश्चित किया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।
- ix. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (6) के अनुसार 19 सितंबर, 2011 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त करने के लिए सभी हितबद्ध पक्षकारों को अवसर भी प्रदान किया । जिन पक्षकारों ने सार्वजनिक सुनवाई में अपने विचार मौखिक रूप से व्यक्त किए थे उनसे यह अनुरोध किया गया था कि वे मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें । हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त लिखित अनुरोधों ने दिए गए तर्कों पर प्रकटन विवरण में जहां संगत पाया गया है, विचार किया गया है ।
- x. वर्तमान समीक्षा के प्रयोजनार्थ जांच अवधि 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 (12 माह) की है । तथापि, क्षति विश्लेषण में वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10 और जांच अवधि शामिल होगी । पाटन और क्षति की संभावना का निर्धारण करने के लिए जांच अवधि से आगे के आंकड़ों की भी जांच की जा सकती है ।
- xi. घरेलू उत्पादकों और चीन जन.गण. के सहयोगी निर्यातक/उत्पादक द्वारा प्रस्तुत सूचना एवं आंकड़ों के संबंध में आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया था ।
- xii. पाटनरोधी नियमावली के नियम 16 के अनुसार, वर्तमान जांच में प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन आवश्यक तथ्यों का प्रकटन ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को किया गया था । प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों पर संगत समझी गई सीमा तक इस जांच परिणाम में विचार किया गया है ।

xiii. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी । संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है । जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं ।

xiv. जहां किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच के दौरान आवश्यक सूचना जुटाने से मना किया है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने "उपलब्ध तथ्यों" के आधार पर यह जांच परिणाम दर्ज किया है ।

xv. *** यह चिन्ह इस विवरण में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत उसे गोपनीय ही माना है ।

ग. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रकटन विवरण के बाद किए गए अनुरोध और उनकी जांच

मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण.,

7. प्रकटन विवरण के उत्तर में मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण. ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यहां तक कि मात्रा संबंधी सूचना भी गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है ।
- प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन निकालने के प्रयोजनार्थ डी पी सी ओ अधिकतम कीमत पर सही ढंग से विचार किया है । तथापि ऐसे क्षति मार्जिन की गणना मौजूदा डी पी सी ओ अधिकतम कीमत के आधार पर की जानी चाहिए जो 514 रूपए प्रति किग्रा. है ।
- उपायों का स्वरूप : घरेलू उद्योग का शुल्क के बैचमार्क स्वरूप के कारण वित्तीय घाटे के बारे में किया गया दावा निराधार है । प्रथमतः उपायों का स्वरूप (निर्धारित या बैचमार्क) शुल्क के बैचमार्क स्वरूप के अंतर्गत ऐसे घाटे का कारण नहीं हो सकता क्योंकि घरेलू उद्योग को तत्स्थपरक रूप से निर्धारित स्तर तक संरक्षण जारी है । यह बात मानते हुए परंतु उसे स्वीकार न करते हुए कि घरेलू उद्योग को वित्तीय घाटा शुल्क के स्वरूप के कारण हुआ है तो स्पष्ट प्रश्न यह उठता है कि घरेलू उद्योग पिछले 10 वर्ष से मौन क्यों था और उसने समीक्षा के लिए प्राधिकारी से संपर्क क्यों नहीं किया । इसके अलावा इस मामले में डी पी सी ओ कीमत पर आधारित केवल संदर्भ कीमत पर शुल्क की संस्तुति की जाए क्योंकि संबद्ध उत्पाद की कीमतें डी पी सी ओ द्वारा नियंत्रित हैं, अतः प्राधिकारी के लिए वर्तमान मामले में डी पी सी ओ 1995 के अंतर्गत अधिसूचित अधिकतम बिक्री कीमत के स्तर तक बैचमार्क पाटनरोधी शुल्क अपेक्षित है ।

- जांच अवधि के बाद अम.डा. के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि को देखते हुए तथा डी पी सी ओ ने भी भारतीय रूपए में बैचमार्क निर्धारित किया है, अनुरोध है कि निश्चयात्मक शुल्क यदि लगाना अपेक्षित हो तो उसे भारतीय रूपए में संदर्भ कीमत के आधार पर संस्तुत किया जाए ।
- ए डी एल द्वारा किए गए आयातों के कारण याचिकाकर्ता द्वारा छिपाई गई सूचना : सामान्यतः ऐसी सूचना छिपाए जाने से स्वतः जांच का निर्धारण नहीं किया जा सकता । स्पष्ट प्रश्न यह है कि घरेलू उद्योग ने अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत ए डी एल द्वारा किए गए आयातों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों को गलत सूचना क्यों प्रदान की है । इस चरण पर ऐसे आयातों के आधार पर ए डी एल के आंकड़ों को हटाया जाना नियमों के अनुसार किया गया प्रतीत नहीं होता है । इस मामले में प्राधिकारी के लिए इस बात का मूल्यांकन करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग गलत सूचना का प्रकटन कर हितबद्ध पक्षकारों को जानबूझकर गुमराह कर सकता है ।
- क्षति निर्धारण : यूनीकैम का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 29.36 प्रतिशत बनता है । इसका तात्पर्य यह है कि जांच अवधि के दौरान यूनीकैम का उत्पादन लगभग 246 मी.ट. था जिसमें कुल भारतीय उत्पादन में से ए डी एल द्वारा किया गया उजरती कार्य उत्पादन शामिल है जो 838 मी.ट. था । यह नोट किया जाना चाहिए कि गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी पी सी बी) द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों के कारण ए डी एल का संयंत्र जांच अवधि के दौरान 3-4 माह तक बंद रहा था जिसकी वजह से जांच अवधि में कम भारतीय उत्पादन हुआ होगा । यूनीकैम एक लघु उत्पादक है क्योंकि उसका खुद का उत्पादन क्षति अवधि के दौरान भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम रहा होगा और इसलिए यूनीकैम के आंकड़ों के आधार पर क्षति निर्धारण से तथ्यपरक विश्लेषण तथा उचित निर्धारण नहीं किया जा सकेगा । इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि क्षति अवधि के दौरान यूनीकैम के द्वारा किए गए उजरती कार्य की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है । इसका तात्पर्य यह है कि किए गए उजरती कार्य के कारण क्षति अवधि के दौरान (पूर्ववर्ती वर्षों) यूनीकैम का क्षमता उपयोग कम रह सकता है । अतः प्राधिकारी को उजरती कार्य की वजह से उत्पादन क्षमताओं के अकुशल उपयोग के कारण घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो को निष्फल ठहराने के लिए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण हेतु 100 प्रतिशत क्षमता उपयोग पर विचार करना चाहिए ।

घरेलू उद्योग

8. प्रकटन विवरण के उत्तर में घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत के आधार पर किया जाना चाहिए न कि डी पी सी ओ कीमत के आधार पर जिसके निम्नलिखित कारण हैं :-
(क) आयातों की पहुंच कीमत डी पी सी ओ और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है और इसलिए आयातों की कम कीमत के कारण घरेलू उद्योग डी पी सी ओ कीमत से बराबर कीमत को भी प्राप्त करने से वंचित हुआ है । चूंकि घरेलू उद्योग डी पी सी ओ कीमत पर बिक्री नहीं कर रहा है, इसलिए घरेलू उद्योग को डी पी सी ओ कीमत के कारण क्षति नहीं हो रही है बल्कि पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है ।

(ख) उद्योग ने डी पी सी ओ कीमत के पिछले निर्धारण के बाद कच्ची सामग्री की कीमत में हुई अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए डी पी सी ओ कीमत को वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 672 रूपए प्रति किग्रा. करने की मांग की है। घरेलू उद्योग का अनुरोध एन पी पी ए के विचाराधीन है।

(ग) वर्तमान मामला ऐसे किसी उत्पाद का पहला मामला नहीं है जिसकी कीमत डी पी सी ओ के अधीन अधिसूचित हो और जहां अधिकारी ने पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की हो। प्राधिकारी ने इससे पूर्व डी पी सी ओ कीमत को पाटनरोधी प्रयोजन हेतु बाध्यकारी नहीं माना है। इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कुछ अंतिम जांच परिणामों का हवाला दिया गया है जिनमें प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षति रहित कीमत डी पी सी ओ द्वारा अधिसूचित कीमत से अधिक या कम है परंतु प्राधिकारी ने क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु डी पी सी ओ कीमत पर विचार नहीं किया है। अतः प्राधिकारी को डी पी सी ओ कीमत पर विचार करते हुए क्षति मार्जिन का निर्धारण नहीं करना चाहिए।

(घ) पाटन कानून के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए “घरेलू उद्योग को हुई क्षति” का निर्धारण करना अपेक्षित है। पाटनरोधी मामले में घरेलू उद्योग के भागस्वरूप उद्योग की संरचना एन पी पी ए के प्रयोजनार्थ उद्योग की संरचना की तुलना में भिन्न हो सकती है।

(ङ) क्षतिरहित कीमत और क्षति मार्जिन का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा चुनी गई जांच अवधि के लिए करना अपेक्षित है। मात्र इस वजह से कि जांच अवधि के दौरान कुछ डी पी सी ओ कीमत प्रचलित थी, इसका तात्पर्य यह नहीं है कि यह जांच अवधि के लिए क्षतिरहित कीमत है। प्राधिकारी के लिए जांच अवधि के दौरान क्षतिरहित कीमत के आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित है। ऐसी किसी कीमत जो इस अवधि में विद्यमान नहीं है, पर विचार करना पाटन कानून के विभिन्न उपबंधों के प्रतिकूल होगा। प्राधिकारी के लिए क्षतिरहित कीमत संबंधी कानून का पालन करना अपेक्षित है।

(च) इस बात की प्रबल संभावना है कि जहां प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिरहित कीमत डी पी सी ओ कीमत से कम हो और प्राधिकारी ने उन मामलों में उच्चतर डी पी सी ओ कीमत को नहीं अपनाया हो। इसके विपरीत मात्र इस वजह से कि डी पी सी ओ कीमत कम है, निर्धारित क्षति रहित कीमत को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। मांग के निर्धारण में निष्पक्षता और तथ्यात्मकता के सिद्धांतों को प्राधिकारी द्वारा वर्तमान मामले में उसी तर्काधार पर लागू किया जाना चाहिए।

(छ) जांच प्राधिकारी के रूप में प्राधिकारी के लिए आंकड़ों/सूचना की तथ्यपरक जांच के आधार पर कार्रवाई करना अपेक्षित होता है और इसके स्थान पर वस्तुपरक विचारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

- सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण के बारे में घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के निर्धारण हेतु अपनाई गई कार्यप्रणाली की उन्हें जानकारी नहीं है और ऐसा प्रतीत होता है कि परिकलित सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन में इस वजह से संशोधन करना अपेक्षित है कि खपत कारक, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और वित्तीय लागत घरेलू उद्योग पर आधारित नहीं हैं। उन्होंने आगे यह बताया है कि प्राधिकारी को सत्यापन के बाद जांच अवधि के लिए घरेलू उद्योग और न कि अन्य घरेलू उत्पादक की सूचना पर विचार करना चाहिए।

- निर्धारित मात्रा आधार पर शुल्क : चीन से आयातों पर इस उत्पाद के संबंध में शुल्क का बैंचमार्क स्वरूप लागू है । प्राधिकारकर्ता ने प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वे कृपया अम.डा./किग्रा. में शुल्क के रूप में व्यक्त वर्तमान निर्णायक समीक्षा में शुल्क के निर्धारित स्वरूप की सिफारिश करें जिसके निम्नलिखित कारण हैं :-

- घरेलू उद्योग को सतत क्षति-घरेलू उद्योग को पाटित आयातों के कारण सतत क्षति हो रही है जिसकी वजह यह है कि प्राधिकारी ने इस स्थापित तथ्य कि शुल्क का स्वरूप घरेलू उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है, के बावजूद शुल्क का बैंचमार्क स्वरूप निर्धारित किया है । आयात कीमत की इस प्रकार सूचना दी जा रही है कि आयातों की पहुंच कीमत बैंचमार्क से अधिक है, परिणामतः इन आयातों पर कोई पाटनरोधी शुल्क वसूल नहीं किया जा रहा है-भले ही आयात शुल्क मुक्त या शुल्क प्रदत्त श्रेणी के अंतर्गत सूचित किए जा रहे हों ।
- विचाराधीन उत्पाद हेतु कच्ची सामग्री की कीमत में घट-बढ़ हो रही है और तदनुसार घरेलू उद्योग तथा विदेशी उत्पादकों की उत्पादन लागत में भी घट-बढ़ हो रही है । तथापि, प्राधिकारी ने 5 वर्ष के लिए एक बैंचमार्क निर्धारित किया है । इस प्रकार घरेलू उद्योग को उस स्थिति में एक बैंचमार्क के साथ सुरक्षा प्रदान की गई है जिसमें कच्ची सामग्री की कीमत में काफी अधिक घट-बढ़ हुई है । उत्पाद की कीमतें सीधी निविष्टि की कीमतों और आयात कीमतों द्वारा शासित होती हैं । कीमतों को तय करने के लिए ये दो बड़े कारक हैं । तथापि, बैंचमार्क कीमत को ध्यान में रखते हुए विदेशी उत्पादक लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद सामग्री का पाटन करने में सफल हैं । वर्तमान मामले की जांच अवधि के बाद कच्ची सामग्री की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हो चुकी है ।
- यह तर्क दिया जा सकता है कि घरेलू उद्योग लागू पाटनरोधी शुल्क की मध्यावधि समीक्षा की मांग कर सकता है । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि समीक्षा की मांग उस स्थिति में की जा सकती है जब कच्ची सामग्री की कीमत में अत्यधिक वृद्धि हुई हो । यह ऐसी स्थिति नहीं है जहां कच्ची सामग्री की कीमत दोगुनी या तिगुनी हो गई हों । यह ऐसी स्थिति है जहां कच्ची सामग्री की कीमत अल्पावधि में घट-बढ़ रही है । इस प्रकार समीक्षा से भी घरेलू उद्योग की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकेगा । शुल्क के स्वरूप में परिवर्तन से ही घरेलू उद्योग की समस्याओं का समाधान हो सकता है ।
- पाटनरोधी विधान डब्ल्यू टी ओ पाटनरोधी करार के अनुरूप और उससे सुसंगत तैयार किया गया है जिसमें प्राधिकारियों को अनुरोध किए गए प्रपत्र में और ढंग से पाटनरोधी शुल्क लागू करने की स्पष्ट अनुमति है ।
- कई जांचों (15 से अधिक वर्षों में अब तक 300 से अधिक जांचें की गई हैं) से प्राप्त अनुभव यह रहा है कि लगाए गए पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन के प्रयास किए जाते हैं । इस संबंध में पाटनरोधी शुल्क के अपवंचन के बारे में कई वर्षों से कई उद्योगों द्वारा की गई कई शिकायतें संगत हैं । प्राधिकारी को शुल्क के ऐसे स्वरूप की सिफारिश नहीं करनी चाहिए जिससे पाटनरोधी शुल्क के

अपवंचन को बढ़ावा मिलता हो और उसे शुल्क के ऐसे स्वरूप की सिफारिश करनी चाहिए जिसका न्यूनतम दुरुपयोग/कुप्रयोग किया हो सके ।

- vi. विश्व भर के पाटनरोधी शुल्क संबंधी विधान का उद्देश्य अनुचित व्यापार व्यवहारों से घरेलू उद्योग की सुरक्षा करना है । जिस प्रयोजन के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया जाता है वह प्रयोजन शुल्क के वर्तमान स्वरूप से निष्फल हो रहा है । शुल्क उस ढंग से लगाया जाना चाहिए जिससे कि वह निरर्थक न हो जाए ।
- vii. कुछ मामलों में सेस्टेट के आदेश का भी हवाला दिया गया है :-

- कोरिया से एन बी आर के मामले में माननीय सेस्टेट ने प्राधिकारी द्वारा संस्तुत परिवर्तनीय पाटनरोधी शुल्क को संशोधित कर निर्धारित शुल्क कर दिया ।
- मैटको के मामले में सेस्टेट ने निर्णय 2000 (116) ई एल टी 67 के तहत पाटनरोधी शुल्क को परिवर्तनीय से संशोधित कर निर्धारित स्वरूप में किया ।
- विट्रीफाइड टायलों के मामले में सेस्टेट ने शुल्क की निर्धारित मात्रा लागू किए जाने के बारे में प्राधिकारी के निर्णय को बरकरार रखा ।

- अम.डा. में शुल्क: निम्नलिखित कारणों से शुल्क केवल अम.डॉ. के रूप में लागू किया जाना चाहिए :-

क. प्राधिकारी द्वारा कई अन्य जांचों में अम.डॉ. के रूप में पाटनरोधी शुल्क लागू किया जा चुका है । रूपए में भारी अवमूल्यन हुआ है इसलिए निश्चयात्मक शुल्क कृपया अम.डा. में व्यक्त किया जाए । इसे चीन सवे मैटको के मामले में सेस्टेट के मामले में शामिल तर्काधार द्वारा भी समर्थन मिलता है । यदि पाटनरोधी शुल्क को अम.डा. (भा. रू. से) में परिवर्तन करने का आधार अम.डा. की मजबूती रहा है और वह भी अपीलीय चरण पर तो उस आधार को भा.रू. में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का आधार नहीं बनाया जा सकता ।

ख. घरेलू उद्योग की निविष्टि लागत परिवर्तन दर में वृद्धि द्वारा सीधे प्रभावित होती है । प्रथमतः घरेलू उद्योग ने कच्ची सामग्री का आयात किया है और इसलिए विनिमय दर का प्रभाव सीधे निविष्टि लागत पर महसूस किया जाता है । द्वितीयतः घरेलू रूप से खरीदी गई निविष्टियां भी अम.डॉ. की मजबूती द्वारा प्रभावित होती हैं क्योंकि उन निविष्टियों की लागत पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अम.डॉ. की मजबूती का प्रभाव पड़ता है । अतः यदि घरेलू उद्योग की लागत संरचना अम.डॉ. की मजबूती से प्रभावित होती है तो अम.डा. रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करना आवश्यक है ।

ग. प्राधिकारी ने पिछले दो वर्षों में लगभग सभी मामलों में अम.डा. के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश की है । ऐसा मामला होने के कारण ऐसा कोई कारण नहीं है कि वर्तमान मामले में अम.डॉ. में शुल्क क्यों लागू नहीं किया जाना चाहिए ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

9. हितवद्ध पक्षकारों के अनुरोधों की निम्नानुसार और इस जांच परिणाम के संगत खंडों में जांच की गई है :-

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि याचिकाकर्ता ने अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया है, यहां तक कि मात्रात्मक सूचना भी गोपनीय आधार पर प्रदान की गई है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह कहना सही नहीं है कि मात्रात्मक मापदंडों का अनिवार्यतः प्रकटन किया जाना चाहिए भले ही किए गए दावे का गुण-दोष कुछ भी हो। आगे यह नोट किया जाता है कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि ए डी एल द्वारा किए गए आयातों के कारण याचिकाकर्ता ने सूचना छिपाई है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. आरती ड्रग्स ने सरकार की विभिन्न शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया था और मै. आरती ड्रग्स लि. को शामिल किए जाने/बाहर किए जाने के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर भी विचार करते हुए मै. आरती ड्रग्स लि. को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से बाहर रखने का निर्णय लिया है। इसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की एकमात्र शेष उत्पादक होने के कारण मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज घरेलू उद्योग है और इस प्रकार वह पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करती है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि मै. यूनीकैम का उत्पादन आरती उत्पादन का 29.36 प्रतिशत बनता है और यह कि यूनीकैम एक लघु उत्पादक है और क्षति अवधि के दौरान उसके खुद का उत्पादन भारतीय उत्पादन के 25 प्रतिशत से कम रहा होगा और इसलिए यूनीकैम के आंकड़ों पर आधारित क्षति निर्धारण से तथ्यपरक विश्लेषण और उचित निर्धारण नहीं होगा; प्राधिकारी नोट करते हैं कि यह पाटनरोधी नियमों की सही समझ पर आधारित है। पाटनरोधी नियमों में अन्य बातों के साथ-साथ यह अपेक्षित है कि क्षति की जांच और मूल्यांकन घरेलू उद्योग के संबंध में करनी अपेक्षित होती है और पाटनरोधी नियमों में घरेलू उद्योग के क्षेत्र को और आगे परिभाषित किया गया है जिसका तात्पर्य मै. आरती ड्रग्स लि. को बाहर रखे जाने के बाद यह निकलेगा कि मै. यूनीकैम भारत में संबद्ध वस्तु का एकमात्र शेष उत्पादक है और इस प्रकार उसे सही ढंग से घरेलू उद्योग माना गया है।
- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग के आंकड़ों के आधार पर क्षति रहित कीमत का निर्धारण नहीं किया है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने घरेलू उद्योग के सत्यापित आंकड़ों के आधार पर और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार क्षति रहित कीमत निर्धारित की है और तदनुसार क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए पाटित आयातों के कारण हुई क्षति के अलावा, घरेलू उद्योग को हुई क्षति के कारणों का विश्लेषण करना भी अपेक्षित है। इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्द्र सरकार ने 4.8.2008 से संबद्ध वस्तु की अधिकतम बिक्री कीमत 526 रूपए प्रति किग्रा. अधिसूचित की है। इसका वस्तुतः यह

तात्पर्य है कि भारत में कोई भी संबद्ध वस्तु की बिक्री इससे अधिक कीमत पर नहीं कर सकता भले ही उनकी वास्तविक उत्पादन लागत/बिक्री लागत कुछ भी हो। अतः प्राधिकारी नोट करते हैं कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति डी पी सी ओ अधिसूचित कीमत तक ही हो सकती है और तदनुसार, उसने क्षति मार्जिन निर्धारित किया है। अतः घरेलू उद्योग का यह तर्क निराधार है कि प्राधिकारी को केवल क्षति रहित कीमत के आधार पर क्षति मार्जिन का निर्धारण करना चाहिए और डी पी सी ओ कीमत की अनदेखी करनी चाहिए। डी पी सी ओ कीमत वह आन्तरिकतम कीमत है जिससे अधिक कीमत पर उत्पाद की बिक्री नहीं की जा सकती और इस प्रकार डी पी सी ओ कीमत से कम कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करने में किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है और इसलिए ऐसी स्थिति में प्राधिकारी क्षति के निर्धारण हेतु आधार के रूप में केवल क्षति रहित कीमत पर विचार करेंगे क्योंकि यह डी पी सी ओ कीमत से कम है।

- जहां तक इस तर्क का संबंध है कि क्षति निर्धारण वर्तमान डी पी सी ओ कीमत पर आधारित हो; प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच अवधि में प्रचलित डी पी सी ओ कीमत ही प्रासंगिक है क्योंकि प्राधिकारी के लिए जांच अवधि हेतु क्षति मार्जिन का निर्धारण करना अपेक्षित होता है।
- क्षमता उपयोग से संबंधित तर्क के बारे में प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग अपने संयंत्र में संबद्ध वस्तु का विनिर्माण करने के अलावा, उसका विनिर्माण उजरती कार्य आधार पर तीसरे पक्षकार के जरिए भी करवाता है। प्राधिकारी ने स्वयं विनिर्मित वस्तु तथा उजरती कार्य के जरिए उत्पादित वस्तु के लिए पृथक क्षतिरहित कीमत निर्धारित की है और तत्पश्चात क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु औसत क्षति रहित कीमत पर विचार किया है। क्षति रहित कीमत की गणना पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-III में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर की गई है।
- जहां तक परिकलित सामान्य मूल्य और पाटन मार्जिन के पुनः निर्धारण से जुड़े तर्क का संबंध है; प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने घरेलू उद्योग द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन किया है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि मै. आरती इगर्स लि. ने आवेदन के भाग के रूप में सूचना/आंकड़े दायर किए थे और उन पर विचार किया गया है क्योंकि मै. आरती इगर्स लि. अधिक कुशल घरेलू उत्पादक है। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि उचित आधार पर सामान्य मूल्य का परिकलन करना अपेक्षित होता है और इसलिए उसने रिकॉर्ड में उपलब्ध सर्वोत्तम सूचना पर विचार किया है।

घ. हितवद्ध पक्षकारों के विविध अनुरोध और उनकी जांच

मै. हुबेई हांगगुआन फार्मास्यूटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण.,

10. मै. हुबेई हांगगुआन फार्मास्यूटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण. ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

- कि घरेलू उद्योग ने काफी देर से अनुरोध (अगोपनीय) किए हैं और सूचना समय पर प्रदान कर अन्य हितवद्ध पक्षकारों को अंधेरे में नहीं रखा है। घरेलू उद्योग द्वारा दायर अनुरोध

का अगोपनीय रूपांतरण व्यापार सूचना सं. 01/2012, दिनांक 09.01.2012 और प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं है। घरेलू उद्योग ने हितबद्ध पक्षकारों को समय पर उपर्युक्त अनुरोध का अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध नहीं कराया है। अनुरोधों का ऐसा अगोपनीय रूपांतरण निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजते समय अन्य भागीदार सभी हितबद्ध पक्षकारों को साथ-साथ भेजा जाना चाहिए था।

- आवेदक उद्योग ने क्षमता, उत्पादन मात्रा, क्षमता उपयोग, उजरती कार्य पर उत्पादन, घरेलू बिक्री मात्रा, निर्यात बिक्री मात्रा और आबद्ध मात्रा जैसे कोई कारण न देकर पर्याप्त सूचना को गोपनीय रखा है। आवेदक उद्योग ने गोपनीयता के बारे में मात्र ये कारण बताए हैं कि यूनीकैम लेबोरेटरी के एम टी जैड से संबंधित आर्थिक मापदंडों के बारे में कोई सूचना सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है और कंपनी के उपभोक्ताओं को कंपनी की क्षमता के बारे में जानकारी नहीं है और यह कि कंपनी ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस सूचना का प्रकटन नहीं किया है। इस संबंध में चीन से लौह या इस्पात के कुछेक फास्नरों पर यूरोपीय समुदाय-पाटनरोधी उपय में अपीलित निकाय की रिपोर्ट (डब्ल्यू टी/डी एस 397/ ए बी/आर, दिनांक 15 जुलाई, 2011) का हवाला दिया है।

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

11. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- विलंबित अनुरोध - हुबेई ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने अनुरोध काफी विलंब से किए हैं। अनुरोध है कि इस मामले में घटनाक्रम निम्नानुसार है:

क. यूनीकैम और आरती ड्रग्स द्वारा संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की गई थी जिसमें आरती ड्रग्स ने कंपनी द्वारा किए गए आयातों के बावजूद घरेलू उद्योग के रूप में शामिल होने की दलील दी थी।

ख. जांच शुरुआत संबंधी सूचना का उत्तर देते समय हितबद्ध पक्षकारों (मुख्यतः हुबेई) ने यह अनुरोध किए कि आरती ड्रग्स को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए।

ग. सुनवाई के समय घरेलू उद्योग ने अपने इस दावे को दोहराया कि आरती को घरेलू उद्योग माना जाना चाहिए। घरेलू उद्योग ने अपने लिखित और उत्तर संबंधी अनुरोधों में इस दावे को दोहराया है।

घ. हुबेई ने सुनवाई के समय यह तर्क दिया है कि आरती ड्रग्स को घरेलू उद्योग नहीं माना जाना चाहिए। हुबेई ने लिखित अनुरोधों में अपने दावे को दोहराया है।

ड नियमों में कार्यवाही के अगले चरण से पूर्व अर्थात् प्रकटन विवरण के चरण पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा किसी निर्णय का प्रावधान नहीं है ।

च निर्दिष्ट प्राधिकारी के निर्धारित प्रपत्र में "घरेलू उद्योग को क्षति" के बारे में सूचना अपेक्षित होती है । इसका स्पष्ट तात्पर्य "समग्र घरेलू उद्योग" से है ।

छ. निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यूनीकैम के बारे में सत्यापन किया परंतु आरती ड्रग्स की सूचना का सत्यापन नहीं किया ।

ज. यह मामला 30 मई, 2011 को शुरू किया गया था और अंतिम जांच परिणाम 29 मई, 2012 को जारी किए जाने हैं ।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और अपनाए जा रहे नियमों तथा प्रक्रियाओं के मद्देनजर घरेलू उद्योग विधिक दायित्व न होने के बावजूद स्वयं केवल यूनीकैम के बारे में क्षति का विवरण प्रदान करता है ।

कानून के अंतर्गत प्राधिकारी को यह निर्णय लेना होता है कि क्या किसी कंपनी को घरेलू उद्योग के दायरे में शामिल किया जाए या उसे अलग रखा जाए । इसके अलावा, यदि प्राधिकारी आरती ड्रग्स को बाहर रखने का निर्णय लेते हैं तो परिणाम निम्नानुसार होंगे ।

उपर्युक्त स्थिति की तुलना ऐसी स्थिति से की जा सकती है जिसमें कई घरेलू उत्पादक प्राधिकारी के समक्ष आते हैं और अलग-अलग काउंसिलों के जरिए प्राधिकारी को सूचना प्रदान करते हैं । कुछ सीधे भी सूचना दायर कर सकते हैं । घरेलू उत्पादकों के बीच विरोधाभासी व्यापारिक हित से भी ऐसा घरेलू उत्पादक समेकित सूचना दायर करने से वंचित हो सकता है । यदि ऐसा होता है तो इसका तात्पर्य यह है कि कानून ऐसे घरेलू उद्योग को केवल इस वजह से संरक्षण प्रदान नहीं करेगा कि उसने समेकित क्षति विवरण दायर नहीं किया है । ऐसी कठिनाइयों को समझते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी पर वस्तुतः यह दायित्व डाला गया है कि वह निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अंतिम निर्णय लिए जाने से पूर्व निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन सभी आवश्यक तथ्यों का प्रकटन सभी हितबद्ध पक्षकारों को करे । इसके अलावा, नियमों में टिपणियों के लिए अवसर का भी प्रावधान है । निर्विवाद रूप से यह ऐसा मामला नहीं है कि इस मामले में प्रकटन विवरण जारी होने की निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए विलंबित अवसर के बारे में दिए गए तर्क में कोई दम नहीं है ।

- जहां तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों को अनुरोधों के परिचालन का संबंध है, सच्चाई यह है कि उन्होंने स्वयं घरेलू उद्योग को अपने अनुरोध नहीं भेजे हैं। वस्तुतः निर्यातक को कार्यवाही के दौरान कई अनुरोध दायर करने होते हैं। सुनवाई के बाद लिखित अनुरोधों को छोड़कर हुबेई ने कोई भी अनुरोध घरेलू उद्योग को नहीं भेजा है। कोई हितबद्ध पक्षकार उस स्थिति में ऐसे अननुपालन के खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता जब ऐसे हितबद्ध पक्षकार ने स्वयं ऐसी अपेक्षा का पालन न किया हो।

इस तथ्य के होते हुए भी कि प्राधिकारी ने सार्वजनिक फाइल के जरिए हमारे अनुरोधों के प्रति हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराई है और ऐसे अवसर से स्पष्ट तौर पर यह सिद्ध होता है कि कानून के अंतर्गत विधिक अपेक्षाओं का विधिवत पालन किया गया है। यह उल्लेख करना संगत नहीं है कि कानून के अंतर्गत एकमात्र विधिक अपेक्षा यह है कि प्राधिकारी को एक हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य जांच में भागीदार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने चाहिए। ऐसा साक्ष्य किसी भी ढंग से अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराया जा सकता है और जब तक अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसा साक्ष्य उपलब्ध कराया जाता है तो शिकायत का प्रश्न नहीं उठता है।

- **गोपनीयता** - निर्यातक ने घरेलू उद्योग द्वारा किए गए गोपनीयता के दावे पर आपत्ति की है। घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि -

(क) केवल ऐसी सूचना के बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है जिसकी गोपनीयता नियमों के अंतर्गत अनुमत है।

(ख) गोपनीयता का दावा करने के लिए घरेलू उद्योग ने पर्याप्त कारण दिए हैं। यदि आगे और कारणों/औचित्य की जरूरत हो तो हमें निर्देश दिया जाए।

(ग) निर्दिष्ट प्राधिकारी ने पिछले कई अवसरों पर ऐसी सूचना गोपनीय मानी है। निर्दिष्ट प्राधिकारी का ध्यान मार्फोलिन के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच के अंतिम जांच परिणामों की ओर आकर्षित किया जाता है जिसमें ऐसी सभी समान सूचना को गोपनीय माना गया था जिसकी अनुमति प्राधिकारी ने दी थी।

(घ) अनुरोध है कि कंपनी ने ऐसी सूचना का सार्वजनिक रूप से प्रकटन नहीं किया है। वार्षिक रिपोर्ट का भी हवाला दिया जाता है जिसमें ऐसी सूचना वार्षिक रिपोर्ट में अलग से उपलब्ध नहीं है।

(ङ) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग जैसी सूचना वस्तुतः गोपनीय है। यहां तक कि अन्य घरेलू उत्पादकों के पास भी यूनीकैम से संबंधित इन मापदंडों के बारे में सटीक सूचना उपलब्ध नहीं है। इस उत्पाद का वैश्विक रूप से अत्यंत सीमित उत्पादन होने के कारण इस सूचना के प्रकटन से ऐसी कंपनी के व्यापारिक हितों का अत्यधिक नुकसान हो सकता है जो घरेलू और विश्व बाजार में अन्य घरेलू तथा चीन के उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा कर रही है।

(च) जहां तक कंपनी अधिनियम की अनुसूची IV के अंतर्गत अपेक्षा का संबंध है, अनुरोध है कि इसका दूसरे सरकारी प्राधिकारण से सरोकार है। जहां तक निर्दिष्ट प्राधिकारी का संबंध है, केवल एकमात्र विधिक अपेक्षा यह हो सकती है कि क्या ऐसी सूचना का प्रकटन

वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है। कुछेक समान सांविधिक अपेक्षाओं के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट में ऐसे प्रकटनों की पर्याप्तता वर्तमान जांच की विषय वस्तु नहीं है और न ही हो सकती है। तथापि, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी कोई स्पष्टीकरण चाहते हैं तो कंपनी को निर्देश दिया जाए।

(छ) जहां तक यूरोपीय समुदाय - चीन से कुछेक लौह या इस्पात के फासलों पर पाटनरोधी उपायों के मामले में अपीलीय निकाय के निर्णय (डी एस 397/ए बी/बी, दिनांक 15 जुलाई, 2011) का संबंध है, हमारा अनुरोध है कि प्राधिकारी के लिए गोपनीयता का दावा करने हेतु कारणों पर विचार करना अपेक्षित होता है। अनुरोध है कि रिपोर्ट का हवाला देना नितांत निराधार है। वस्तुतः डब्ल्यू टी ओ अपीलीय निकाय ने इस बात पर विचार किया है और स्वीकार किया है कि जांच प्राधिकारी गोपनीयता की अनुमति देने में न्यायोचित है।

(ज) जहां तक प्रतिरक्षा के अधिकार का संबंध है, प्राधिकारी के लिए कई आर्थिक मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार कर घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच करना अपेक्षित होता है। प्राधिकारी द्वारा निर्धारण विभिन्न आर्थिक मापदंडों में प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रवृत्तियों के आधार पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण करते हैं तो समग्र संख्याओं की प्रासंगिकता को किसी भी हालत में नहीं समझा जा सकता।

प्राधिकारी द्वारा जांच

12. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया है और उन पर निम्नानुसार तथा इस दस्तावेज के संगत खंडों में विचार किया गया है:

- जहां तक विलंब के मुद्दों का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि वह जांच की कार्रवाई के दौरान विभिन्न चरणों पर हितबद्ध पक्षकारों से अनुरोध प्राप्त करते हैं और उनका गोपनीय रूपांतरण पाटनरोधी नियमों के अनुसार रखी गई सार्वजनिक फाइल में विधिवत रखा जाता है। यह सार्वजनिक फाइल हितबद्ध पक्षकारों के निरीक्षण हेतु हमेशा उपलब्ध रहती है जैसा कि वर्तमान मामले में भी किया गया है।
- प्राधिकारी नोट करते हैं कि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रदत्त सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के बारे में की गई थी। संतुष्ट होने के बाद प्राधिकारी ने अपेक्षानुसार, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना गोपनीय मानी गई है जिसका प्रकटन अन्य हितबद्ध पक्षकारों को नहीं किया गया है। जहां संभव हुआ है, गोपनीय आधार पर सूचना प्रदाता पक्षकारों को निर्देश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर दायर सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतरण उपलब्ध कराएं।

ड विचाराधीन उत्पाद तथा समानवस्तु

13. मूल जांच में शामिल उत्पाद "मैट्रोनिडाजोल" था। चूंकि यह निर्णायक समीक्षा है इसलिए इस जांच में मूल जांच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में शामिल उत्पाद शामिल है।

मैट्रोनिडाजोल डायरियारोधी तथा सूक्ष्म जीवाणुरोधी औषधि है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा के बाद शल्य चिकित्साजनित संक्रमण जियाडियासिस, तीव्र अल्सरेटिव एवं जिजीवाइटिस, एनीरोबिक, एनीरोबिक माइक्रोफार्मेशन द्वारा हुए संक्रमण के वैजाइनोसिस उपचार के मामलों में किया जाता है। यह उक्त सीमाशुल्कटैरिफ अधिनियम तथा आई टी सी एच एस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के शीर्ष सं. 29332920 के अंतर्गत आने वाला एक अकार्बनिक रसायन है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी रूप में बाध्यकारी नहीं है।

14. घरेलू उद्योग भी उस मैट्रोनिडाजोल का उत्पादन करता है जिसमें मिलती-जुलती विशेषताएं और विनिर्देशन होते हैं। विचाराधीन उत्पाद या समान वस्तु के मुद्दे पर किसी हितबद्ध पक्षकार ने कोई तर्क नहीं दिया है इसलिए प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद पाटनरोधी नियमावली के अनुसार विचाराधीन उत्पाद के "समान वस्तु" है।

घरेलू उद्योग का क्षेत्र

मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि., चीन जन.गण. की ओर से किए गए अनुरोध

15. मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि., ने संक्षेप में निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

- घरेलू उद्योग ने इस बात का झूठा उल्लेख किया है कि याचिकाकर्ता भारत में संबद्ध वस्तु के एकमात्र उत्पादक हैं क्योंकि मै. जे डी कैमिकल्स भी भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादक है।
- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार याचिका में ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के नाम और पते दिए जाने चाहिए। इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने याचिका में हितबद्ध पक्षकारों की अधूरी सूची प्रस्तुत की थी जैसा कि इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि संभावना के मापदंडों हेतु लिए गए निर्यातक के नाम ज्ञात निर्यातकों की सूची में नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि सूचना को शुनिन्दा ढंग से इस प्रकार की महत्वपूर्ण सूचना को प्राधिकारी को भ्रमित करने की मंशा से छिपाया गया है।
- मै. आरती ड्रग्स लि. ने न केवल अग्रिम लाइसेंस पर चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु का आयात किया है, अपितु बाजार आसूचना के आधार पर जांच अवधि के दौरान शुल्क का भुगतान करने के बाद पर्याप्त मात्रा में विचाराधीन उत्पाद का आयात भी किया है। इन आयातों पर विचार करते हुए मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका तथा यूरोपीय संघ के मूल के या वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों के बारे में पाटनरोधी (मध्यावधि समीक्षा) जांच तथा अमरीका, कोरिया गण. एवं ताइवान के मूल के या वहां से निर्यातित फेनोल के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच के मामले में प्राधिकारी के जांच परिणामों का हवाला दिया गया है। यदि मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग

के भाग के रूप में शामिल किया जाता है तो घरेलू उद्योग को हुई कोई क्षति केवल स्वतः स्फूर्त होती जिसे कोई पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता ।

- मै. आरती ड्रग्स लि. ने निर्यातक/आयातक के साथ याचिकाकर्ता के संबंध तथा ए डी एल को घरेलू उद्योग मानने के लिए उसके द्वारा किए गए आयातों से संबंधित औचित्य के बारे में गलत तर्क प्रस्तुत किए हैं क्योंकि उसने न केवल जांच अवधि के दौरान अपितु वर्ष 2000 से संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया है । इसके अलावा, यह मै. सुयश लेबोरेटरीज लि., की एक सहायक कंपनी है जो चीन जन.गण. से संबद्ध वस्तु की आयातक भी है । अतः मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखा जाना चाहिए ।
- याचिकाकर्ताओं ने इस बात का गलत दावा किया है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति में मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयातों के कारण विकृति नहीं आई है क्योंकि आयातों के कारण घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग कम रहा होगा और घरेलू उद्योग की लागत में परिवर्तन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप वृद्धि हुई होगी और मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयातों के कारण उत्पादन में गिरावट आई होगी । इसे अलावा, देश की कुल मांग में निर्यात के प्रयोजन हेतु खपत शामिल होती है और इसलिए क्या आयात चाहे अनुषंगी उत्पाद के लिए किए गए हों अथवा नहीं, का कोई अंतर नहीं पड़ता है ।
- मै. आरती ड्रग्स लि. की चीन जन.गण. में एक संबद्ध कंपनी है और उसकी भारत में भी एक सहायक कंपनी है जो संबद्ध वस्तु की आयातक है ।
- आवेदकों द्वारा दायर आवेदन में विरोधाभासी तर्क दिए गए हैं और एक पर जोर दिया गया है जो अधिक लाभदायक है । इसके अलावा, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने क्षति के दावे के लिए चुनिन्दा आंकड़ों को लेने का विकल्प अपनाया है । क्षति दर्शाने के लिए उसने दावा किया है कि घरेलू उद्योग संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण अपनी क्षमता का कम उपयोग कर रहा है और वह उत्पादन बढ़ाने में समर्थ नहीं है जबकि घरेलू उद्योग को परिभाषित करते समय यह उल्लेख किया गया है कि मै. ए डी एल द्वारा संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए अपनी संयंत्र क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इसलिए वह अनुषंगी उत्पाद के लिए संबद्ध वस्तु का आयात कर रही है । दोनों विवरण विरोधाभासी हैं ।
- अपर्याप्त और अपूर्ण याचिका : याचिकाकर्ता डी जी ए डी के निर्धारित प्रपत्र के अनुसार क्षति की सूचना प्रस्तुत करने में विफल रहे हैं । प्रपत्र- IV क में

याचिकाकर्ताओं ने स्थापित क्षमता का उल्लेख किया है जबकि याचिका में उन्होंने प्रभावी क्षमता का उल्लेख किया है। इस विरोधाभासी विवरण पर विचार करते हुए स्थापित क्षमता हेतु प्रपत्र-IV क का सत्यापन जरूरी है और प्रभावी क्षमता के बारे में किसी सूचना को केवल अतिरिक्त सूचना माना जाए। इसके अलावा, क्षमता उपयोग प्रपत्र-IV क में उल्लिखित क्षमता पर आधारित नहीं हैं जिससे क्षमता उपयोग ही गलत हो गया है। कुछ विरोधाभास प्रपत्र-IV क में दिए गए शुरुआती और अंतिम स्टॉक के आंकड़ों के संबंध में भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा, प्रपत्र IV क में वृद्धि की गणना भी सही नहीं है क्योंकि उसने मूल्य वर्ग में चालू वर्ष के आंकड़े लिए हैं। अतः याचिकाकर्ताओं ने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में प्राधिकारी को भ्रमित किया है जिसका क्षति मापदंडों पर प्रभाव पड़ सकता है। प्राधिकारी को अगोपनीय प्रपत्र IV-क को संशोधित कर सही सूचना देने और उसकी एक प्रति हमारी टिप्पणियों के लिए हमें उपलब्ध कराने की घरेलू उद्योग को सलाह देनी चाहिए।

- यह तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उद्योग शुल्क के स्वरूप से संतुष्ट नहीं था तो वह निर्णायक समीक्षा का इंतजार करने के बजाए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क के प्रावधान के अनुसार इसके विरुद्ध मांग कर सकता था। घरेलू उद्योग ने इस बारे में कोई औचित्य नहीं दिया है कि वह सतत क्षति यदि कोई हो और शुल्क के स्वरूप के बारे में पिछले पांच वर्ष से मौन क्यों था जब वह इस संबंध में कानून में प्रदत्त संरक्षण के उपायों का सहारा ले सकता था।
- निर्यात प्रयोजनों के लिए किए गए सभी आयातों और ए डी एल तथा सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी आयातों को क्षति के प्रयोजनार्थ अलग रखा जाना चाहिए क्योंकि उनका घरेलू उद्योग की क्षति के बारे में कोई योगदान नहीं हो सकता है।
- संबद्ध वस्तु के अधिकांश आयात लगभग 80% अग्रिम लाइसेंस पर हुए हैं और ए डी एल तथा जे बी कैमिकल्स भारत में संबद्ध वस्तु के प्रमुख आयातक हैं और वे भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादकों के दर्जे का भी दावा करते हैं। अग्रिम लाइसेंस के अंतर्गत किए गए सभी आयातों और ए डी एल तथा उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए आयातों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति के विश्लेषण हेतु अलग रखा जाना चाहिए। इसी तर्काधार पर शुल्कमुक्त आयातों को क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ अलग रखा जाना चाहिए।
- गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जी पी सी बी) द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों के कारण जांच अवधि के दौरान मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र लगभग 4-5 माह बंद रहा था और इसके परिणामस्वरूप जांच अवधि के दौरान आयातों में वृद्धि हुई होगी क्योंकि उपभोक्ताओं के पास आयात करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था क्योंकि संबद्ध वस्तु औषध की श्रेणी में आती है। अतः इसकी अनुपलब्धता की वजह से आयात आवश्यक बन गए थे और मै. आरती ड्रग्स लि. संबद्ध वस्तु की प्रमुख

उत्पादक है और वह मै. यूनीकैम के लिए उजरती कार्य भी करती है इसलिए मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र बंद होने से आयातों में वृद्धि हुई है ।

- याचिकाकर्ताओं ने क्षमता उपयोग की गणना हेतु प्रपत्र IV क में प्रभावी क्षमता ली है । यह क्षमता जांच अवधि के दौरान गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण संयंत्र बंद होने की वजह से आधार वर्ष की तुलना में 14-18 मी.ट. से घटकर 899 मी.ट. हो गई है । अतः पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बल्कि अन्य कारक जो गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाया गया प्रतिबंध है, का प्रभाव पड़ा है ।
- क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है । उत्पादन में गिरावट गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र बंद होने की वजह से आई है और याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा संबद्ध वस्तु की मांग को पूरा करने के लिए अपने संयंत्र की क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इसलिए वह अनुषंगी उत्पाद हेतु संबद्ध वस्तु का आयात कर रही है । तथापि, क्षमता उपयोग जांच अवधि में 77% से बढ़कर 92% हुआ है । अतः आयातों के कारण घरेलू उद्योग के उत्पादन और क्षमता उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।
- ईष्टतम उपयोग का लाभ उठाने के लिए घरेलू उद्योग ने प्रभावी क्षमता उपयोग लिया है । क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु नियमों (अनुबंध-III) में यह उल्लेख है कि प्राधिकारी को उच्चतर शुल्क हेतु क्षति अवधि के दौरान ईष्टतम क्षमता उपयोग लेना होगा और उसने ऐसा किया है ।
- यदि प्राधिकारी क्षति रहित कीमत के निर्धारण हेतु प्रभावी क्षमता उपयोग लेते हैं तो जिस अवधि में संयंत्र बंद रहे हैं उस अवधि के व्यय को लागत से अलग रखा जाना चाहिए और उसका उपयोग क्षति विश्लेषण हेतु भी किया जाना चाहिए ।
- घरेलू उद्योग वर्ष 2000-01 से घाटे में था और घरेलू उद्योग का घाटा 2007-08 में 100 से बढ़कर जांच अवधि में 220 हो गया जब घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत क्षति अवधि के दौरान संदर्भ कीमत से अधिक थी । तथापि, निर्णायक समीक्षा के मामले में संदर्भ कीमत शुल्क की गणना क्षति रहित कीमत के आधार पर की गई थी । इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग के निष्पादन में अक्षमताओं के कारण सुधार नहीं हुआ है ।
- घरेलू उद्योग 2 एम एन आई की लागत के कारण घाटे में चल रहा था जिसकी लागत अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में अधिक है । इसके अलावा, घरेलू उद्योग की

लागत में वृद्धि परिवर्तन लागत में वृद्धि के परिणामस्वरूप और मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र बंद होने के कारण उत्पादन में आई गिरावट के कारण हुई है जिसे घरेलू उद्योग ने याचिका में स्वीकार किया है और यह कि आंशिक क्षति परिवर्तन लागत के कारण हुई है । अतः परिवर्तन लागत में वृद्धि पर क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ विचार नहीं किया जाना चाहिए जो अन्य कारक (संयंत्र का बंद होना) की वजह से हुई है । अन्य कारक पर विचार करने के बाद घरेलू उद्योग को उचित लाभ से अधिक लाभ मिला होगा । अतः इन कारकों में गिरावट, यदि कोई हो, की वजह आरोपित पाटित आयातों को नहीं माना जा सकता । अतः हमारा अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को क्षति 2 एम एन आई लागत और परिवर्तन लागत के कारण हुई है ।

- यह सच नहीं है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में प्रस्तावित जांच अवधि के दौरान बिक्री लागत में अत्यधिक वृद्धि आंशिक रूप से कच्ची सामग्री की लागत में वृद्धि और आंशिक रूप से परिवर्तन लागत में हुई वृद्धि के कारण हुई है क्योंकि दो एम एन आई की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 2009-10 में 182.05 रुपए प्रति किग्रा. थी जो जांच अवधि में घटकर 181.84 रुपए प्रति किग्रा. हो गई है । वस्तुतः पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की लागत में गिरावट आनी चाहिए थी । इसका तात्पर्य यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कीमत की तुलना में घरेलू उद्योग की कच्ची सामग्री की लागत (2 एम एन आई) अधिक थी । अतः 2 एम एन आई की लागत और अन्य कारकों के कारण परिवर्तन लागत में हुई वृद्धि पर क्षति और क्षति रहित कीमत के प्रयोजनार्थ संबद्ध वस्तु की लागत की गणना करने के लिए विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता की लागत अक्षमताओं की वजह से अधिक है ।
- यह तर्क दिया गया है कि मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र बंद होने के लिए समायोजन न केवल क्षमता के संबंध में किए गए हैं, अपितु क्षति के सभी कारकों के संबंध में भी किए गए हैं । समायोजित करने के बाद विश्लेषण करना उचित होगा जिसका निष्पक्ष परिणाम मिलेगा । सभी आंकड़ों, खासकर बिक्री, मालसूची, मजदूरी, लागत, लाभप्रदता, पुनः शुरुआत संबंधी लागत, वास्तविक हानि आदि जैसी असामान्य लागत का समायोजन करना अपेक्षित है ।
- मालसूची का विश्लेषण भी अंतिम स्टॉक के संबंध में किया जाना चाहिए जिससे यह पता चलेगा कि मालसूची के बारे में कोई क्षति नहीं हुई है । यह भी अनुरोध किया जाता है कि 31.12.2009 की स्थिति के अनुसार संबद्ध वस्तु का अंतिम स्टॉक 133 मी.ट. था जबकि आंकड़ों को घटाकर 31.3.2010 की स्थिति के अनुसार 49 मी.ट. दर्शाया गया है । अतः मासिक स्टॉक की जांच की जानी चाहिए ।

- गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण संयंत्र बंद होने की वजह से जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जिसके परिणामस्वरूप आयात में वृद्धि हुई है। प्राधिकारी को इस बात पर विचार करना चाहिए कि संबद्ध वस्तु औषध की श्रेणी में आने के कारण उपभोक्ताओं के पास सामग्री का आयात करने के अलावा, कोई अन्य विकल्प नहीं था। अतः इसकी अनुपलब्धता की वजह से आयात आवश्यक हो जाते हैं और चूंकि मै. आरती ड्रग्स लि. संबद्ध वस्तु की एक प्रमुख उत्पादक है और वह मै. यूनीकैम के लिए भी उजरती कार्य करती है, इसलिए ए डी एल का संयंत्र बंद होने के कारण आयातों में वृद्धि हुई है।
- पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना: घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के लिए सूचना प्रदान की है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि संबद्ध देश से पाटन हुआ है। प्राधिकारी को पाटन मार्जिन की गणना करते समय सहयोगी उत्पादक और निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराए गए वास्तविक आंकड़ों पर ही विचार करना चाहिए।
- घरेलू उद्योग वर्तमान क्षति अथवा भावी क्षति की किसी संभावना का मामला बनाने में असहाय होते हुए विफल हुआ है। घरेलू उद्योग ने चीन जन.गण. में केवल अतिरिक्त क्षमताओं का उल्लेख किया है लेकिन अपने दावे के समर्थन में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है और न ही पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई क्षति जारी रहने तथा उसकी पुनरावृत्ति होने के दावे के संबंध में रिकॉर्ड में कोई साक्ष्य है।
- कारणात्मक संबंध: अनुरोध है कि घरेलू उद्योग ने मै. आरती ड्रग्स लि. और उसकी सहायक कंपनी द्वारा किए गए आयातों और मै. आरती ड्रग्स लि. का संयंत्र बंद होने के प्रभावों के बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया है। अतः हमारा अनुरोध है कि इन कारकों के लिए विश्लेषण भी किया जाए जिससे यह पता चलेगा कि घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, संबद्ध देश से आयातों के कारण नहीं हुई है अपितु उपर्युक्त अन्य कारकों की वजह से हुई है।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि घरेलू उद्योग को आयातों के कारण कोई क्षति नहीं हुई है और न ही घरेलू उद्योग क्षति की संभावना को सिद्ध करने में सफल रहा है इसलिए शुल्क की अवधि का विस्तार करने का कोई मामला नहीं बनाया गया है और इसलिए धारा 9 क (5) के अनुसार इसे समाप्त करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

16. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

- मैट्रोनिटाजोल का देश में एक से अधिक दशक से निरंतर पाटन किए जाने का लंबा इतिहास रहा है। प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने और निर्णायक समीक्षा जांच के बाद उसकी अवधि में आगे और वृद्धि किए जाने के बावजूद चीन जन.गण. से पाटित कीमत पर अत्यधिक मात्रा में लगातार आयात हुआ है।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
आयात मूल्य						
संबद्ध देश- चीन जन.गण	मी.ट.	522	506	740	1,133	1,049
अन्य देश	मी.ट.	12	26	28	-	92
कुल आयात	मी.ट.	535	532	769	1,133	1,141
चीन जन.गण. से आयात कीमत	रु./किग्रा	324.41	435.67	401.39	412.20	420.83

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि (वार्षिक)

- पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की प्रासंगिकता और प्रयोजन यह है कि घरेलू उद्योग को उचित कीमत पर अपनी सामग्री बेचने का बाजार में अधिक अवसर प्राप्त होता है। तथापि, वर्तमान मामले में पाटित आयात की मात्रा पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का बमशुक्ल कोई प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है।
- लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने का चीन जन.गण. से उत्पाद का और अधिक पाटन होना लाजिमी है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना है।
- लागू उपाय के स्वरूप से पूर्व में लगाया गया समूचा पाटनरोधी शुल्क एक निष्फल प्रक्रिया बन गया है। चीन के उत्पादक सामग्री का पाटन जारी रखने में समर्थ हैं और आयातित उत्पाद पर पाटनरोधी शुल्क लागू नहीं होता है। परिणामतः घरेलू उद्योग धीरे-धीरे संख्या की दृष्टि से कम हो रहा है।
- उत्पाद के ऐसे सतत/वृद्धिशील पाटित आयातों का तात्पर्य है कि:
 - (क) पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बावजूद क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से पाटित आयातों में वृद्धि हो रही है। यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो इस मात्रा में निश्चित तौर पर वृद्धि होगी, और
 - (ख) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क के स्वरूप में संशोधन कर उसे पाटनरोधी शुल्क की निर्धारित मात्रा में लागू करना अपेक्षित है।

- v. चीन जन.गण. मैट्रोनिडाजोल का एक प्रमुख निर्यातक है और वह कई देशों को उत्पाद का निर्यात कर रहा है और यह कि इन उत्पादकों के पास विचाराधीन उत्पाद की अत्यधिक निर्यात क्षमताएं हैं ।
- vi. आयात कीमत में माह दर माह आधार पर भारी वृद्धि हुई है और तत्पश्चात गिरावट आई है । यह देखा जाएगा कि :
- (क) मैट्रोनिडाजोल की कीमतें जो जून-सितंबर, 2008 के दौरान काफी अधिक थीं, वे अक्टूबर, 2008 में तेजी से घटकर 260 रूपए प्रति किग्रा. हो गईं और तत्पश्चात जनवरी, 2009 में वे 584 रूपए प्रति किग्रा. के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गईं ।
- (ख) तथापि, आयात कीमत में उसके बाद गिरावट आई जो नवंबर, 2009 जब आयात कीमत बढ़कर 529 रूपए प्रति किग्रा. हो गई, को छोड़कर, फरवरी, 2009 से दिसंबर, 2010 तक 400 रूपए प्रति किग्रा. बनी रही ।
- (ग) जहां वर्ष 2009-10 और जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की भारत औसत बिक्री लागत में *** रूपए प्रति किग्रा. की वृद्धि हुई है, वहीं आयातों की पहुंच कीमत में उसी अवधि के दौरान केवल 16 रूपए प्रति किग्रा. की वृद्धि हुई है । इससे यह पता चलता है कि आयात कीमतों में वृद्धि लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं हुई है । इसके अलावा, लागत में पर्याप्त वृद्धि के बावजूद इस अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में *** रूपए प्रति किग्रा. की गिरावट आई है ।
- vii. पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बाद भी आयातों की कीमत से घरेलू कीमत में भारी कटौती हो रही है । इस प्रकार पूर्ववर्ती जांच में प्राधिकारी द्वारा संस्तुत संदर्भ कीमत निष्प्रभावी हो गई है ।
- viii. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता-याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि आयातों का पहुंच मूल्य वह कीमत है जो घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है ।
- ix. यह स्पष्ट होता है कि चीन के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की वर्तमान और संभावित बिक्री कीमत से कम है । अतः चीन के उत्पादक शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार को आक्रामक रूप से लक्ष्य बनाएंगे । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में उचित कीमत वसूल किए जाने की स्थिति में चीन का उत्पाद और अधिक सस्ता होने की संभावना है ।
- x. याचिकाकर्ताओं ने यह पाया है कि उन्होंने आयातकों की सूची में मै. यूनीकैम लि. के नाम का असावधानीवश उल्लेख किया है । मै. यूनीकैम लि. संबद्ध उत्पाद की आयातक नहीं है ।
- xi. मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयातों की मात्रा का प्रकटन किया जा चुका है । आयातों की मात्रा के बारे में पूर्व में प्रदत्त सूचना की समीक्षा करने पर यह पाया गया है कि

आयातों की कहीं दोहरी गणना की गई है और जांच अवधि में आयात की वास्तविक मात्रा केवल *** मी.ट. है।

xii. मै. आरती ड्रग्स लि. के संबंध और अपात्रता का खुलासा प्राधिकारी को किया जा चुका है। जहां तक संबद्ध कंपनी द्वारा किए गए आयातों और निर्यातक के साथ संबंध का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रासंगिक है।

xiii. निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथापरिभाषित संबंध का अर्थ: सकुलर वीविंग मशीनों के आयातों के बारे में पाटनरोधी जांच के मामले में प्राधिकारी ने यह माना है कि एकमात्र घरेलू उत्पादक विदेशी उत्पादक द्वारा स्वीकृत 35% की शेयरधारित के बावजूद विदेशी उत्पादक से संबंधित नहीं है। अतः यह देखा जाएगा कि प्राधिकारी ने इस बात पर विचार किया है कि कोई पक्षकार तब संबंधित नहीं है जब उसकी 35% शेयरधारित हो। वर्तमान मामले में शेयरधारिता केवल ***% है। यह नहीं कहा जा सकता कि मै. आरती ड्रग्स लि. विदेशी उत्पादक से संबंधित है।

xiv. क्या इस मामले के तथ्यों से मै. आरती ड्रग्स लि. का अपवर्जन न्यायोचित बनता है.:

(क) मै. आरती ड्रग्स लि. उत्पादक की घरेलू विनिर्माता है। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि कंपनी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से यह निर्देश दिया गया था कि वह अपने उत्पादन को कुछ स्तर तक सीमित करे। उत्पादन पर इस प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए और अपने निर्यात हेतु सामग्री की जरूरत एवं अपने उपभोक्ता के लिए सामग्री की जरूरत पर विचार करते हुए अपने ग्राहकों को सामग्री प्रदान करने की जरूरत की दृष्टि से मै. आरती ड्रग्स लि. ने मैट्रोनिडाजोल के अपने निर्यातों का उपयोग कर सामग्री का आयात किया था।

(ख) मै. आरती ड्रग्स लि. की मै. सुयश लेबोरेटरीज लि. के नाम से एक संबद्ध कंपनी है। यह कंपनी इसलिए संबद्ध है क्योंकि इसके 3 साझा निदेशक हैं और इसने *** शेयरों में *** करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। यह कंपनी ए पी आई (एक्टिव फार्मास्युटीकल इन्ट्रीडिअंट) का विनिर्माण करती है। अंतर्ग्रस्त वित्तीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए मै. आरती ड्रग्स लि. ने कुछ सामग्री का आयात मै. सुयश के जरिए किया है। इन मामलों में सामग्री की व्यवस्था मै. सुयश ने की थी जिसकी बिक्री मै. आरती ड्रग्स लि. को उच्च समुद्री बिक्री आधार पर की गई थी। यह स्पष्ट किया जाता है कि मै. सुयश ने सामग्री की निकासी के लिए प्रबंध बिल दायर नहीं किया है।

(ग) मै. आरती ड्रग्स लि. ने मै. हुआंगगांग यिनहे आरती फार्मा कंपनी लिमिटेड (यिनहे) में ***% का निवेश किया है। यह कंपनी अन्य के उत्पादन के साथ-साथ मैट्रोनिडाजोल का विनिर्माण करती है। तथापि, याचिकाकर्ताओं का अनुरोध है कि प्राधिकारी को यह मानना चाहिए कि यह निवेश संबंध की पुष्टि नहीं करता है। सकुलर वीविंग मशीनों के मामले में प्राधिकारी के अंतिम जांच परिणाम का हवाला देते हुए उस पर भरोसा किया जा सकता है।

(घ) मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयातों के ब्यौरे का प्रकटन प्राधिकारी को किया जा चुका है। इन आयातों में मै. सुयश के जरिए मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयात भी

शामिल हैं । आयातों की समीक्षा किए जाने के बाद यह पाया गया है कि कंपनी ने असावधानीवश एक से अधिक आयातों की सूचना दी है । आयात का संशोधित विवरण प्राधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया है ।

(ड) मै. यिनहे ने भारतीय पक्षकारों को उत्पाद का सीधे निर्यात नहीं किया है । यह देखा जाएगा कि :

- मै. आरती ड्रग्स लि. विचाराधीन उत्पाद की एक आयातक है और वह मै. सुयश से संबंधित है ।
- मै. सुयश ने कुछ आयातों की व्यवस्था की है । तथापि, मै. सुयश विचाराधीन उत्पाद की आयातक नहीं है । मै. सुयश ने केवल इन आयातों की व्यवस्था की है और उसने प्रवेश बिल दायर नहीं किए हैं ।
- मै. इन्हे मै. आरती ड्रग्स लि. की संबद्ध कंपनी नहीं है क्योंकि उसकी शेयरधारिता केवल *** % है और उसके पास अधिकांश शेयरधारिता नहीं है । इसके बावजूद मै. इन्हे ने उत्पाद का निर्यात नहीं किया है । इसके अलावा, इन आयातों का प्रकटन मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयातों के रूप में पहले ही किया जा चुका है ।
- मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए आयात शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत किए गए हैं ।
- कंपनी द्वारा उत्पाद का आयात मूल जांच के समय और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांचों के समय भी किया जा रहा था । विधिवत विचार करने के बाद प्राधिकारी ने यह माना है कि मै. आरती ड्रग्स लि. निर्णायक समीक्षा जांचों में पात्र घरेलू उद्योग है ।
- मै. आरती ड्रग्स लि. की एक संबद्ध कंपनी मै. सुयश है जिसने मै. आरती ड्रग्स लि. की ओर से ही उत्पाद का आयात किया है और जिसने सामग्री की निकासी हेतु प्रवेश बिल दायर नहीं किया है । अतः मै. सुयश पर उत्पाद के आयातक के रूप में विचार नहीं किया जाना चाहिए ।
- मै. आरती ड्रग्स लि. पर इस अवधि के दौरान उत्पादन प्रतिबंध लगे हुए थे और इसलिए कंपनी द्वारा कुछ आयात अपने ग्राहकों की जरूरत को पूरा करने के लिए किए गए थे ।

xv. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि प्राधिकारी को मै. आरती ड्रग्स लि. को पात्र घरेलू उद्योग के रूप में मानना जारी रखा जाना चाहिए । इसके साथ-साथ प्राधिकारी मै. आरती ड्रग्स लि. को नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर अपात्र घरेलू उद्योग मान सकते हैं और यह मान सकते हैं कि मै. यूनीकैम लि. नियमों के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है ।

याचिकाकर्ता का अनुरोध है कि मै. आरती ड्रग्स लि. के संबंध और उसके द्वारा किए गए आयातों के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के दायरे से अलग रखने पर विचार करें । परिणामतः

मै. यूनीकैम लि. घरेलू उद्योग होगी और प्राधिकारी से अनुरोध है कि वे कृपया मै यूनीकैम लि. के आंकड़ों को लेकर घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर विचार करें :

प्राधिकारी द्वारा जांच

17. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में नियमानुसार उपबंध है:-

"घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उसके आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा ।

18. मै. आरती ड्रग्स लि. और मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज लि. (भारत) ने चीन जन.गण. के मूल के या वहां से निर्यातित "मैट्रोनिडाजोल" के पाटन का आरोप लगाते हुए वर्तमान मामले में आवेदन दायर किया था और पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा करने और उसे जारी रखने का अनुरोध किया था । यह उल्लेख किया गया था कि वे घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं क्योंकि संबद्ध वस्तु के अन्य घरेलू उत्पादकों ने अपना उत्पादन बंद कर दिया है अतः रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार आवेदकों का उत्पादन संबद्ध वस्तु का कुल भारतीय उत्पादन बनता है । प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तु के घरेलू उत्पादकों से अनुरोध किया कि वे अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराएं । इसके प्रत्युत्तर में केवल मै. यूनीकैम कैमिकल्स (मै. जे वी कैमिकल्स एंड फार्मा लि. का एक प्रभाग) ने यह कहते हुए उत्तर दायर किया कि वे पूर्व में मैट्रोनिडाजोल का विनिर्माण कर रहे थे । लेकिन वे अब इस उत्पाद का विनिर्माण नहीं कर रहे हैं और उन्होंने दिसंबर, 2010 से मैट्रोनिडाजोल का उत्पादन बंद कर दिया है और वे मै. हुबेई होंगयुआन फार्मा कं. लि. हुबेई, चीन से मैट्रोनिडाजोल की खरीद कर रहे हैं ।

9. तथापि, यह नोट किया जाता है कि मै. आरती ड्रग्स लि. ने जांच अवधि अर्थात् 1 जनवरी, 2010 से 31 दिसंबर, 2010 की अवधि के दौरान *** मी.ट. के कुल आयातों में से शुल्क छूट स्कीमों के अंतर्गत संबद्ध वस्तु के *** मी.ट. का आयात किया है । उन्होंने यह तर्क दिया है कि उनकी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ये आयात आवश्यक थे ।

ऊपर किए गए उल्लेखानुसार विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने अन्य बातों के साथ-साथ यह तर्क देते हुए अनुरोध दायर किए हैं कि मै. आरती ड्रग्स लि. को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से अलग रखा जाना चाहिए । घरेलू उद्योग ने भी अन्य बातों के साथ-साथ इस विषय पर यह तर्क देते हुए अनुरोध प्रस्तुत किए हैं कि उसे घरेलू उद्योग के भाग के रूप में शामिल किया जाना चाहिए । मै. आरती ड्रग्स लि. को शामिल करने/बाहर रखने तथा मै. आरती ड्रग्स लि. द्वारा किए गए संबद्ध वस्तु के आयातों की मात्रा के बारे में हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम

2(ख) के अनुसार मै. आरती ड्रस लि. को घरेलू उद्योग के क्षेत्र और दायरे से बाहर रखना उचित होगा। इसके परिणामस्वरूप संबद्ध वस्तु की एकमात्र शेष उत्पादक होने के कारण मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज घरेलू उद्योग बनती है जो पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करती है।

छ. पाटन का निर्धारण

मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. के अनुरोध

18. मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन.गण. ने संक्षेप में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लिमिटेड, ने अनुरोध किया है कि पाटन का निर्धारण सहयोगी प्रतिवादी के आंकड़ों के अनुसार किया जाना चाहिए।
- परिकलित सामान्य मूल्य: यदि प्राधिकारी प्रमुख निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत, चीन के प्रतिवादी उत्पादकों/निर्यातकों के खपत मानकों, परिवर्तन लागत और भारतीय घरेलू उद्योग के एस जी ए व्यय तथा 5% के उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखते हुए चीन के मैट्रोनिडाजोल के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करते हैं तो यह अनुरोध है कि प्राधिकारी निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें और सामान्य मूल्य तथा निर्यात कीमत के बीच उचित तुलना सुनिश्चित करने के लिए सामान्य मूल्य का परिकलन करते समय उचित समायोजन करें:

क. परिकलित सामान्य मूल्य का प्रयोजन चीन के उत्पादकों/निर्यातकों के लिए मैट्रोनिडाजोल की कारखाना घरेलू बिक्री कीमत का परिकलन करना है।

ख. मै. यूनीकैम की संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत उसकी अक्षमता अथवा उच्च 2 एम एन आई लागत के कारण काफी अधिक हो सकती है और इसलिए उस पर परिकलित सामान्य मूल्य हेतु विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग. प्राधिकारी को घरेलू उद्योग के खपत मानकों जो अक्षमताओं के कारण प्रभावित हैं, के बजाए परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु चीन के सहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रदत्त कच्ची सामग्री के खपत मानकों का प्रयोग करना चाहिए।

घ. वर्तमान मामले में प्राधिकारी को परिकलित सामान्य मूल्य के निर्धारण के लागत के भाग के रूप में वित्तीय लागत पर विचार नहीं करना चाहिए क्योंकि चीन के उत्पादक की घरेलू कीमत की गैर बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे के कारण अनदेखी की जा सकती है। तथापि, ऋण दिवसों से संबंधित ऋण लागत को निवल निर्यात कीमत निकालने के

लिए निर्यात कीमत की अनदेखी की गई है ! वित्तीय लागत पर निर्यात कीमत की तुलना में परिकलित सामान्य मूल्य की गणना में विचार नहीं किया जाना चाहिए ।

घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

• परिकलित सामान्य मूल्य - निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

(क) आयात कीमत : चीन से निविष्टियों की आयात कीमत खासकर वर्तमान मामले में अंतर्राष्ट्रीय कीमत नहीं बन सकती, क्योंकि चीन के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है । चीन के उत्पादकों पर एक कार एम टी जैड हेतु गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के रूप में विचार किए जाने के बाद वे अपनी कच्ची सामग्री के लिए भी गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां बन जाती हैं । यह उल्लेखनीय है कि कच्ची सामग्री और तैयार उत्पाद दोनों का सामान्य रूप से उत्पादन चीन में उन्हीं कंपनियों द्वारा किया जा रहा है । अतः यदि चीन की कंपनियां एम टी जैड हेतु गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं तो वे 2 एम एन आई और एम आई के लिए भी गैर-बाजार अर्थव्यवस्था हैं । प्राधिकारी कृपया चीन से हुए आयातों को अलग रखने के बाद इन निविष्टियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करने के बाद सामान्य मूल्य का परिकलन करें ।

(ख) जहां तक खपत मानकों का संबंध है, हमारा अनुरोध है कि कंपनी को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किए जाने की स्थिति में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

(ग) जहां तक हुबेई द्वारा प्रस्तुत विधिक आधार का संबंध है, हमारा अनुरोध है कि हुबेई की विधिक समझदारी यह है कि सामान्य मूल्य का प्रयोजन चीन के उत्पादकों/निर्यातकों की कारखाना घरेलू कीमत का परिकलन करना है न कि भारतीय घरेलू उद्योग की कारखाना घरेलू उद्योग कीमत का परिकलन करना । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 का उल्लेख करते हुए यह तर्क दिया गया है कि गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियों के मामले में सामान्य मूल्य ऐसे देश में घरेलू बिक्री कीमत पर आधारित नहीं होगा । वस्तुतः यह भारत सहित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देशों में लागत या कीमत पर आधारित होगा ।

(घ) जहां तक इस तर्क का संबंध है कि यूनीकैम की उत्पादन लागत उसकी अक्षमताओं के कारण अधिक हो सकती है, घरेलू उद्योग का अनुरोध है कि (i) यह तर्क मात्र आनुमानिक

है और साक्ष्य से रहित है. (ii) यूनीकैम देश में उत्पाद और विभिन्न वस्त्रों का एक कुशल विनिर्माता है । यूनीकैम को अकुशल उत्पादक के रूप में मानने का कोई विधिक आधार नहीं है। वस्तुतः निर्यातक को ऐसे कोरे विवरण देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जिनकी पुष्टि साक्ष्य द्वारा न की गई हो ।

(ड) चीन से 2 एम एन आई की आयात कीमत को किसी भी हालत में इस वजह से स्वीकार नहीं किया जा सकता कि चीन के उत्पादकों को एम टी जैड हेतु गैर बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान किया जा रहा है क्योंकि यही उत्पादन 2 एम एन आई और एम आई के भी उत्पादक हैं । प्राधिकारी चीन के लिए 2 एम एन आई की आयात कीमत पर तभी विचार कर सकते हैं जब यह पाया जाए कि वह अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की प्रतिनिधिक है ।

(च) जहां तक कार्बन ब्लैक के मामले का हवाला दिए जाने का संबंध है, यह किसी विधिक और तथ्यात्मक आधार से रहित है । इस बात की प्रबल संभावना है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी उक्त जांच में यह पाएं कि निर्यातकों द्वारा सूचित खपत के कारक उन्हें प्रदत्त गैर बाजार अर्थव्यवस्था के व्यवहार के बावजूद अत्यंत विश्वसनीय हैं । चूंकि यह मुद्दा तथ्य के अत्यधिक विवादित प्रश्न से संबंधित है, इसलिए प्राधिकारी को किसी अन्य जांच का हवाला नहीं देना चाहिए और वे कृपया वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई स्वतंत्र निर्णय दें ।

(छ) जहां तक वित्तीय लागत का संबंध है, यह तर्क अस्वीकरणीय है । ऐसा प्रतीत होता है कि हुबेई ने यह माना है कि सामान्य मूल्य के प्रयोजनार्थ उत्पादन लागत में बिक्री पर अनुमत ऋण के कारण केवल वित्तीय लागत शामिल की गई है । सामान्य मूल्य के निर्धारण में शामिल वित्तीय लागत वस्तुतः नियत परिसंपत्तियों और कार्यशील पूंजी में विनिर्माण संगठन द्वारा लगाए गए वित्त की लागत शामिल होती है । इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी कृपया इस संबंध में स्थापित परंपरा का पालन करें ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

सामान्य मूल्य

20. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को प्रश्नावलियां भेजीं और उन्हें निर्धारित प्रपत्र में तथा ढंग से सूचना प्रदान करने की सलाह दी । इसके प्रत्युत्तर में चीन जन.गण. के एक उत्पादक तथा निर्यातक केवल मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि. ने प्रश्नावलियों का उत्तर दायर कर इस जांच में सहयोग किया है ।

21. प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत तथा अन्य डब्ल्यू टी ओ सदस्यों द्वारा विगत तीन वर्षों में पाटनरोधी जांचों में चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है ।

चीन जन.गण. को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना गया है जो पाटनरोधी नियमों के अनुसार निर्यातक देश या अलग-अलग निर्यातकों/उत्पादकों द्वारा इस अनुमान के खंडन के अधीन है ।

22. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध I के पैराग्राफ 8 के अनुसार गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान का उस स्थिति में खंडन किया जा सकता है यदि चीन के निर्यातक (निर्यातकों) द्वारा पैराग्राफ 8 के उप पैरा(3) में विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर सूचना और पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं और उसके विपरीत सिद्ध करते हैं । चीन जन.गण. के संबद्ध वस्तु के निर्यातकों/उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी व्यवहार विषयक प्रश्नावली के उत्तर में पैरा 8 के उप पैरा (3) में उल्लिखित आवश्यक सूचना/पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करना अपेक्षित है ताकि निर्दिष्ट प्राधिकारी निम्नलिखित मापदंडों पर विचार कर सकें कि क्या :-

- कच्ची सामग्रियों सहित कीमत; लागत और निविष्टि तथा श्रम लागत, उत्पादन, बिक्रियां और निवेश के बारे में चीन जन.गण. में संबंधित फर्मों का निर्णय ऐसे बाजारी संकेतों के अनुसार किया जाता है जिसमें आपूर्ति और मांग परिलक्षित होती है और इस बारे में राज्य का अधिक हस्तक्षेप नहीं होता है और क्या प्रमुख निविष्टियों की लागत में बाजार मूल्य पर्याप्त रूप से प्रदर्शित होते हैं;
- इस प्रकार की फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति विशेषकर परिसंपत्तियों के मूल्यहास, अन्य बड़े खातों, वस्तु विनिमय-व्यापार और ऋणों की प्रतिपूर्ति के माध्यम से भुगतान के संदर्भ में पूर्ववर्ती गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाली प्रणाली से हुई महत्वपूर्ण विकृतियों के अध्यधीन हैं;
- इस प्रकार की फर्मों दिवालियापन और संपत्ति कानूनों के अध्यधीन हैं जो फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता और स्थिरता की गारंटी देते हैं; और
- विनिमय दर का परिवर्तन बाजार की दर पर किया जाता है ।

23. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्राधिकारी द्वारा जारी जांच शुरुआत संबंधी सूचना के बाद चीन के एक उत्पादक/निर्यातक मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं. लि. ने बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी प्रश्नावली के उत्तर सहित प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत किया है और गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अनुमान के खंडन की मांग की है । तथापि, चीन की कंपनी के परिसरों में मौके पर जांच के दौरान कंपनी एम ई टी के अपने दावे की पुष्टि करने में सफल नहीं रही और इस प्रकार इस दावे को छोड़ने का निर्णय लिया गया । प्रश्नावलियों के उत्तर का अवलोकन किया गया जिसमें अन्य

बातों के साथ साथ यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू बाजार में बेची गई वस्तु तथा भारत को निर्यातित वस्तु समान हैं ।

चीन जन.गण. के निर्यातकों/उत्पादकों के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण

24. चूंकि चीन का एकमात्र सहयोगी निर्यातक/उत्पादक एम ई टी अनुमान का खंडन करने में समर्थ नहीं रहा है और इसके बजाए उसने एम ई टी का दावा छोड़ने का विकल्प चुना है और चीन के किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने प्रश्नावलियों का उत्तर नहीं प्रस्तुत किया है और एम ई टी अनुमान के खंडन की मांग नहीं की है इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के आधार पर चीन जन गण में सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है ।

25. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 में प्रावधान है कि :

"गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयातों के मामले में सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश की कीमत अथवा संरचित मूल्य, अथवा किसी तीसरे देश से भारत सहित अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव न हो, अथवा अन्य किसी समुचित आधार पर किया जाएगा, जिसमें भारत में समान वस्तु के लिए वास्तविक रूप से संदत्त अथवा भुगतान योग्य कीमत, जिसमें यदि आवश्यक हो तो लाभ की समुचित गुंजाइश भी शामिल की जाएगी । निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी तीसरे समुचित देश का चयन उचित तरीके से किया जाएगा जिसमें संबंधित देश के विकास के स्तर तथा प्रश्नगत उत्पाद का ध्यान रखा जाएगा और चयन के समय उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना का भी ध्यान रखा जाएगा । जहां उचित हो उचित समयसीमा के भीतर किसी अन्य बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के संबंध में इसी प्रकार के मामले में की गई जांच पर भी ध्यान दिया जाएगा । जांच से संबंधित पक्षों को बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त प्रकार से चयन के बारे में बिना किसी अनुचित विलंब के सूचित किया जाएगा और उन्हें अपनी टिप्पणियां देने के लिए उचित अवधि प्रदान की जाएगी ।"

26. चूंकि पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 (2) में निहित गैर बाजार अर्थव्यवस्था का अनुमान अखंडित रहता है, इसलिए प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित किया है । पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 में निर्धारित अन्य पद्धतियों के बारे में रिकॉर्ड में पर्याप्त सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने "किसी अन्य उचित आधार" की पद्धति अपनाकर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है ।

27. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी ने चीन जन.गण हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन किया है । यह नोट किया जाता है कि संबद्ध वस्तु के विनिर्माण हेतु प्रमुख कच्ची सामग्री है - ऐंसेटिक ऐसिट, 2- एम एन आई, सल्फ्यूरिक ऐसिड, एथिलिक ऑक्साइड तथा कार्बोस्टिक सोडा । सामान्य मूल्य के परिकलन हेतु दो एम एन आई, ऐंसेटिक ऐसिड और सल्फ्यूरिक ऐसिड की

अंतर्राष्ट्रीय कीमतों पर विचार किया गया है जबकि अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री- एथीलिन ऑक्साइड और कौस्टिक सोडा के लिए प्राधिकारी ने कुशल घरेलू उत्पादक की खरीद कीमत पर भरोसा किया है क्योंकि उनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमतें काफी असामान्य हैं । इसके अलावा कुशल घरेलू उत्पादक के खपत कारक, परिवर्तन लागत, एस जी ए व्यय और वित्तीय लागत पर विचार किया गया है । इसमें 5% का उचित लाभ मार्जिन जोड़ा गया है । इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य *** अम.डॉ./किग्रा. बनता है ।

निर्यात कीमत

मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कं.

28 प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन के एकमात्र उत्पादक/निर्यातक मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल कंपनी लि. ने प्रश्नावलियों का उत्तर प्रस्तुत किया है । उत्तर के अवलोकन से यह नोट किया गया है कि कंपनी ने जांच अवधि के दौरान भारत को *** मी.ट. संबद्ध वस्तु का निर्यात किया है । अंतरदेशी दुलाई, विदेशी भाड़े, समुद्री बीमा, हैंडलिंग व्यय, कमीशन, ऋण लागत और बैंक प्रभारों के लिए दावा किए गए और मौके पर सत्यापन के दौरान यथासत्यापित समायोजन स्वीकार किए गए हैं । मौके पर सत्यापन के दौरान यह भी नोट किया गया था कि कंपनी ने इस तथ्य के बावजूद कि वह 17% की दर से वैट का भुगतान कर रही थी । उसने वैट के लिए कोई समायोजन नहीं किया था सत्यापन के दौरान कंपनी ने दावा किया कि वह ***% की दर से वैट वापसी प्राप्त कर रही है । इस प्रकार वैट की राशि में अंतर को भी समायोजित किया गया है । इस प्रकार निकाली गई निवल निर्यात कीमत *** अम.डॉ./किग्रा. निर्धारित की गई है ।

असहयोगी निर्यातक/उत्पादक

29. चूंकि किसी अन्य निर्यातक/उत्पादक ने ऐसी कोई सूचना प्रदान नहीं की है जिसका उपयोग निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु किया जा सके । इसलिए प्राधिकारी ने न्यूनतम प्रतिनिधिक सौदों के आधार पर रिकॉर्ड में "उपलब्ध तथ्यों" के अनुसार "निर्यात कीमत" निर्धारित की है जो *** अम.डॉ./किग्रा. बनती है ।

ज. पाटन मार्जिन

30. कारखाना स्तर पर इस प्रकार निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर चीन जन.गण. के सभी निर्यातकों/उत्पादकों के लिए जांच अवधि के दौरान पाटन मार्जिन का निर्धारण निम्नानुसार किया गया है:

निर्यातक/उत्पादक	देश	पाटन मार्जिन (अम.डॉ./किग्रा.)	पाटन मार्जिन	पाटन मार्जिन रेंज

मे. हुबेई हॉंगयुआन फार्मास्युटीकल कं. लि.	चीन जन.गण.	***	***	30 - 40
अन्य कोई	चीन जन.गण.	***	***	50 - 60

अ. पाटन का जारी रहना या उसकी पुनरावृत्ति होना :

घरेलू उद्योग के अनुरोध:

31. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- ऐसी स्थिति में जहां सतत निर्यात होते हैं, प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये पाटित कीमतों पर हुए थे । यदि भारत को हुए निर्यात पाटित कीमतों पर नहीं हैं तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या तीसरे देश को निर्यात पाटित कीमत पर हुए हैं और क्या यह प्रतीत होता है कि क्या निर्यात कीमतें यह सिद्ध करने के लिए उचित और भरोसेमंद हैं कि पाटन की कोई संभावना नहीं है । यदि भारत को निर्यात पाटित कीमत पर हुए हैं तो यह माना जाना चाहिए कि निर्यातक पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटित कीमत पर संबद्ध वस्तु का निर्यात जारी रखेंगे । यदि वर्तमान निर्यात अपाटित कीमत पर हुए हैं तो इस बात की जांच की जानी चाहिए कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातक द्वारा ये कीमत बरकरार रखे जाने की संभावना है । यदि निर्यातक द्वारा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में ये कीमतें बरकरार रखे जाने की संभावना नहीं है तो प्राधिकारी को उस कीमत का निर्धारण करना चाहिए जिस कीमत पर पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में निर्यातक द्वारा निर्यात किए जाने की संभावना हो और तत्पश्चात यह निर्धारित किया जाना चाहिए कि क्या ये निर्यात पाटित कीमतों पर हुए हैं । यह उल्लेखनीय है कि चीन जन.गण. का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत पर ध्यान न देने के बावजूद बैंकमार्क कीमत से भी काफी कम है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर आयात अत्यधिक कम कीमत पर किए जाने की संभावना है ।
- वर्तमान मामले में संबद्ध देश के निर्यातकों और उत्पादकों ने पाटनरोधी शुल्क लागू किए जाने के बाद भी पाटित कीमत पर सामग्री का निर्यात जारी रखा है जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है :

जांच की प्रकृति	पाटन मार्जिन (%)
मूल	47.85%
निर्णायक समीक्षा-1	68.67%
वर्तमान जांच	29.08%

- प्राधिकारकों का अनुरोध है कि उपर्युक्त आकड़ों से संबद्ध देश के मामले में पाटन की संभावना की पुष्टि हो जाएगी।

क. पूर्ववर्ती सभी जांचों में संबद्ध उत्पाद के बारे में निर्धारित पाटन मार्जिन

- प्राधिकारी ने चीन जग.गण. से मैट्रोनिडाजोल के आयातों के बारे में दो पाटनरोधी जांचें की हैं। पूर्ववर्ती जांचों अर्थात् मूल जांच और निर्णायक समीक्षा जांच, दोनों में अत्यधिक पाटन की मौजूदगी की पुष्टि हुई है।
- वर्तमान जांच अवधि में भी पाटन मार्जिन काफी अधिक है। इराके अलावा, शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में और तेजी आने की संभावना है। संबद्ध देश से क्षति अवधि में पाटित आयातों की संवर्धित मात्रा के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता है। इससे इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने और उसमें वस्तुतः वृद्धि होने की संभावना है।
- पाटन मार्जिन जो काफी अधिक बना हुआ है, के बारे में पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है। पूर्व में संपन्न की गई जांच में भी प्राधिकारी ने अत्यधिक पाटन मार्जिन पाया था और संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के साथ जांच संपन्न की थी।

ख. संबद्ध देश में अतिरिक्त उत्पादन क्षमता

- इस बात पर विचार करते हुए कि संबद्ध देश से विभिन्न देशों को पर्याप्त निर्यात किए जाते हैं, संबद्ध देश के निर्यातकों के पास भारतीय मांग से काफी अधिक क्षमताएं हैं। निम्नलिखित तालिका से चीन के कुछ उत्पादकों की उत्पादन क्षमताओं का पता चलता है:

क्र.सं.	चीन में उत्पादक	क्षमता/आपूर्ति सामर्थ्य (प्रति वर्ष मी. ट.)
1	हुबेई हांगयुआन फार्मास्युटीकल्स कं. लि.	5,000
2	हेफेई टी एन जे कैमिकल इंडस्ट्री कं. लि.	5,000
3	हैंगझोऊ तियानकाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं. लि.	5,000
4	हैंगझोऊ रूइजियांग कैमिकल कं. लि.	1,000

5	चाइना फूडफार्मा ग्रुप कं. लि.	7,200
6	शिजियाझुआंग विटूर इपोर्ट ट्रेडिंग कं. लि.	500

- संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों की ओर से सतत पाटन किया जा रहा है जिसमें लागू शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में और वृद्धि होने की संभावना है। इस प्रकार पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन संवर्धित स्तर पर जारी रहने की संभावना है।

ग. भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता

- आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है।

विवरण	इकाई	जांच अवधि
आयातों का पहुंच मूल्य	रु/किग्रा.	449.68
घरेलू उद्योग की निचल बिक्री प्राप्ति *	रु/किग्रा.	***
घरेलू उद्योग की बिक्री की लागत*	रु/किग्रा.	***
घरेलू उद्योग की लक्षित बिक्री कीमत (डी पी सी ओ अधिरूचित कीमत)	रु/किग्रा.	526.00

*यह मानते हुए कि केवल यूनीकैम घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करती है

- उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि चीन के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की वर्तमान और संभावित बिक्री कीमत से कम है। अतः चीन के उत्पादक शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में भारतीय बाजार को आक्रामक ढंग से लक्ष्य बनाएंगे। इस प्रकार यदि घरेलू उद्योग बाजार में उचित कीमत वसूल करेगा तो चीन के उत्पाद के सस्ता होने की संभावना है।

घ. भारतीय बाजार में संबद्ध देश द्वारा धारित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि

भाग में बाजार हिस्सा	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
----------------------	------	---------	---------	---------	-----------	----------------

हिस्सा						अवधि
संबद्ध देश	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
अन्य देश	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16
घरेलू उद्योग	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
अन्य भारतीय उत्पादक	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14

- अनुरोध है कि क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. द्वारा धारित बाजार हिस्सा न केवल अधिक रहा है अपितु काफी ज्यादा भी रहा है। वस्तुतः भारतीय बाजार में पर्याप्त हिस्सा चीन जन.गण. का रहा है। लागू शुल्क के बावजूद चीन द्वारा धारित हिस्से में गिरावट नहीं आई है। उसके विपरीत पाटित आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है।

ड संबद्ध देश से आयात के मूल्य और मात्रा में भारी वृद्धि

- यह देखा जा सकता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और मूल्य में भारी वृद्धि हुई है। इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में तेजी आएगी।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
आयात-मूल्य						
चीन जन.गण.	मी.ट.	522	506	740	1,133	1,049
अन्य देश	मी.ट.	12	26	28	-	92
कुल आयात	मी.ट.					

		535	532	769	1,133	1,141
आयात- मूल्य *						
चीन जन. गण.	लाख रुपए	1,694	2,203	2,972	4,670	4,415
अन्य देश	लाख रुपए	46	106	146	0	503
कुल आयात मूल्य	लाख रुपए	1,740	2,309	3,118	4,670	4,918

- यह देखा जा सकता है कि चीन से आयात में जिस दर से वृद्धि हो रही है वह अन्य देशों की तुलना में काफी अधिक है। वस्तुतः जांच अवधि में अन्य देशों से आयात शून्य है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की स्थिति काफी नाजुक बन जाएगी।

घ. संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों का निर्यातोन्मुखी होना

- अनुरोध है कि चीन जन. गण. के निर्यातक विश्व भर में सर्वाधिक निर्यातोन्मुखी हैं। चीन की कंपनियों का निर्यात का प्रतिशत 30%-100% के बीच है। अतः इस चरण पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति में अत्यधिक उच्च स्तर पर पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

छ. लागू पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती

- पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों के पहुंच कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ करने पर यह देखा जाएगा कि अत्यधिक कीमत कटौती मौजूद है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना मौजूद है। आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि बेंचमार्क पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत से काफी कम है।

ज. एक भी शर्त पूरी होने पर शुल्क समाप्त किया जा सकता है

- ऊपर चर्चा की गई शर्तों में से यह आवश्यक नहीं है कि शुल्क जारी रखने के लिए सभी शर्तें मौजूद हों। ऐसे कई मामले हैं जिनमें एक या अधिक मापदंड पूरा होने की स्थिति शुल्क जारी रखा गया है।

- वर्तमान मामले के तथ्यों को देखते हुए और उपर्युक्त मापदंडों पर विचार करते हुए अनुरोध है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति जारी रहने की प्रबल संभावना है ।

मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं. लि. के अनुरोध

32. मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं. लि. ने संक्षेप में निम्नानुसार तर्क दिए हैं:

- (क) पाटन और प्रतिवादी उद्योग को क्षति की संभावना का दावा मात्र अनुमानों पर आधारित है ।
- (ख) तीसरे देश में पाटन कानूनन कोई वैध आधार नहीं है ।
- (ग) निर्यातक की मात्र बेशी क्षमता से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वास्तविक क्षति का आसन्नवर्ती खतरा है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

33. संगत प्रावधानों के अनुसार किसी निर्णायक समीक्षा जांच में निम्नलिखित पहलुओं का जांच करना जरूरी है:

- क्या पाटन जारी है; और यदि हां, तो क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में इसके जारी रहने की संभावना है ।
- जहां पाटन जारी नहीं है, वहां क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होगी;

34. पाटनरोधी नियमों के अंतर्गत किसी निर्णायक समीक्षा जांच में पाटन की संभावना की जांच करने के लिए कोई विशिष्ट कार्य प्रणाली निर्धारित नहीं है । तथापि, यदि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के निर्यातों के बारे में अत्यधिक सकारात्मक पाटन मार्जिन है तो इस बात की संभावना है कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में जब तक तथ्यों से अन्यथा पता न चले, पाटन जारी रहेगा । तथापि, यदि जांच अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं हुआ है तो इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । ऐसे मामलों में अन्य संगत कारकों उदाहरणार्थ पाटन की तीव्रता के बारे में साक्ष्य, यदि कोई हो, की जांच करना अपेक्षित है, जिसका निर्धारण तीसरे देश के बाजारों में संबद्ध वस्तु के निर्यात पर विचार करके किया जा सकता है ।

35. वर्तमान मामले में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का अत्यधिक मात्रा में आयात किया गया है । वस्तुतः क्षति अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो रही है । यह नोट किया जाता है कि इन वस्तुओं का निर्यात पाटन कीमतों पर

हुआ है और इनसे घरेलू उद्योग की कीमत में भारी कटौती हो रही है। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दी जाती है तो पाटित कीमत पर संबद्ध वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है। चीन जन.गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादन हेतु अप्रयुक्त क्षमताओं पर विचार करते हुए इस मत को और बल मिलता है जिसका खंडन किसी हितबद्ध पक्षकार ने नहीं किया है।

36. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति दिए जाने की स्थिति में संबद्ध वस्तु का पाटन जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से संबद्ध देश से पाटित कीमत पर संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में वृद्धि होने की संभावना है।

क्षति

हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध और उनकी जांच

मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लि., चीन जन.गण.

37. मै. हुबेई हांगयुआन फार्मास्यूटिकल कंपनी लि., चीन जन.गण ने संक्षेप में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

- यूनीकैम लेबोरेटरीज लि. द्वारा करवाया गया उजरती कार्य.- मै. यूनीकैम भारत में संबद्ध वस्तु का एक लघु उत्पादक है और कुछेक उत्पादन कार्यकलाप उजरती कार्य आधार पर मै. आरती द्वारा भी किए जाते हैं और इस बात की संभावना है कि कंपनी ने इन दोनों उत्पादनों के लिए पृथक क्षमताएं दर्शायी हों। अतः प्राधिकारी को इस पर गौर करना चाहिए।
- क्षमता उपयोग-आवेदक उद्योग ने दिनांक 23.4.2012 के अपने अनुरोध में क्षमता को गोपनीय सूचना होने का दावा किया है। अतः अनुरोध है कि प्राधिकारी को उस स्थिति में उजरती कार्य को अलग करना चाहिए और क्षति की जांच करना चाहिए। यदि मै. यूनीकैम ने क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की अपनी संयंत्र की क्षमता का पूर्ण उपयोग न किया हो।
- उत्पादन लागत- मै. यूनीकैम द्वारा क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु के दो प्रकार के उत्पादन (अर्थात् उजरती कार्य और अपना उत्पादन) किए जा रहे हैं। अतः प्राधिकारी के लिए जांच अवधि के दौरान मै. यूनीकैम के खुद के उत्पादन और उसके उजरती कार्य पर किए गए उत्पादन की लागत की तुलना करना अपेक्षित है। ऐसा करना यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि आवेदक घरेलू उद्योग को उसकी कम क्षमता या अक्षमताओं के कारण क्षति हुई है। यदि कम क्षमता या अक्षमताओं के कारण खुद की उत्पादन लागत अधिक है तो प्राधिकारी को क्षति की जांच करते समय अक्षमताओं के कारण उत्पादन की अधिक लागत पर ध्यान नहीं देना चाहिए।

- कीमत प्रभाव: चीन जन.गण. से पहुंच कीमत 2008-09 में 470 रु. प्रति किग्रा से घटकर 2009-10 में 433 रूपए प्रति किग्रा. हो गई है जबकि इसी अवधि में आवेदक की बिक्री कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित हो रही है। अतः आवेदक उद्योग की बिक्री कीमत में ऐसी स्थिति में वृद्धि हुई है जब पहुंच कीमत में गिरावट आई है। इससे अंतरनिहित संबंध का पता चलता है और पहुंच कीमत तथा घरेलू बिक्री कीमत के बीच सह-संबंध प्रदर्शित होता है। अतः चीन जन.गण. से हुए आयातों से घरेलू कीमतें प्रभावित नहीं हुई हैं।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	358	470	433	445
परिवर्तन	रु./किग्रा.	-	112	-37	12
यूनीकैम की बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
परिवर्तन	रु./किग्रा.	-	59	17	

- कारणात्मक संबंध: हालांकि वर्ष 2009-10 में पहुंच कीमत में गिरावट आई है तथापि, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि हुई है जिससे अंतरनिहित संबंध क स्पष्ट पता चलता है, कारणात्मक संबंध की पुष्टि तो होती ही नहीं है।

घरेलू उद्योग की ओ से किए गए अनुरोध

38. घरेलू उद्योग ने संक्षेप में निम्नानुसार अनुरोध किए हैं:

प्रारंभिक अनुरोध: पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) में "घरेलू उद्योग" इस प्रकार परिभाषित है - "घरेलू उद्योग" का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बनता है, परंतु जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं या वे स्वयं उर्रादे आयातक होते हैं तो ऐसे मामले में "घरेलू उद्योग" पद का अर्थ केवल शेष उत्पादकों के उल्लेख के रूप में निकाला जाएगा।

भागीदार कंपनियों का उत्पादन भारतीय उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा रखता है। अतः भागीदार कंपनी पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार "घरेलू उद्योग" है। विरोधी पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि मै. आरती इंग्स. लि., को घरेलू उद्योग का भाग

नहीं माना जाना चाहिए । यद्यपि यूनीकैम ने कोई आयात नहीं किया है तथापि मै. आरती इग्स लि. ने उसके द्वारा किए गए आयातों के बारे में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराई है ।

निर्दिष्ट प्राधिकारी विकल्प के तौर पर मै. यूनीकैम के बारे में पात्र घरेलू उद्योग के रूप में विचार कर सकते हैं और केवल मै. यूनीकैम के आंकड़ों के आधार पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण कर सकते हैं और उसने यह मानते हुए क्षति संबंधी सूचना भी प्रस्तुत है कि केवल मै. यूनीकैम लेबोरेटरीज पर घरेलू उद्योग के रूप में विचार किया जाए ।

क्षति संबंधी सूचना का पृथक्करण

पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध ii (iv) का हवाला देते हुए यह अनुरोध किया गया है कि मै. यूनीकैम एक बहुउत्पाद कंपनी है और उसने व्यवहार्य सीमा तक समान वस्तु के बारे में संगत सूचना पृथक् रूप में उपलब्ध करायी है । तथापि, उन स्थितियों में जिनमें समान वस्तु के बारे में पृथक् सूचना उपलब्ध नहीं होती है, क्योंकि उक्त सूचना का पृथक् अभिज्ञान उचित रूप से उपलब्ध नहीं होता है, सूचना उत्पादों के निकटतम समूह/रेंज के बारे में प्रदान की गई है जिसमें समान वस्तु शामिल है, जिसके बारे में आवश्यक सूचना उपलब्ध है और जिसे प्रदान किया जा सकता है ।

यह तर्क दिया गया है कि समीक्षा जांच करते समय प्राधिकारी के लिए उस सीमा पर विचार करना अपेक्षित होता है जिसके सीमा तक घरेलू उद्योग के निष्पादन में हुआ कोई सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क से संबंधित होता है और क्या घरेलू उद्योग मौजूदा शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति हेतु सुभेद्य है । किसी निर्णायक समीक्षा जांच में क्षति विश्लेषण में मूल जांच के समय और जांचोत्तर अवधि में घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति में हुए सुधार की दृष्टि से घरेलू उद्योग की आर्थिक स्थिति पर विचार करना शामिल होता है ।

इसके अलावा, घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति का निर्धारण करने के लिए घरेलू उत्पादन, उत्पादन क्षमता तथा क्षमता उपयोग, बिक्री, स्टॉक, रोजगार, खपत, बाजार हिस्से, कीमत प्रवृत्ति, लाभप्रदता, निवेश और अन्य कारकों पर विचार करना अपेक्षित होता है । और यदि इस विश्लेषण के परिणामस्वरूप यह पाया जाता है कि आयातों से घरेलू उद्योग को क्षति जारी है तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लागू शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में केवल पहले से कमजोर चल रहे घरेलू उद्योग की हालत और खराब होगी । जहां कोई आयात नहीं हुआ है, वहां लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना के बारे में जांच करना अपेक्षित होता है ।

यह तर्क दिया गया है कि प्राधिकारी ने मूल तथा निर्णायक समीक्षा जांचें की थीं, जिनमें यह निष्कर्ष निकाला गया था कि घरेलू उद्योग को सतत वास्तविक क्षति हुई है । इस पर वर्तमान अवधि में घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बारे में विचार किया जाए ।

- (क) विचाराधीन उत्पाद की मांग में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है ।
- (ख) विचाराधीन उत्पाद के आयात में समूची क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है और 2009-10 में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उसके बाद जांच अवधि में वृद्धि हुई है । तथापि, तीसरे देशों से आयातों में उस सीमा तक गिरावट आई है और यहां तक कि जांच अवधि में तीसरे देशों से कोई आयात नहीं हुआ था ।
- (ग) पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद आयातों में समग्र रूप में अत्यधिक वृद्धि हुई है ।
- (घ) आयातों में भारत में उत्पादन और उत्पाद की खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है ।
- (ङ) भारत में मांग/खपत की तुलना में आयातों का हिस्सा काफी अधिक रहा है ।
- (च) घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उसे अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करने से वंचित किया गया है ।
- (छ) समूची क्षति अवधि के दौरान कुल आयातों में चीन के बाजार हिस्से में भारी वृद्धि हुई है और यह जांच अवधि में कुल आयातों का 83% है जबकि अन्य देशों के हिस्से में समूची क्षति अवधि में गिरावट आई है ।
- (ज) वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बाद भी संबद्ध देश से आयातों द्वारा घरेलू कीमत में कटौती हो रही है ।
- (झ) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में अत्यधिक गिरावट के साथ समूची क्षति अवधि में गिरावट आई है ।
- (ञ) घरेलू उद्योग के क्षमता उपयोग में भी उत्पादन के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।
- (ट) घरेलू उद्योग की बिक्री में समूची क्षति अवधि के दौरान गिरावट आई है ।
- (ठ) समूची क्षति अवधि के दौरान मांग में चीन के उत्पादकों द्वारा धारित बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है जबकि क्षति अवधि में घरेलू उद्योग के हिस्से में लगातार गिरावट आई है ।
- (ड) लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग लाभ कमाने में समर्थ नहीं रहा है । यदि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो घरेलू उद्योग आयात कीमत से तुलनीय कीमत पर अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होगा । इसकी परिणति अत्यधिक वित्तीय घाटे, निवेश पर नकारात्मक आय और भारी नकद घाटे के रूप में होगी ।
- (ढ) निवेश पर आय और नकद लाभ में लाभप्रदता के समान प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई है ।
- (ण) रोजगार का स्तर समूची क्षति अवधि में स्थिर रहा है । तथापि, प्रदत्त मजदूरी में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है । प्रति दिन उत्पादकता में 2008-09 में गिरावट आई, 2009-10 में वृद्धि हुई और तत्पश्चात जांच अवधि में यह स्थिर रही ।
- (त) मालसूची के स्तर में 2008-09 तक गिरावट आई परंतु उसके बाद जांच अवधि के दौरान भारी वृद्धि हुई जिससे संबद्ध देश से कम कीमत पर हुए आयातों के कारण बाजार में अपने उत्पाद बेचने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता का स्पष्ट पता चलता है ।
- (थ) बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय और नकद लाभ के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि प्रतिकूल रही है ।
- (द) वर्तमान स्थिति से इस बात की स्पष्ट पुष्टि होती है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से आयातों में आगे और वृद्धि होगी जिसकी वजह से भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु के पाटन में आगे और तेजी आएगी ।
- (ध) आयातों में वृद्धि का कारण शुल्क के बैचमार्क स्वरूप का कारण न रहना है ।

- (न) लगाई गई पूंजी के निर्धारण हेतु आधार के रूप में निवल अचल परिसंपत्तियां गलत हैं और प्राधिकारी को संयंत्रों के निवल वर्तमान मूल्य या कम से कम सकल अचल परिसंपत्तियों पर विचार करना चाहिए ।
- (प) संयंत्र की आयु को देखते हुए लगाई गई पूंजी पर आय की मात्रा पर विचार करना चाहिए ।
- (फ) किसी अन्य वर्ष में उत्पादन के आधार पर निर्धारित व्यय को ईष्टतम नहीं बनाया जाना चाहिए । इन वर्षों में उत्पाद का उत्पादन सीधे उत्पाद मिश्रण पर निर्भर होता है और इसलिए यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा कि कंपनी ने उत्पादन क्षमताओं का अकुशल उपयोग किया है । याचिकाकर्ता का प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह जांच अवधि में संयंत्र के उपयोग के वास्तविक स्तर पर विचार करे ।
- **यूनीकैम द्वारा करवाया गया उजरती कार्य** - इस तर्क का कोई आधार नहीं है कि यूनीकैम संबद्ध वस्तु की एक लघु उत्पादक है । यूनीकैम का उत्पादन भारतीय उत्पादन का 29.36% बनता है । वस्तुतः कई अवसरों पर यह माना गया है कि जिन घरेलू उत्पादकों का सामूहिक उत्पादन 25% से अधिक बनता है, उनका उत्पादन प्रमुख उत्पादन बनता है । ऐसा मामला होने के कारण यूनीकैम को एक लघु उत्पादक कहना किसी विधिक तथा तथ्यात्मक आधार से रहित है । इसके विपरीत यूनीकैम का उत्पादन भारतीय उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है । क्षति अवधि के दौरान यूनीकैम द्वारा कराए गए उजरती कार्य की मात्रा में तेजी से गिरावट आई है । हुबेई ने यह तर्क दिया है कि कंपनी अपने खुद के उत्पादन तथा उजरती कार्य पर उत्पादन हेतु पृथक क्षमताएं रख सकती है । यह स्पष्ट किया जाता है कि उजरती कार्य आधार पर उत्पादन करवाने के लिए कंपनी ने क्षमताएं स्थापित नहीं की हैं । कराए गए उजरती कार्य हेतु क्षमता उपयोग का प्रश्न नहीं उठता है । घरेलू उद्योग ने उजरती कार्य के बारे में पृथक सूचना उपलब्ध कराई है ।
 - जहां तक उत्पादन लागत का संबंध है, यह अनुरोध किया जाता है कि प्राधिकारी के लिए किए गए वास्तविक व्यय पर विचार करना अपेक्षित होता है । उजरती कार्य में उत्पादन लागत और खुद के विनिर्माण में उत्पादन लागत की तुलना द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि संगत अवधि के दौरान उत्पादन की प्रति इकाई लागत का वास्तविक प्रचालनों पर सीधे प्रभाव पड़ता है । यदि खुद का कोई उत्पादन नहीं हुआ है तो कंपनी किए जा रहे निर्धारित व्यय और वर्तमान में खुद के उत्पादन हेतु प्रभार को उजरती कार्य के अंतर्गत और विलोमतः वहन किया गया होगा । अतः उजरती कार्य पर किए गए उत्पादन और खुद के उत्पादन के बीच तुलना द्वारा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता ।
 - जहां तक संभावित अक्षमताओं या कम क्षमताओं के कारण संभावित उच्च लागत का संबंध है, यह तर्क निराधार है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अक्षमता विद्यमान है । प्राधिकारी कृपया अनुमान और कल्पना के आधार पर कार्रवाई न करें । चूंकि इस विवरण की साक्ष्य द्वारा पुष्टि नहीं की गई है इसलिए इसे अस आधार पर ही अस्वीकृत कर लिया जाए ।

- कंपनी का क्षमता उपयोग इतना कम नहीं है और न ही कम क्षमता उपयोग के कारण उत्पादन लागत असामान्य रूप से अधिक है। इस संबंध में वरचाऊ लेबोरेटरीज लि. बनाम वित्त मंत्रालय 2002 (141) ई एल टी 60 (ट्रि - डेल); मै. निप्पान जिओन कंपनी लिमिटेड, जापान व अन्य बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (1997 (96) ई एल टी 126 (टी)); ऋषिरूप पालिमर्स प्रा. लि बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2000 (119) ई एल टी 157 (ट्रिब्युनल) में सेस्टेट के निर्णयों का उल्लेख किया गया है।

- कीमत प्रभाव - कीमत पर कोई प्रभाव न पड़ने के बारे में हुबेई के दावे को अस्वीकृत किया जाए। प्रथमतः घरेलू उद्योग पहले से ही भारी वित्तीय घाटा (शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप के कारण) उठा रहा है। वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को हुए वित्तीय घाटे में आगे और वृद्धि होगी। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत डी पी सी ओ स्तर से कम है। चूंकि आयातों की पहुंच कीमत (क) उत्पादन लागत, (ख) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत, (ग) डी पी सी ओ कीमत (घ) क्षति रहित कीमत से कम है इसलिए इसका तात्पर्य यह है कि पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति का घरेलू उद्योग पर प्रतिकूल कीमत प्रभाव पड़ेगा।

यह भी उल्लेखनीय है कि 2008-09 में आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि हुई तथा आयात मात्रा में गिरावट आई (यह दोहराया जाता है कि अधिकांश आयात अग्रिम लाइसेंस पर किए गए हैं और इसलिए घरेलू उद्योग के निर्यात ऑर्डरों पर आयात नहीं हुए हैं)। इसके अलावा, आयातों की पहुंच कीमत में 2009-10 में गिरावट आई और आयात मात्रा में वृद्धि हुई। जांच अवधि में आयात कीमत में मामूली वृद्धि हुई और यह तब भी जांच अवधि में प्रचलित कीमत से कम थी। वर्ष 2009-10 में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में वृद्धि से वर्ष 2008-09 में आयात कीमत में वृद्धि के प्रभाव का पता चलता है। यद्यपि, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में वर्ष 2009-10 में आयात कीमत में गिरावट आई तथापि, वह तब भी 2007-08 में प्रचलित बिक्री कीमत से अधिक थी।

प्राधिकारी द्वारा जांच

39. जहां तक क्षति के सभी कारकों में सुधार के बारे में दिए गए तर्कों का संबंध है, इन पर नीचे उचित कार्यवाई की गई है :
40. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उसने क्षति अवधि के दौरान क्षति संबंधी आंकड़ों की जांच कर उनका मूल्यांकन करने की सुसंगत परंपरा को अपनाया है। तथापि, किसी निर्णायक समीक्षा जांच में प्राधिकारी यह निर्धारण करते हैं कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और परिणामी क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।
41. प्राधिकारी ने तथ्यों और हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए क्षति मापदंडों की निम्नानुसार तथ्यपरक जांच की है:

42. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में यह उपबंध है कि क्षति के निर्धारण में (क) पाटित आयातों की मात्रा और समान उत्पाद के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पाटित आयातों की मात्रा और समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव ; तथा (ख) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातकों के परिणामी प्रभाव, दोनों की तथ्यपरक जांच शामिल होगी । पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में पर्याप्त वृद्धि हुई है । जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पाटित आयातों द्वारा भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में अत्यधिक कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट आई है या कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है, जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती ।"
43. वर्तमान क्षति विश्लेषण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों का घरेलू उद्योग पर मात्रात्मक एवं कीमत प्रभावों तथा कीमत और लाभप्रदता पर उसके प्रभाव की जांच की है ताकि क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध, यदि कोई हो, की मौजूदगी की जांच की जा सके ।

मात्रात्मक प्रभाव

मांग का निर्धारण

44. भारत में संबद्ध वस्तु की स्पष्ट खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री और सभी देशों से हुए आयातों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाए । इस संबंध में संगत ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
मांग का निर्धारण	मी.ट.	1,531	1,407	1,802	1,867	1,782
आबद्ध सहित घरेलू उद्योग की बिक्री	मी.ट.	227	234	277	268	175
अन्य भारतीय उत्पादकों की बिक्री	मी.ट.	770	641	757	466	466
अप्रत्याक- चीन जन गण.	मी.ट.	522	506	740	1,133	1,049
आयातक-अन्य देश	मी.ट.					

		12	26	28		92
मांग में बाजार हिस्सा						
घरेलू उद्योग	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
अन्य भारतीय उत्पादक	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14
चीन जन. गण.	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
अन्य देश	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि (वार्षिक)

45. स्पष्ट तौर पर क्षति अवधि के दौरान संबद्ध वस्तु की खपत में वृद्धि हुई है और 2008-09 में मामूली गिरावट आई है (जिसके बारे में मंदी एक वजह होने का दावा किया गया है)। यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग की बिक्री में 2008-09 में गिरावट आई है और 2009-10 में वृद्धि हुई है परंतु बिक्री मात्रा में जांच अवधि में पुनः गिरावट आई है। हालांकि जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों की मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। यद्यपि, जांचोत्तर अवधि में मांग एवं आयातों के बारे में प्रवृत्ति में कोई खास परिवर्तन नहीं देखा गया है, तथापि, जांचोत्तर अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री मात्रा में तेजी से गिरावट आई है।

आयात मात्रा तथा बाजार हिस्सा

46. पाटित आयातों की मात्रा के बारे में प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित होता है कि क्या पाटित आयातों में समग्र रूप में या भारत में उत्पादन या खपत की तुलना में भारी वृद्धि हुई है। इस संबंध में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II (ii) में निम्नानुसार उपबंध है:

"पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय उक्त प्राधिकारी यह विचार करेंगे कि क्या समग्र रूप से या भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों में भारी वृद्धि हुई है।"

47. आयात एवं बाजार हिस्से से संबंधित सूचना निम्नलिखित तालिका में दी गई है।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि

आयातक-चीन जन. गण.	मी.ट.	522	506	740	1,133	1,049
आयातक-अन्य देश	मी.ट.	12	26	28	-	92
कुल	मी.ट.	535	532	769	1,133	1,141
आयातों में बाजार हिस्सा- चीन जन.गण.	%	97.66	95.07	96.31	100.00	91.94
आयातों में बाजार हिस्सा- अन्य देश	%	2.34	4.93	3.69	-	8.06

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि (वार्षिक)

48. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि आधार वर्ष की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा में जांच अवधि के दौरान समग्र रूप में और तुलनात्मक आंकड़ों के रूप में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यही प्रवृत्ति जांचोत्तर अवधि के दौरान आयातों की मात्रा के मामले में देखी गई है।
49. पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद उपर्युक्त स्थिति विद्यमान है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि यदि मैट्रोनिडाजोल का बाजार निष्पक्ष होगा तो वह पाटन के विगत दुष्प्रभावों से उबर गया होता। तथापि, पाटित आयातों की सतत मौजूदगी से वह उस सीमा तक बाजार हिस्सा प्राप्त करने से वंचित हुआ है जिस सीमा तक वह सामान्य परिस्थितियों में प्राप्त कर सकता था। इसके अलावा, अपनी स्थापित क्षमताओं की सीमा तक उत्पादन करने के लिए घरेलू उद्योग की अक्षमता से भी घरेलू उद्योग के निष्पादन पर पाटित आयातों के प्रतिकूल प्रभाव का पता चलता है। यदि लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने की अनुमति दी जाती है तो पाटित आयातों की मात्रा में आगे और वृद्धि होने की संभावना है।

कीमत प्रभाव

कीमत कटौती

50. जहां तक कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव का संबंध है, प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में

पाटित आयातों के कारण कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से कीमत में अन्यथा गिरावट आई है अथवा होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर तक बढ़ गई होती। निम्नलिखित तालिका से घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत, पाटित आयातों की पहुंच कीमत और कीमत कटौती का पता चलता है।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
संदर्भ कीमत	रू./किग्रा.	405.06	455.25	480.10	461.61	452.44
निवल बिक्री प्राप्ति	रू./किग्रा.	***	***	***	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	357.83	469.32	432.40	444.05	453.34
कीमत कटौती	रू./किग्रा.	***	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज %	10-20	0-10	10-20	5-15	5-15

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि

- 5.1. यह देखा जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के साथ ही संबद्ध वस्तु के आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत से कम है जिससे कीमत में भारी कटौती हो रही है। इस मामले में लागू पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के स्वरूप में है जो घरेलू उद्योग की निवल बिक्री प्राप्ति से कम है। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग की कीमत में आगे और कटौती होने की संभावना है। आगे यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से काफी कम है जिससे अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री का पता चलता है।

घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले आर्थिक मापदंड

52. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में प्राधिकारी के लिए संबद्ध घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करना यह अपेक्षित है जिसमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्से, उत्पादकता, निवेश पर आय या क्षमता उपयोग में वास्तविक एवं संभावित गिरावट सहित उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले संकेतकों; घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा; नकद प्रवाह, माल सूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले समस्त संगत आर्थिक कारकों और संकेतकों का मूल्यांकन शामिल है। तदनुसार, घरेलू उद्योग के विभिन्न आर्थिक मापदंडों का निम्नानुसार विश्लेषण किया गया है :

बिक्री, क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग

53. बिक्री, क्षमता, उत्पादन तथा क्षमता उपयोग के बारे में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नानुसार रहा है:

	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि
सकल मांग	मी.ट.	1,531	1,407	1,802	1,867	1,782
क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100	100
स्वयं के उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
ऋण के तहत उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
कुल उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	105	114	85	113
क्षमता उपयोग (स्वयं के उत्पाद)	%	***	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	78	116	116	161
आबद्ध खपत सहित घरेलू बिक्री	मी.ट.	227	234	277	268	175

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि (वार्षिक)

54. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान मांग में समग्र वृद्धि होने के बावजूद जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में गिरावट आई है। यहां तक कि अधिक उत्पादन करने की क्षमता के बावजूद जांच अवधि में घरेलू उद्योग के उत्पादन में गिरावट आई है। घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि इस बात पर विचार करते हुए (क) कि सरकार ने संबद्ध वस्तु पर पूर्व में पाटनरोधी शुल्क लगाया था और (ख) संबद्ध वस्तु की मांग बढ़ रही है, उसके निष्पादन में सुधार होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग द्वारा अपने उत्पादन में बेतहाशा वृद्धि की जानी चाहिए थी परंतु वह संबद्ध देश के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत पाटित संबद्ध वस्तु की सतत मौजूदगी के कारण मांग में वृद्धि के बावजूद अपने उत्पादन को नहीं बढ़ा सका। अतः यह देखा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने और भारत में संबद्ध वस्तु की मांग में समग्र वृद्धि होने के बावजूद घरेलू उद्योग अपने उत्पादन और बिक्री में सुधार करने तथा संपूर्ण सीमा तक अपनी क्षमता का उपयोग करने में समर्थ नहीं रहा है। यह भी देखा जाता है कि जांचोत्तर अवधि में यद्यपि, क्षमता उपयोग में सुधार हुआ है तथापि, घरेलू बिक्री में गिरावट आई है।

बाजार हिस्सा

55. यह देखा जाता है कि क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. का बाजार हिस्सा काफी अधिक रहा है। आधार वर्ष से लेकर जांच अवधि तक चीन जन.गण. के बाजार हिस्से में लगभग 30% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, जहां चीन जन.गण. के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, वहीं क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के हिस्से में गिरावट आई है, जैसा कि निम्नलिखित से स्पष्ट हो जाएगा:

भाग में बाजार हिस्सा	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि *
चीन जन.गण.	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
अन्य देश	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16
घरेलू उद्योग	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
अन्य भारतीय उत्पादक	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14

*जांचोत्तर अवधि अर्थात् जन.-जून, 2011 की अवधि

लाभ/हानि, नकद प्रवाह, लगाई गई पूंजी पर आय

56. घरेलू उद्योग के लाभ, बिक्री कीमत, लगाई गई पूंजी पर आय से संबंधित सूचना निम्नानुसार है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-	2009-10	जांच अवधि
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	117	117
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	114	105
घरेलू बिक्री पर लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-86	-143	-111
व्याज तथा कर पूर्व लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-86	-143	-112
नकद लाभ	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-85	-143	-111
नियोजित पूंजी पर आय	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	-66	-75	-60

57. प्राधिकारी नोट करते हैं कि यद्यपि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री लागत में 5% की वृद्धि हुई है, तथापि, आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में बिक्री कीमत में 17% की वृद्धि हुई है। तथापि, घरेलू उद्योग घाटे में रहा है और वस्तुतः इस घाटे में आधार वर्ष की तुलना में जांच अवधि में वृद्धि हुई है।

58. निम्नलिखित तालिका से जांच अवधि तथा जांचोत्तर अवधि में विचाराधीन उत्पाद की बिक्री लागत, बिक्री कीमत, पहुंच मूल्य, लाभ/हानि के ब्यौरों का पता चलता है।

विवरण	इकाई	जांच अवधि	जांचोत्तर अवधि*
बिक्री की लागत	रु./किग्रा.	***	***
बिक्री कीमत	रु./किग्रा.	***	***
आयातों की पहुंच कीमत	रु./किग्रा.	444.05	453.34
लाभ/हानि	रु./किग्रा.	***	***
	लाख रुपए	***	***
घरेलू उद्योग द्वारा आयातों की पहुंच कीमत के साथ बिक्री कीमत की बराबरी किए जाने की स्थिति में लाभ/हानि	रु./किग्रा.	***	***
	लाख रुपए	***	***

59. उपर्युक्त आंकड़ों के अवलोकन से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत वसूलने में समर्थ नहीं रहा है और यदि वह शुल्क समाप्त किए जाने के कारण आयातित वस्तु के पहुंच मूल्य के बराबर कीमत पर संबद्ध वस्तु की बिक्री करेगा तो घरेलू उद्योग को और अधिक वित्तीय घाटा होगा। यदि उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होती है तो निवेश पर आय और नकद लाभ की स्थिति और अधिक खराब हो जाएगी। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की कीमत पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

मालसूची

60. निम्नलिखित तालिका में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की मालसूची के ब्यौरे दिए गए हैं।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
-------	------	---------	---------	---------	-----------

		08	09	10	अवधि
औसत स्टॉक	मी.ट.	12	12	15	53

61. उपर्युक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि जहां आरंभिक दो वर्षों के दौरान मालसूची का स्तर स्थिर रहा है, वहीं उसमें जांच अवधि के दौरान तेजी से वृद्धि हुई है जिससे यह पता चलता है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपने स्टॉक को समाप्त करने की स्थिति में नहीं था।

रोजगार, मजदूरी तथा उत्पादकता

62. निम्नलिखित तालिका से क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के रोजगार, प्रति कर्मचारी मजदूरी और उत्पादकता का पता चलता है।

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	102	102
मजदूरी	लाख रुपए	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	160	89
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	मी.ट	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	77	115	114

63. यह देखा जाता है कि घरेलू उद्योग एक बहु उत्पाद कंपनी है। समूची क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या लगभग समान रही है। हालांकि 2009-10 में मजदूरी लगभग में वृद्धि हुई थी, तथापि उसमें जांच अवधि में गिरावट आई थी। इसी प्रकार जहां प्रति कर्मचारी उत्पादकता में 2009-10 में वृद्धि हुई, वहीं जांच अवधि में उसमें मामूली गिरावट आई।

64. निम्नलिखित तालिका में क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की वृद्धि दर्शायी गई है:

विवरण	इकाई	2007-08	2008-09	2009-10	जांच अवधि
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि					
उत्पादन (मी.ट.)	%	-	5	9	-25
बिक्री मात्रा (मी.ट.)	%	-	10	20	-2
बिक्री कीमत (रू./किग्रा.)	%	-	13	4	-1
बिक्री की लागत (रू./किग्रा.)	%	-	-0.13	14	-7
औसत स्टॉक (मी ट.)	%	-	1	27	243
नियोजित पूंजी पर आय (% नकारात्मक)	%	-	54	-14	24

65. घरेलू उद्योग ने मात्रा और कीमत मापदंडों दोनों के संबंध में अत्यधिक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की है। हालांकि बिक्री मात्रा, उत्पादन मात्रा और लाभप्रदता जैसे अधिकांश मापदंडों में 2009-10 में वृद्धि सकारात्मक थी, तथापि इनमें जांच अवधि के दौरान भारी गिरावट आई।

पाटन मार्जिन की मात्रा

66. यह देखा जाता है कि पाटन मार्जिन न केवल न्यूनतम सीमा से अधिक है अपितु काफी अधिक भी है। शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन जारी रहने की संभावना है।

क्षति के बारे में निष्कर्ष

67. उपर्युक्त को देखते हुए यह नोट किया जाता है कि:
- क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. से आयातों में वृद्धि हुई है और इसका अत्यधिक हिस्सा बना हुआ है;
 - भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में पाटित आयातों की मात्रा काफी अधिक है;
 - चीन जन.गण. से सबद्ध वस्तु का सत पाटन हो रहा है और पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन के जारी रहने और उसमें वृद्धि होने की संभावना है।

- iv. मांग में वृद्धि के बावजूद घरेलू उद्योग जांच अवधि के दौरान अपनी क्षमता का संपूर्ण उपयोग करने तथा अपनी घरेलू बिक्री को बढ़ाने में समर्थ नहीं रहा है ।
- v. घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में 2009-10 तक वृद्धि हुई और जांच अवधि में गिरावट आई । समूची क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती अत्यधिक सकारात्मक रही है;
- vi. उत्पादन, घरेलू बिक्री, बाजार हिस्से, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह आदि के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट आई है जबकि इनमें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद सामान्यतः सुधार होना चाहिए था;

क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना

घरेलू उद्योग के अनुरोध

68. घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि किसी समीक्षा जांच में प्राधिकारी के लिए लागू शुल्क समाप्त होने के संभावित परिणाम की जांच करना अपेक्षित होता है । ऐसी स्थिति हो सकती है जिसमें पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग के वर्तमान निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हुआ हो । ऐसे मामले में प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग के निष्पादन में हुए सुधारों के बारे में जांच के अलावा, घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित होता है । इसके अलावा, जहां घरेलू उद्योग को पहले से क्षति हो रही है, वहां प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित होता है कि क्या संबद्ध देश से संभावित पाटन के कारण घरेलू उद्योग को क्षति होने या उसमें और गंभीरता आने की संभावना है । घरेलू उद्योग ने थाई एक्रीलिक फाइबर कंपनी लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (अपील संख्या ए डी/4/2009 में अंतिम आदेश संख्या एडी/5/2010 (पीबी), दिनांक 30.4.2010) के मामले में सेस्टेट के निर्णय का आगे उल्लेख किया है जिसमें माननीय न्यायाधिकरण ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय दिया कि "जहां तक क्षति निर्धारण का संबंध है यदि पाटनरोधी शुल्क का अपेक्षित प्रभाव पड़ता है तो पाटनरोधी शुल्क लागू होने की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार होने की आशा की जाएगी । अतः यह निर्धारण कि क्या पाटन आयातों के अनुमानित स्तर, कीमत और घरेलू उत्पादकों पर प्रभाव के आधार पर भविष्य में क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने के बारे में विरोध तथ्यात्मक विश्लेषण के आधार पर किया जाएगा । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या शुल्क समाप्त किए जाने पर घरेलू उद्योग को पुनः वास्तविक क्षति होने की संभावना है ।"
69. जहां तक क्षति जारी रहने की संभावना का संबंध है, घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी का ध्यान सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9(क) 5 और डब्ल्यू टी ओ करार के अनुच्छेद 11.3 की ओर आकर्षित किया है । यह अनुरोध किया गया है कि निर्णायक समीक्षा का प्रयोजन इस बात का निर्धारण करना होता है कि क्या उपाय समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है या नहीं । समीक्षा जांच में प्राधिकारी के लिए इस बात की जांच करना अपेक्षित है कि लागू शुल्क समाप्त किए जाने का परिणाम क्या होगा । यह एक संभावनाजनित जांच होती है । अतः घरेलू उद्योग का वर्तमान निष्पादन केवल उस सीमा तक संगत है जिस सीमा तक सतत क्षति की मौजूदगी

या अन्यथा कापता चलता है । वर्तमान निष्पादन में सुधार लागू पाटनरोधी शुल्क के कारण हो सकता है और ऐसे मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करना अपेक्षित होता है । यदि प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को कोई सतत क्षति नहीं हुई है तो प्राधिकारी को लागू पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति की पुनरावृत्ति की संभावना की जांच करनी चाहिए और यह कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग ने जांच अवधि के दौरान प्रतिकूल निष्पादन दर्ज किया है । अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को क्षति होने की प्रबल संभावना है ।

70. यद्यपि, पूर्वोक्त से इस बात की पुष्टि होती है कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क की अवधि में आगे विस्तार किया जाना चाहिए । तथापि, अनुरोध है कि प्रतिवादी निर्यातकों को इस बात की पुष्टि करनी चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है । निर्यातक ने प्राधिकारी को इस आशय की सूचना याचिका में पहले ही प्रदान कर दी है कि शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने की कोई संभावना नहीं है । जब तक निर्यातक इस सूचना के आधार पर इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन जारी रहने, उसमें तेजी आने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना नहीं है, तब तक यह माना जाना चाहिए कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और परिणामी क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने या उसमें तेजी आने की संभावना है । इस संदर्भ में समीक्षा जांचों के बारे में सेस्टेट के कुछ निर्णयों का हवाला दिया गया है । इन निर्णयों से यह स्पष्ट होता है कि निम्नलिखित स्थितियों में अकाट्य निष्कर्ष यह होगा कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन से घरेलू उद्योग को क्षति होती ।

(क) विद्यमान पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती सकारात्मक है ;

(ख) यदि किसी विशेष देश से कीमत कटौती नकारात्मक है तो प्राधिकारी के लिए इस बात पर विचार करना अपेक्षित है कि क्या आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत हासकारी अथवा न्यूनकारी प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ग) आयतों की पहुंच कीमत न केवल घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है अपितु घरेलू उद्योग की क्षति रहित कीमत से भी कम है ।

घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि वर्तमान मामले में उपर्युक्त स्थितियां विद्यमान हैं और इसलिए पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना रहेगी ।

71. इस बात की पुष्टि करने के लिए घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित का उल्लेख किया है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की प्रबल संभावना है ।

72. मूल अवधि तथा परवर्ती अवधियों के बीच आयात मात्रा में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा, संबद्ध देश में अतिरिक्त उत्पादन क्षमताएं हैं जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकेगा कि चीन के कुछ उत्पादकों की उत्पादन क्षमताएं काफी अधिक हैं:

क्र.सं.	चीन जन.गण. में उत्पादक	क्षमता/आपूर्ति क्षमता (प्रति वर्ष मी.ट.)
1	हुबेई होंगयुआन फॉरस्युटीकल्स क. लि.	5,000
2	हेफेई टीएनजे कैमिकल इंडस्ट्री क. लि.	5,000
3	हेंगझोऊ तियानकाई इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट क. लि.	5,000
4	हेंगझोऊ रूईजियांग कैमिकल क. लि.	1,000
5	चाइना फूडफार्म ग्रुप क. लि.	7,200
6	शिजियाझुआंग विटूर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग क. लि.	500

73. चीन के कुछ उत्पादकों के पास उपलब्ध ज्ञात क्षमताओं (लगभग 24,000 मी.ट.) पर विचार करते हुए 2000 मी.ट से कम की भारतीय मांग की पाटित आयातों द्वारा समग्र पूर्ति आसानी से की जा सकती है। यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किया जाता है तो इस बात की प्रबल संभावना है कि समूची भारतीय मांग की पूर्ति चीन के उत्पादकों द्वारा की जा सकती है। संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों की ओर से सतत पाटन हो रहा है जो शुल्क समाप्त किए जाने पर और अधिक मात्रा में होगा। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में भारी वृद्धि होने की संभावना है। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन में वृद्धि जारी रहने की संभावना है।

74. **भारतीय बाजार की कीमत आकर्षकता:** आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है। यह उल्लेखनीय है कि चीन से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की वर्तमान और संभावित बिक्री कीमत से कम है। अतः शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादक भारतीय बाजार को आसान लक्ष्य बनाएंगे इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा बाजार में उचित कीमत वसूल किए जाने की स्थिति में चीन का उत्पाद सस्ता होने की संभावना है। पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन के उत्पादक अपनी लाभप्रदता बढ़ाने और भारतीय आयातकों और ग्राहकों को आकर्षक कम कीमत की पेशकश करने में समर्थ हो जाएंगे ताकि ये भारतीय उत्पादकों के बजाए चीन के निर्यातकों पर आश्रित हो सकें।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के कार्यों की वास्तविक स्थिति

75. क्षति की वास्तविक स्थिति क्षति के बारे में किए गए उपर्युक्त अनुरोधों से स्पष्ट हो जाती है। पाटनरोधी शुल्क का मौजूदा स्वरूप कारगर नहीं रहा है। इसके अलावा, कोई राहत न दिए जाने की स्थिति में क्षति जारी रहने की संभावना है।

76. घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि क्षति अवधि के दौरान चीन जन.गण. द्वारा धारित बाजार हिरसा न केवल पर्याप्त रहा है अपितु काफी उच्च भी रहा है । लागू शुल्क के बावजूद चीन के हिस्से में गिरावट नहीं आई है । इसके विपरीत जांच अवधि में पाटित आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है और वह जांचोत्तर अवधि में भी उसी स्तर पर रहा है ।
77. आगे यह बताया गया है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा और मूल्य में भारी वृद्धि हुई है और इस वृद्धिकारी प्रवृत्ति से यह पता चलता है कि शुल्क समाप्त किए जाने पर पाटन में आगे और तेजी आएगी ।
78. यह भी देखा जा सकता है कि जिस दर से चीन से आयात में वृद्धि हो रही है, वह अन्य देशों की वृद्धि से काफी अधिक है । वस्तुतः जांच अवधि में अन्य देशों से आयात शून्य है । इसके अलावा जांचोत्तर अवधि में चीन जन.गण. से आयात उसी स्तर पर और पाटित कीमतों पर हुए हैं । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग की स्थिति अत्यधिक कमजोर हो जाएगी ।
79. **संबद्ध देश के उत्पादकों और निर्यातकों का निर्यात अभिमुखीकरण:** घरेलू उद्योग ने यह बताया है कि चीन जन.गण. के निर्यातक विश्व भर में सर्वाधिक निर्यातान्मुखी हैं । चीन की कंपनियों का निर्यात का प्रतिशत 30%-100% के बीच है । अतः इस चरण पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन और क्षति में अत्यधिक उच्च स्तर पर पुनरावृत्ति होने की संभावना है ।
80. **लागू पाटनरोधी शुल्क के बिना कीमत कटौती** पाटनरोधी शुल्क के बिना आयातों के पट्टी कीमत की तुलना घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत के साथ करने पर यह देखा जाएगा कि अत्यधिक कीमत कटौती मौजूद है । अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की प्रबल संभावना मौजूद है । आंकड़ों से यह देखा जा सकता है कि बेंचमार्क पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग की वर्तमान बिक्री कीमत से काफी कम है ।
81. **घरेलू उद्योग की सुभेद्यता:** घरेलू उद्योग ने आगे यह उल्लेख किया है कि उसे पिछले कुछ समय से पाटित आयातों के कारण क्षति हो रही है जैसी कि मूल जांच और पूर्ववर्ती निर्णायक समीक्षा जांच में पुष्टि की गई है । यह भी अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग पाटित आयातों के कारण क्षति सहने के लिए आसान है । संबद्ध देश से आयातों की मात्रा और पाटन मार्जिन के वर्तमान स्तर की वजह से इस बात की प्रबल संभावना बन गई है कि शुल्क समाप्त किए जाने से इस तथ्य को देखते हुए कि संबद्ध देश में अत्यधिक संभावनाएं हैं । भारतीय बाजार में संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के पाटन में तेजी आएगी ।

82. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 3.5 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के पैरा V का हवाला दिया है। यह तर्क दिया गया है कि कारणात्मक संबंध की पुष्टि मूल जांच में की जा चुकी है। वर्तमान समीक्षा जांच में प्राधिकारी को इस बात की जांच करनी है कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। अतः इस बात की जांच करने में कि क्या पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है, ऐसा विश्लेषण शामिल होगा कि सकारात्मक जांच परिणाम तभी दर्ज किया जाएगा यदि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने पर क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। इससे यह सिद्ध होता है कि क्षति के बारे में सकारात्मक जांच परिणाम तभी दर्ज किया जाएगा जब पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने और क्षति के पुनरावृत्ति होने या उसके जारी रहने के बीच संबंध हो। पाटन जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना और क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है जैसा कि निम्नलिखित अनुरोधों से देखा जा सकेगा।

क. पाटित कीमत पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य: - घरेलू उद्योग चीन जन गण से देश में हो रहे पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना कर रहा है। क्षति अवधि में भारी मात्रा में आयात हुए हैं और जांच अवधि में अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

ख. मांग में कमी: - इन अनुरोधों के साथ संलग्न क्षति विवरण में समूची क्षति अवधि के दौरान विचाराधीन उत्पाद की मांग के बारे में सूचना दी गई है। यह देखा जाता है कि वर्ष 2008-09 को छोड़कर समूची क्षति अवधि में विचाराधीन मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है। अतः मांग में कमी ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन: - विचाराधीन उत्पाद से संबंधित खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की पद्धति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा: - ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी विकास: - उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और न ही भविष्य में कोई परिवर्तन होने की संभावना है। अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का कारक नहीं है।

च. निर्यात निष्पादन: - याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना पर ही संभव सीमा तक क्षति के निर्धारण हेतु विचार किया गया है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्रीत अन्य उत्पादों का निष्पादन: - याचिकाकर्ता एक बहु उत्पाद कंपनी है। तथापि, सूचना विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्रदान की गई है।

83. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि एक बार यह प्रदर्शित किए जाने पर कि (क) पाटित आयातों का मात्रात्मक और कीमत प्रभाव पड़ा है, और (ख) पाटित आयातों के कारण क्षति हुई है, निष्कर्ष निकालने के लिए जो एकमात्र आधार बचता है वह यह है कि पाटित आयातों के कारण क्षति कारणोत्तर विश्लेषण की वजह से हुई है। चूंकि सूचीबद्ध ज्ञात अन्य कारकों से इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि क्षति इन अन्य कारकों से हुई है, इसलिए अकाट्य निष्कर्ष यह निकलता है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण हुई है।

प्राधिकारी द्वारा जांच

84. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का पाटन जारी है जिससे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है। आगे यह नोट किया जाता है कि लागू पाटनरोधी शुल्क के बावजूद घरेलू उद्योग लाभ कमाने में समर्थ नहीं रहा है। कीमत में अत्यधिक कटौती और अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री हुई है तथा पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग आयात कीमत से तुलनीय कीमत पर अपना उत्पाद बेचने के लिए बाध्य होगा जिससे भारी वित्तीय घाटा होगा तथा घरेलू उद्योग के लिए निवेश पर आय में आगे और गिरावट आएगी। इसके अलावा, संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने की पर्याप्त क्षमताएं हैं। अतः पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में संबद्ध देश से सतत पाटन जारी रहने और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति होने की संभावना है।

ज. कारणात्मक संबंध

85. प्राधिकारी ने किसी निर्णायक समीक्षा जांच में कारणात्मक संबंध के महत्व और प्रासंगिकता के बारे में किए गए अनुरोधों की जांच की है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम की धारा 9 क (5) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पाटन और क्षति की संभावना एवं शुल्क को जारी रखने की जरूरत की जांच करना अपेक्षित होता है। तदनुसार पैरा 67 और 84 में किए गए उल्लेखानुसार प्राधिकारी ने यह निष्कर्ष निकाला है कि पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और पाटनरोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में इनके जारी रहने और क्षति पहुंचाने की संभावना है। इसके होते हुए भी प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या पाटनरोधी नियमों में सूचीबद्ध अन्य मापदंडों से घरेलू उद्योग को क्षति हुई है।

क. पाटित कीमत पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और मूल्य: - घरेलू उद्योग चीन जन गण से देश में हो रहे पाटित आयातों के कारण क्षति का सामना कर रहा है। क्षति अवधि में भारी मात्रा में आयात हुए हैं और जांच अवधि में अन्य देशों से कोई आयात नहीं हुआ है।

ख. मांग में कमी: - प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्ष 2008-09 को छोड़कर समूची क्षति अवधि में विचाराधीन मांग में सकारात्मक वृद्धि हुई है। अतः मांग में कमी ऐसा कोई संभावित कारण नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती हो।

ग. खपत की पद्धति में परिवर्तन: - विचाराधीन उत्पाद से संबंधित खपत की पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। खपत की पद्धति में परिवर्तन से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना नहीं है।

घ. विदेशी और घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार और उनके बीच प्रतिस्पर्धा: - ऐसा कोई व्यापार प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ प्रौद्योगिकी विकास: - उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अतः प्रौद्योगिकी विकास क्षति का कारक नहीं है।

च. निर्यात निष्पादन: - याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद का निर्यात किया है। तथापि, घरेलू बिक्री से संबंधित सूचना पर ही संभव सीमा तक क्षति के निर्धारण हेतु विचार किया गया है।

छ. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्रीत अन्य उत्पादों का निष्पादन: - याचिकाकर्ता एक बहु उत्पाद कंपनी है। तथापि, सूचना विचाराधीन उत्पाद के बारे में प्रदान की गई है।

ज. उत्पादकता : यह देखा गया है कि क्षति अवधि के दौरान प्रति दिन घरेलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि हुई है और इसलिए यह घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कोई कारण नहीं है।

झ. डी पी सी ओ कीमत : प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्द्र सरकार ने 4.8.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1944 (अ) के तहत मैट्रोनिडाजोल की अधिकतम बिक्री कीमत 526 रूपए प्रति किग्रा. तय की है। अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग को आंशिक क्षति सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम बिक्री कीमत के कारण हुई है।

क्षति की मात्रा और क्षति मार्जिन:

86. प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु की क्षति रहित कीमत की तुलना जांच अवधि के दौरान क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से निर्यातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। इस प्रकार की गई तुलना के अनुसार क्षति मार्जिन निम्नानुसार बनता है:

विवरण	इकाई	मे. हुबेई होंगयुआन फार्मास्यूटीकल कं., लि.	चीन जन.गण. - अन्य
एन आई पी	रू./किग्रा.	***	***

पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	***	***
क्षति मार्जिन	रू./किग्रा.	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज %	60 - 70	80 - 90

87. प्राधिकारी नोट करते हैं कि केन्द्र सरकार ने 4.8.2008 की अधिसूचना सं. का.आ. 1944 (अ) के तहत मैट्रोनिडाजोल की अधिकतम बिक्री कीमत 526 रूपए प्रति किग्रा. तय की है। चूंकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति आंशिक रूप से सरकार द्वारा अधिसूचित अधिकतम बिक्री कीमत के कारण हुई है, इसलिए प्राधिकारी ने उस क्षति मार्जिन की गणना के प्रयोजनार्थ इस कीमत पर विचार किया है जो पाटित आयातों के कारण बन सकता है।

विवरण	इकाई	मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं., लि.	चीन जन.गण. - असहयोगी निर्यातक/उत्पादक
डी पी सी ओ कीमत	रू./किग्रा.	526	526
पहुंच कीमत	रू./किग्रा.	***	***
क्षति मार्जिन	रू./किग्रा.	***	***
क्षति मार्जिन	%	***	***
क्षति मार्जिन	रेंज %	10 - 20	25 - 35

ट. निष्कर्ष

88. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए तर्कों, प्रदत्त सूचना और किए गए अनुरोधों तथा उपर्युक्त जांच परिणाम में यथा दर्ज प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और पाटन जारी रहने और परिणामी क्षति होने की स्थिति के बारे में उपर्युक्त विश्लेषण तथा पाटन एवं क्षति जारी रहने/उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना के आधार पर प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु भारतीय बाजार में पाटित कीमत पर प्रवेश कर रही है और पाटन मार्जिन काफी अधिक है। यह देखा जाता है कि मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के बावजूद भारत को संबद्ध वस्तु का निर्यात पाटित कीमतों पर जारी है। यह नोट किया जाता है कि इस समय भी अर्थात् जब पाटनरोधी शुल्क लागू है, कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री की मात्रा काफी अधिक है। यदि घरेलू उद्योग इसकी बराबरी करने का प्रयास करता है तो कीमत मापदंडों पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। विकल्पतः मात्रात्मक मापदंडों को भी क्षति होगी, अतः वर्तमान पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने की अनुमति देने की स्थिति में

घरेलू उद्योग को हुई क्षति की पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आगेक यह नोट किया जाता है कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार पाटनरोधी शुल्क की अवधि में आगे और विस्तार करने और उसकी राशि में संशोधन करने की जरूरत है।

ठ. सिफारिशें

89. उपर्युक्तानुसार निष्कर्ष निकालने के बाद प्राधिकारी का मत यह है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के बारे में पाटनरोधी शुल्क की अवधि को बढ़ाने और उसकी राशि में संशोधन करना अपेक्षित है जैसा कि निम्नलिखित तालिका में उल्लेख किया गया है।

90. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी पाटन मार्जिन तथा क्षति मार्जिन जो भी कम हो के बराबर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके। प्राधिकारी नोट करते हैं कि पिछले 10 वर्षों से इस उत्पाद हेतु पाटनरोधी शुल्क संदर्भ कीमत के आधार पर रहा है परंतु घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति अत्यंत नाजुक बनी हुई है और वह घाटे में चल रहा है। स्पष्टतः शुल्क का संदर्भ स्वरूप कारगर नहीं रहा है अतः मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि निर्धारित स्वरूप के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करना उचित होगा। तदनुसार, संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से निम्नलिखित तालिका के कॉलम 8 में दी गई राशि के बराबर पाटनरोधी शुल्क लागू करने की सिफारिश करना उचित होगा।

शुल्क तालिका

क्र.सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष	वस्तु विवरण	उद्गम का देश	निर्यात का देश	उत्पादक	निर्यातक	पाटन मार्जिन अम.डॉ./कि ग्रा.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	29332920	मेट्रोनिडाजोल	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं., लि.	मै. हुबेई होंगयुआन फार्मास्युटीकल कं., लि.	1.49
2.	29332920	मेट्रोनिडाजोल	चीन जन.गण.	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2.57
3.	29332920	मेट्रोनिडाजोल	चीन जन.गण.	कोई	कोई	कोई	2.57

4.	29332920	मेट्रोनिडाजोल	कोई	चीन जन.गण.	कोई	कोई	2.57
----	----------	---------------	-----	------------	-----	-----	------

91. इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आकलनीय मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3, 3क, 8ख, 9 और 9क के अंतर्गत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर समस्त सीमाशुल्क शामिल होंगे।

92. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी।

विजयलक्ष्मी जोशी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th June, 2012

Subject : Sunset Review of anti-dumping duty imposed concerning imports of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR—Final Findings.

A. BACKGROUND

No. 15/18/2010-DGAD.—Whereas having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (herein after referred to as the AD Rules), the definitive anti-dumping duty was originally recommended vide notification No.17/1/99-DGAD dated 14th July 2000 on import of 'Metronidazole' (hereinafter referred to as the subject goods) originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as the subject country). Whereas upon a Sunset Review undertaken by the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority), the Authority recommended continuation of definitive Anti-dumping duty vide its notification No.15/9/2003-DGAD dated 5th April 2006 and whereas the Central Government issued its Notification No. 61/2006 – Customs dated 15th June 2006.

2. Whereas M/s Aarti Drugs Ltd. and M/s Unichem laboratories Ltd. (India), have filed a duly substantiated application before the Authority in accordance with the Act and the AD Rules alleging dumping of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR and requested for review and modification & continuation of the anti-dumping duties. The Applicants have claimed that they represent the domestic industry as the other domestic producers of the subject goods have already stopped their production. Thus, as per information available on record, the Applicants account for the total Indian production of the subject goods.

3. And whereupon in accordance with Section 9 A (5) of the Act, read with Rule 23 of AD Rules, the Authority issued a public notice dated 30th May 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the Sunset review investigation to review the need for

continued imposition of duties in force and to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

And whereas, the antidumping duty as notified vide Notification No. 61/2006 Customs dated 15th June, 2006 was extended up to 14th June, 2012 vide notification No 48/2011-Customs dated 15th June, 2011 in terms of Section 9(A)(5) of the Act.

4. It is, however, noted that M/s. Aarti Drugs Limited has imported *** MT of the subject goods under the duty exemption schemes out of the total imports of *** MT during the POI viz. 1st January 2010 till 31st December 2010. It has been contended by them that these imports were necessitated in order to meet their export commitments.

5. Opposing interested party has filed its submissions contending, *inter alia*, that M/s. Aarti Drugs Limited should be excluded from ambit and scope of the domestic industry. The domestic industry has also filed its submission on the subject. Considering the submissions made by the interested parties regarding inclusion/exclusion of M/s. Aarti Drugs Limited, the Authority is of the view that it would be appropriate to exclude M/s. Aarti Drugs Limited from the ambit and scope of the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. As a consequence thereof, M/s. Unichem Laboratories would constitute as the domestic industry, being the only remaining producer of the subject goods and thus satisfy the requirement of Rule 2(b) of the AD Rules.

B. PROCEDURE

6. In this proceeding, the procedure described herein-below has been followed:

- i. The Embassy of the subject country in India was informed about the initiation of the investigation, in accordance with Rule 6(2) of the AD Rules.
- ii. The Authority sent copies of initiation notification dated 30th May 2011 to the Embassy of the subject country, known exporters/producers from the subject country, known importers and other interested parties, and the domestic producers, as per the information available with it. Parties to this investigation were requested to file the questionnaires' responses and make their views known in writing within the prescribed time limit. Copies of the letter and questionnaires sent to the exporters/producers were also sent to the Embassy of the subject country along with a list of known exporters / producers with a request to advise the exporters/ producers from the subject country to respond to the questionnaires within the prescribed time.
- iii. Questionnaires were sent to the following known exporters/producers from the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules to elicit relevant information:

S.N.	Company's Name
1.	M/s Great Chang Import & Export Co., Ltd. Of Shandong, China PR
2.	M/s China National Electronic Imp & Exp Ziamen Co., China PR
3.	M/s Jiangsu Guo Tai International Group Co. Ltd., China PR

4.	M/s Hubei Hongye Medical & Chemical Industry Co. Ltd., China PR
5.	M/s Huanggang Yongan Pharmaceutical Co. Ltd., China PR
6.	M/s Qingdao Dacon Trading Co. Ltd., China PR
7.	M/s Changzhou Good-Job Biochemical Co., Ltd. China PR
8.	M/s Qingdao Dacon Trading Co. Ltd. China PR
9.	M/s Seebio Biotech Inc., China PR
10.	M/s Qingdao Fraken International Trading Co., Ltd., China PR
11.	M/s Jiangxi Dongxu Chemical Technology Co., Ltd, China PR
12.	M/s Shanghai Fine Chemicals Co. Ltd., China PR
13.	M/s Shijiazhuang Viture Import & Export Trading Co., Ltd., China PR
14.	M/s Shandong Mingyuan Imp. & Exp. Co., Ltd, China PR
15.	M/s Guangzhou Shiny Import Export Co. Ltd., China PR
16.	M/s Shijiazhuang Huikangyuan Medicine Company Ltd, China PR

In response thereto, M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. China PR, an exporter/producer from the subject country has filed the questionnaires' response.

- iv. Questionnaires were sent to the following known domestic producers, importers, users and associations of the subject goods in India seeking necessary information:

S.N.	Company's Name
1.	M/s Aarti Drugs Ltd., Mumbai
2.	M/s Unichem Laboratories, Mumbai
3.	M/s Unique Chemicals, Mumbai
4.	M/s Aarey Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Thana, Mumbai
5.	M/s Advent Pharma Pvt. Ltd., Mumbai
6.	M/s Ace Laboratories Ltd., Delhi
7.	M/s Alkem Laboratories Ltd., Mumbai
8.	M/s Amoli Organics Pvt. Ltd., Mumbai
9.	M/s Concept Pharmaceuticals Ltd., Mumbai
10.	M/s Dosch Pharmaceuticals Co., Mumbai
11.	M/s DWD Pharmaceuticals Ltd., Mumbai

12.	M/s Flamingo Pharma Ltd., Mumbai
13.	M/s Indo Pharma, Mumbai
14.	M/s Lark Chemicals (P) Ltd., Mumbai
15.	M/s Litika Pharmaceuticals Ltd., Pune
16.	Maneesh Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Mumbai
17.	M/s Medi Pharma Drug House, Mumbai
18.	M/s Mercury Laboratories Ltd., Mumbai
19.	M/s New Generic Drug House, Mumbai
20.	M/s Panacea Biotec Ltd., New Delhi
21.	M/s Shreeji Bhavan, Mumbai
22.	M/s Shubham Pharmachem (P) Ltd., Mumbai
23.	M/s Smruthi Organics Ltd., Mumbai
24.	M/s Unibios Laboratories Ltd., Mumbai
25.	M/s Unique Pharmaceuticals Labs., Mumbai

- v. In response to the initiation notification,
- vi. The imports data for the period of investigation and preceding three years was called from Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S).
- vii. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented by the interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
- viii. The Authority has examined the information furnished by the domestic producers to the extent possible on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) to analyze the likelihood of continuation/recurrence of injury and to work out the cost of production and the non-injurious price of the subject goods in India so as to ascertain if anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- ix. In accordance with Rule 6(6) of the AD Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a public hearing held on 19th September, 2011. The parties which presented their views in the public hearing were requested to file written submissions of the views

expressed orally. The arguments made in the written submissions received from the interested parties have been considered, wherever found relevant, in the disclosure statement.

- x. The Period of Investigation (POI) for the purpose of the present review is 1st January 2010 to 31st December 2010 (12 months). However, injury analysis shall cover the years 2007-08, 2008-09, 2009-10 & POI. The data beyond POI may also be examined to determine the likelihood of dumping and injury.
- xi. Verification to the extent deemed necessary was carried out in respect of the information & data submitted by the domestic producers and the co-operative exporter/producer from China PR.
- xii. In accordance with the Rule 16 of the AD Rules, the essential facts under consideration before the Authority in the instant investigation were disclosed to the known interested parties. The comments received on the disclosure statement, to the extent considered relevant, have been considered in these findings.
- xiii. Information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- xiv. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has recorded these findings on the basis of the 'facts available'.
- xv. *** In this statement represents information furnished by the interested parties on confidential basis and so considered by the Authority under the AD Rules.

C. Post-Disclosure statement submissions made by interested parties and the Examination thereof

M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. China PR,

7. The following submissions, in brief, have been made by M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. China PR, in response to the Disclosure statement:
 - The petitioner has claimed excessive confidentiality; even volume information has been provided on confidential basis.
 - The Authority has correctly considered DPCO ceiling price for the purpose of working out injury margin. However, such injury margin should be worked out on the basis of existing DPCO ceiling price which is Rs. 514/- per kg.

- Form of measures: Claim of the domestic industry with regard to financial losses because of benchmark form of duty is baseless. Firstly, form of measures (fixed or benchmark) cannot be a reason for such losses under benchmark form of duty because domestic industry continues to get protection up to the level of objectively determined NIP. Assuming but not admitting that the financial losses to domestic industry is on account of form of duty then the obvious question is the why domestic industry was silent for last ten years and did not approach the Authority for review. Further in this case only reference price duty based on DPCO price, be recommended as the subject product prices are controlled by the DPCO, therefore, the Authority is required to benchmark anti-dumping duty in the present case up to the level of as the maximum sales price notified under DPCO 1995.
- In view of significant increase in value of US Dollar after POI and DPCO has also fixed benchmark in INR, it is prayed that definitive duty, if at all required to be imposed, be recommended on the basis of reference price in Indian Rupees.
- Information suppressed by petitioner on account of imports made by ADL: Generally, suppression of such information could have led to the termination of the investigation itself. The obvious question is why domestic industry provided incorrect information to the interested parties in relation to imports by ADL as made under Advance License. Removing ADL data on the grounds of such imports at this stage does not appear to be done as per the rules. In this case, Authority is required to evaluate whether the domestic industry can intentionally mislead the interested parties by disclosing incorrect information.
- Injury determinations: The production of Unichem constitutes 29.36% of Indian production. This means production of Unichem was about 246 MT during the POI which includes Job work production done by ADL out of total Indian production which was 838 MT. It should be noted that ADL plant was closed for 3-4 months during POI due to temporary restrictions imposed by Gujarat Pollution Control Board (GPCB) and this would have resulted in lower Indian production during POI. Unichem is a small producer as their own production would be less than 25% of Indian production during injury period and therefore injury assessment based on Unichem data would not lead to objective analysis and fair determination. Further, domestic industry has claimed that the quantum of job work done by Unichem has steeply declined over the injury period. This means, capacity utilization of Unichem could have been less during injury period (previous years) due to job work done. Therefore, the Authority should consider 100% capacity utilization for determination of NIP to nullify injury, if any, caused to the domestic industry by inefficient utilization of production capacities due to Job work.

Domestic industry

8. The following submissions, in brief, have been made by Domestic industry in response to the Disclosure statement:

- The injury margin should be determined on the basis of non-injurious price determined by the Authority and not on the basis of DPCO price for the following reasons:
 - a) The landed price of imports is materially below DPCO and selling prices of the domestic industry and therefore the low price of imports is preventing the domestic industry from realizing even a price equal to DPCO price. Since the domestic industry is not selling at DPCO price, the domestic industry is not suffering injury because of DPCO price but because of dumped imports.
 - b) The industry has sought enhancement of DPCO price to Rs.672/Kg from the present levels in view of very steep increase in the prices of raw materials after the last fixation of the DPCO price. The request of the industry is under consideration of NPPA.
 - c) The present case is not the first case of a product whose price is notified under DPCO and where the Authority has recommended anti dumping duty. The Authority has never before considered the DPCO price as binding for anti-dumping purposes. Reference has been made to a few final findings notified by the Authority, where the non-injurious price determined by the authority is higher or lower than price notified by DPCO but the Authority has not considered DPCO price for determination of injury margin. Thus, the Authority should not determine injury margin considering DPCO price.
 - d) Under dumping law, the Authority is required to determine "injury to domestic industry". The constitution of industry forming domestic industry might be different in anti-dumping as compared to the constitution of industry for the purpose of NPPA.
 - e) The non-injurious price and injury margin is required to be determined for the investigation period chosen by the Authority. Merely because some DPCO price was prevalent during the period, the same does not imply that this is the non injurious price for the investigation period. The Authority is required to determine injury margin based on non injurious price for the period of investigation. Consideration of any price adopted which is not for this period shall be in contravention of various provisions under dumping law. The Authority is required to follow the non injurious price law.
 - f) It is quite possible where the non injurious price determined by the Authority was lower than the DPCO price and the Authority could not have adopted the higher DPCO price in those cases. By converse, merely because DPCO price is lower, the non injurious price determined cannot be rejected. Principles of fairness and objectivity in determination demand that the Authority should apply the same rationality in the present case.
 - g) The Authority as an Investigating Authority is required to proceed based on objective examination of the data/information and should not substitute the same with subjective considerations.
- With regard to the determination of Normal value and dumping margin, the domestic industry has stated that the methodology adopted for determination of Normal value and Dumping Margin is not known to them and it appears that the constructed Normal value and dumping margin are required to be modified for the reason that the consumption factor, conversion costs, SGA expenses and the finance costs are not

based on 'domestic industry. They have further stated that the Authority should consider only the information of the domestic industry for the POI after verification and not other domestic producer.

- Duties on fixed quantum basis: The product is attracting benchmark form of duty on imports from China. The petitioner requests the authority to kindly recommend fixed form of duty in the present sunset review, expressed as duty US\$/kg for the following reasons:
 - i. Continued injury to the domestic industry – The domestic industry is suffering continued injury from dumped imports for the reason that Authority has fixed benchmark form of duty despite established fact that this form of duty is not sufficient to protect the interests of the domestic industry. The import price is being so reported that the landed price of imports is above the benchmark, consequently no anti-dumping duty is being collected on these imports – whether imports are being reported under duty free or duty paid category.
 - ii. Raw materials prices for the product under consideration keeps fluctuating and accordingly cost of production of the domestic industry and foreign producers also keeps fluctuating. However, the Authority has fixed one benchmark for five years. Thus, the domestic industry is protected with one benchmark in a situation where the raw materials price movement is quite significant. The product prices are directly governed by the input prices and import prices. These are two largest factors deciding prices. However, in view of benchmark price, the foreign producers are able to dump the material despite the anti-dumping duty imposed. The raw material prices have already increased significantly after the investigation period of the present case.
 - iii. It could be argued that the domestic industry could seek Mid Term Review of the anti-dumping duties imposed. However, it is pointed out that the review could have been sought in a situation where there have been significant increases in the raw material prices. It is not a situation where raw material prices have doubled or tripled. It is a situation where raw material prices are fluctuating within short span. Thus, a review also would not have addressed the problems of the domestic industry. The change in the form of duty alone can address the problems of the domestic industry.
 - iv. The Anti dumping legislation has been created in consonance and in conformity with the WTO Agreement on Anti Dumping, which explicitly permit Authorities to impose anti dumping duties in the form and manner requested.
 - v. Experience generated out of fairly large number of investigations (more than 300 investigations have been conducted so far spread over more than 15 years) that attempts are made to evade anti dumping duty imposed. A large number of complaints made by spectrum of industries over a long period with regard to circumvention of anti dumping duties are relevant in this regard. The Authority should not recommend a form of duty that would promote circumvention of anti dumping duty and should recommend such form of duty which is susceptible of minimum abuse/misuse.

- vi. The anti-dumping duty legislation the world over aims at protecting the domestic industry from unfair trade practices. The entire purpose for which anti dumping duty is proposed to be imposed is getting frustrated with the current form of duty. The duty should be imposed in a manner where it does not become futile.
- vii. Reference has also been made to the order of CESTAT in a few matters:—
 - in the case of NBR from Korea, the Hon'ble CESTAT modified variable anti-dumping duty recommended by the Authority to fixed duty .
 - in the case of Metcoke, the CESTAT, vide their decision 2000(116) E.L.T. 67 modified the anti-dumping duty from variable to fixed.
 - in the case of Vittrified files, the CESTAT upheld the decision of the Authority to impose fixed quantum of duty.
- Duty in US dollars: the duty should be imposed in terms of US\$ only for the following reasons:
 - a. The Authority has already expressed anti dumping duty in terms of US\$ in a number of other investigations. Rupee has depreciated significantly and therefore, the definitive duties may kindly be expressed in US\$. This is also supported by the rationality involved in the decision of the CESTAT in the matter of Metcoke from China. If the grounds for converting anti dumping duty into US\$ (from INR) has been appreciation of US\$, that too at appellate stage, the same ground cannot become a ground for imposition of anti dumping duty in INR.
 - b. The input costs of the domestic industry are directly influenced by the increase in the exchange rate. Firstly, the domestic industry has imported raw materials and therefore exchange rate impact is directly felt on the input costs. Secondly, even the domestically procured inputs are impacted by the US\$ appreciation, as those input costs are directly or indirectly impacted by US\$ appreciation. Therefore, if the domestic industry cost structures are impacted by US \$ appreciation, it is necessary to recommend anti dumping duty in US \$ form.
 - c. The Authority has recommended anti dumping duty in terms of US\$ in almost all the cases in last two years. Such being the case, there is no reason why duty should not be imposed in US\$ in the present case.

Examination by the Authority

9.

The submissions made by the interested parties have been examined as follows and in relevant sections of these findings:

- As regards the contention that the petitioner has claimed excessive confidentiality, even volume information has been provided on confidential basis; the Authority notes that it is not correct to state that volume parameters have to be necessarily disclosed, irrespective of the merits of the claims made. It is further noted that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on

confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

- As regards the form of measures; the Authority recommends the form of measures as per the facts and circumstances of each case. It is further noted that the antidumping duty imposed in the instant matter for about past ten years in the form of reference price has largely remained ineffective as the domestic industry herein has continued to be in losses. Considering the facts and circumstances of this particular case, the Authority considers that it would be appropriate to recommend the AD measure in fixed form basis as against the reference price recommended earlier.
- As regards imposition of the AD measure in Indian Rupees is concerned; the Authority notes that the entire analysis of dumping has been undertaken in US Dollar terms. Besides, it is not certain whether the Indian Rupee would continue to slide downwards and would not stage a recovery in future. Therefore, the Authority considers it appropriate to recommend the measure in US Dollar terms.
- As regards the contention that the information has been suppressed by petitioner on account of imports made by ADL; the Authority notes that M/s Aarti Drugs Limited had effected significant imports of the subject goods under various duty exemption schemes of the govt. and also considering the submissions made by the interested parties regarding inclusion /exclusion of M/s. Aarti Drugs Limited, it has decided to exclude M/s. Aarti Drugs Limited from the ambit and scope of the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. As a consequence thereof, M/s. Unichem Laboratories constitutes as the domestic industry, being the only remaining producer of the subject goods and thus satisfy the requirement of Rule 2(b) of the AD Rules
- As regards the contention that the production of M/s Unichem constitutes 29.36% of Indian production and that Unichem is a small producer as their own production would be less than 25% of Indian production during injury period and therefore injury assessment based on Unichem data would not lead to objective analysis and fair determination; the Authority notes that the same is not based on correct appreciation of the AD rules. AD Rules, *inter alia*, require that injury be examined and evaluated in relation to the domestic industry and the AD Rules further define the scope of domestic industry, which after the exclusion of M/s Aarti Drugs Ltd would mean that M/s Unichem constitutes the sole remaining domestic producer of the subject goods in India and hence has been correctly treated as the domestic industry.
- As regards the contention that the Authority has not determined the NIP based on the data of the domestic industry; the Authority notes that it has determined the NIP based on the verified data of the domestic industry and in terms of the principles laid down in Annexure III of the AD Rules and has accordingly determined the injury margin. Further, the Authority is also required to analyze

the reasons for the injury to the domestic industry apart from on account of dumped imports. In this connection, the Authority notes that Central Government has notified the maximum selling price of the subject goods w.e.f. 4.8.2008 at Rs.526/Kg. This in effect means that no one in India could sell the subject goods above this price irrespective of their actual cost of production/sales. The Authority, therefore, notes that the injury caused to the domestic industry on dumped imports could only be up to the DPCO notified price and it has accordingly determined the injury margin. Therefore, the contention of the domestic industry that the Authority should determine the injury margin based on the NIP only and ignore the DPCO price completely is devoid of merits. DPCO price is the ceiling price beyond which the product cannot be sold and therefore there is no bar on any one in selling the subject goods below the DPCO price and therefore in such a situation the Authority would consider only the NIP as the basis for determining injury as the same is lower than the DPCO price.

- As regards the contention that the determination of injury margin based on the current DPCO price; the Authority notes that DPCO price prevailing in POI is only relevant as the Authority is required to determine the injury margin for the POI.
- As regards the contention relating to capacity utilisation; the Authority notes that domestic industry besides manufacturing the subject goods in their plant also gets it manufactured through third party on job-work basis. The Authority has determined the NIP separately for the self manufactured goods as well as produced through job work and then considered the average NIP for determination of injury margin. The NIP has been worked out based on the principles laid down in Annexure III of the AD Rules.
- As regards the contention relating to re-determination of the constructed normal value and dumping margin; the Authority notes that it has constructed the normal value based on the information submitted by the domestic industry in their application. The Authority further notes that M/s Aarti Drug Ltd. had filed its information/data as part of the application and the same has been considered as M/s Aarti Drug Ltd, is more efficient domestic producer. The Authority further notes that it is required to construct normal value on reasonable basis and therefore it has considered best information available on record.

D. Misc Submissions made by interested parties and the Examination thereof

M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

10. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR, in brief, has submitted as follows:

- That the domestic industry has made inopportune submissions (Non Confidential) and has not kept other interested parties in the loop by sharing the information on time. The non-confidential version of the submission filed by domestic industry is not in accordance with the Trade Notice No. 01/2012 dated 09.01.2012 and guidelines prescribed by the Authority. The domestic industry has not provided non-confidential

version of above submission in a timely manner to the interested parties. Such non-confidential version of submissions should have been forwarded simultaneously to all other participating interested parties, while forwarding the same to the Designated Authority.

- The applicant industry has kept considerable information as confidential without providing any reasons such as capacity, production volume, capacity utilization, production on job work, domestic sales volume, export sales volume, and captive volume. The applicant industry has merely stated reasons for confidentiality as none of the information relating to Unichem Laboratory's economic parameters concerning MTZ is in public domain and company's consumers are not at all aware about the capacities with the company etc and that the company has not disclosed any of this information in its Annual Report. Reference in this regard has been made to Report of the Appellate Body in European Communities-Anti-Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China (WT/DS 397/AB/R dated 15th July, 2011).

Submissions made on behalf the Domestic industry

11. The Domestic industry in brief, has submitted as follows:

- **Inopportune submissions** – Hubei has stated that the submissions made by the domestic industry are quite late. It is submitted that the following is the sequence of events in this case:
 - a. A petition was filed jointly by Unichem and Aarti Drugs wherein Aarti Drugs pleaded its inclusion as domestic industry despite the imports made by the company.
 - b. While responding to notice of initiation, interested parties (primarily, Hubei) made submissions that Aarti Drugs should not be considered as domestic industry.
 - c. Domestic Industry at the time of hearing, reiterated its claim that Aarti should be considered as domestic industry. Domestic industry reiterated its claim in their written and rejoinder submissions.
 - d. Hubei at the time of hearing argued that Aarti Drugs should not be considered as domestic industry. Hubei reiterated its claim in their written submissions.
 - e. The rules do not provide for a decision by the Designated Authority before next stage of the proceedings i.e. disclosure document.
 - f. The prescribed proforma of the Designated Authority requires information on "*injury to the domestic industry*". This is clearly understood to mean "*domestic industry as a whole*".
 - g. The Designated Authority conducted verification in respect of Unichem but did not conduct verification of information of Aarti Drugs.
 - h. The case was initiated on 30th May, 2011 and the final findings are due on 29th May, 2012.

In view of the above, and having regard to the rules and the procedures being followed, the domestic industry on its own, even when there is no legal obligation, provided injury statement in respect of Unichem alone.

Under the law, the Authority has to decide whether to include or exclude a company from the scope of domestic industry. Further, if the Authority decides to exclude Aarti Drugs, consequences of the same shall follow.

The above position can be compared with the situation whether a number of domestic producers come before authority and provide information to the authority through different counsels. Some may even file information directly. Conflicting business interests amongst domestic producers may prevent such domestic producer from filing consolidated information. If so, it does not mean that the law will not protect such domestic industry only because they have not file consolidated injury statement. Appreciating such difficulties, in fact, an obligation has been cast on the Designated Authority to disclose all essential facts under consideration before the Designated Authority to all other interested parties before the Designated Authority takes a final decision. Further, opportunity for comments has been provided under the rules. Undisputedly, it not a case that the laid down procedure of issuance of disclosure statement shall not be followed in this case. In view of the above, there is no merit in the argument with regard to inopportune opportunity.

- As regards circulation of submissions to other interested parties; the fact is that they themselves have not served their submission to the domestic industry. In fact, the exporter must have filed several submissions during the course of the proceedings. Barring post hearing written submissions, none of the submissions made by Hubei have been served onto the domestic industry. An interested party cannot raise grievance against such non compliance, when such interested party itself has not complied with such requirement.

Notwithstanding, the fact that the Authority has made available a copy of our submissions to the interested parties through the public file and such opportunity has in fact being availed clearly establishes that the legal requirements under the law have been duly complied. It is relevant to point out that the only legal requirement under the law is that evidence presented by one interested party to the Authority should be made available to other interested parties participating in an investigation. Such evidence can be made available to other interested parties in any manner and so long as the evidence has been made available to the other interested parties, no grievance can be raised.

- **Confidentiality** – The exporter has raised objection on claim of confidentiality made by the domestic industry. The domestic industry submits that –
 - a) Only such information has been claimed confidential, confidentiality of which is permitted under the rules.
 - b) The domestic industry has given sufficient reasons for claiming confidentiality. If further reasoning/justification is required, we may be instructed.
 - c) The Designated Authority has on past occasions permitted such information to be treated as confidential. Kind attention of the Designated Authority is requested to the final findings relating to anti-dumping investigations concerning imports of Morpholine, wherein all such similar information were claimed confidential and allowed by the Authority.
 - d) It is submitted that the company has not publically disclosed such information. Reference to annual report is also drawn where such information is not separately available in the annual report.
 - e) Information such as production, capacity and capacity utilization is indeed confidential. Even other domestic producers do not have precise information about these parameters relating to Unichem. In view of very limited production of

this production globally, disclosure of this information can significant harm business interests of the company, who is competing with other domestic and Chinese producers in domestic and global market.

- f) As regards requirement under Schedule IV of Companies Act, it is submitted that the same concerns another government authority. As far as Designated Authority is concerned, the only legal requirement can be whether such information has been disclosed in the annual report. Sufficiency of such disclosures in the annual report under some other statutory requirements is not and cannot be a subject matter of present investigation. Should the Designated Authority however require an explanation, the company may be instructed.
- g) With regard to decision of the Appellate Body in the matter of European Communities – Anti-Dumping Measures on certain Iron or Steel Fasteners from China (DS 397/AB/B dated 15th July 2011), we submit that the Authority is required to consider the reasons for claiming confidentiality. It is submitted that the reference to report is totally misplaced. In fact, the WTO Appellate Body considered and accepted that the Investigating Authority was justified in allowing confidentiality.
- h) As regards right to defence, the Authority is required to examine injury to the domestic industry by considering performance of the domestic industry in respect of a number of economic parameters. Determination by the Authority is based on the trends in various economic parameters. If the DA has to assess injury to the domestic industry based on trends, relevance of absolute numbers in any case is not understood.

Examination by the Authority

12. The Authority has taken note of the submissions made by the interested parties and the same have addressed as follows and in the relevant sections of this document:
 - As regards inopportune time issues, the Authority notes that it receives submissions at various stages from the interested parties during the course of an investigation and the Non-confidential versions thereof are duly placed in the public file maintained in terms of the AD rules. The public file is readily made available for inspection by the interested parties, which has also been done in the instant matter.
 - The Authority notes that the information provided by interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.

E. Product under consideration and Like article

13. The product involved in the original investigation was 'Metronidazole'. This being a Sunset review, therefore, the investigation covers the product covered in the original investigation and the previous SSR investigation. Metronidazole is anti-diarrhea and anti-microbial drug. It is used in cases of Amoebiasis, Trichomoniasis, post-operative infection after surgery, giardiasis, acute ulcerative and gingivitis, anaerobic, vaginosis

treatment of infection caused by anaerobic micro formation. It is an organic chemical falling under heading No. 29332920 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS Classification. This classification however, is indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation.

14. The domestic industry also produces Metronidazole having similar characteristics and specifications. No argument has been extended, by any interested party on the issue of product under consideration or like article and therefore, the Authority considers that the product being manufactured by the domestic industry is 'like article' to the product under consideration as per the AD Rules.

F. Scope of the Domestic Industry

Submissions made on behalf of M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

15. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., in brief, has contended as follows:

- The domestic industry has falsely mentioned that petitioners are the only producers of the subject goods in India as M/s J. B. Chemicals is also a producer of subject goods in India.
- As per the settled practice, the name and address of known interested parties should have been supplied in the petition. In this case, petitioners had supplied incomplete list of interested parties in the petition as it is evident from the fact that exporter's names taken for likelihood parameters is missing in the list of known exporters. We believe such selective suppression of information is done with an intention to mislead the Authority of crucial information.
- M/s Aarti Drugs Ltd. has not only imported the subject goods from the China PR against advance license but has also imported significant quantities of PUC after paying duty during the period of investigation based on market intelligence. Considering these imports, M/s Aarti Drugs Ltd. should be excluded from the scope of domestic industry. Reference has been made to the findings of the Authority in the matters of *Anti-Dumping (Mid-term Review) investigations concerning imports of Phenol originating in or exported from Singapore, South Africa and European Union and Anti-dumping investigations involving imports of Phenol originating in or exported from USA, Korea-RP and Taiwan*. In case M/s Aarti Drugs Ltd. is included as part of domestic industry, any injury to the domestic industry would only be self-inflicted which cannot be considered sufficient to impose any anti-dumping duties.
- M/s Aarti Drugs Ltd. has submitted incorrect facts on relationship of petitioner with Exporter/Importer and justifications on imports by ADL to treat it as Domestic Industry as it has imported large quantities of the subject goods not only during the period of investigation but since 2000. Furthermore, it has a subsidiary company i.e. M/s. Suyash Laboratories Ltd which is also an importer

of the subject goods from China PR. Therefore, M/s Aarti Drugs Ltd. should be excluded from the purview of the domestic industry.

- The petitioners has incorrectly claimed that the injury to domestic industry is no way distorted because of imports made by M/s Aarti Drugs Ltd. as the capacity utilization of domestic industry would be less due to imports and cost of the domestic industry would have increased as a result of increase in the conversion costs and due to decline in the production because of imports made by M/s Aarti Drugs Ltd. Further, the total demand of the country includes consumption for the purposes of exports so whether the imports are for downstream product or not, would not make any difference.
- M/s Aarti Drugs Ltd has a related company in China PR and also has a subsidiary in India, which is the importer of subject goods.
- Contradictory statements have been made in the application filed by the Applicants and the emphasis is given to the one which is more advantageous. Moreover, it is apparent that petitioner has used pick and select option for its claim of injury. For depicting injury it has claimed that domestic industry is under-utilizing its capacity because of dumping of subject goods and not able to increase production whereas while defining domestic industry it has mentioned that M/s. ADL has been utilizing its plant capacity fully to meet the demand of subject goods and therefore importing the subject goods for downstream product. The two statements are self contradictory.
- Inadequate & Incomplete petition: The petitioners have failed to furnish injury information as per the prescribed format of DGAD. In Proforma-IVA, petitioners have mentioned installed capacity whereas in the petition they have stated effective capacity. Considering this contradictory statement, Proforma-IVA needs to be verified for installed capacity and any information on effective capacity may be treated only as additional information. Moreover, capacity utilization is not based on capacity provided in Proforma-IVA resulting capacity utilization also incorrect. Same contradictions can be further observed in relation to the volumes of opening and closing stock data given in the Proforma-IVA. Furthermore, the calculation of growth in Proforma IVA is also not correct as it has taken figure of current year in denominator. Therefore, the petitioners have misled the Authority on crucial facts which could have affected the injury parameters. The Authority should advise the domestic industry to revise their non-confidential Proforma-IVA with the correct information and provide us a copy of the same for our further comments.
- It has been contended that if the domestic Industry was not satisfied with the form of duty then they could have sought relief against the same as per provision of Section 9C of the Custom Tariff Act, instead of waiting for the sunset review. No justification has been provided by domestic industry as to

why it was silent on continued injury, if any, and form of duty for the last five years when they could have resorted to protection measures provided by law in this respect.

- All the imports for export purposes and all the imports by ADL and subsidiary company should be excluded for injury purpose as the same couldn't have contributed towards injury to the domestic industry.
- Majority of imports, almost 80%, of subject goods is against advance license and ADL and J.B. Chemicals are major importers of subject goods in India and also claim the status of producers of subject goods in India. All the imports made under advance license and the imports made by ADL and their subsidiary company ought to be excluded for analyzing injury to the domestic industry. Applying the same logic, duty-free imports must be excluded for the purpose of injury analysis.
- M/s Aarti Drugs Ltd.'s plant was closed for almost 4-5 month during investigation period due to temporary restrictions imposed by Gujarat Pollution Control Board (GPCB) and this would have resulted in increased imports during investigation period because consumers did not have any other option but to import, since the subject goods falls under the category of drugs. Therefore, non-availability of the same made imports necessary and as M/s Aarti Drugs Ltd is the major producer of subject goods and used to do job work for M/s Unichem also, the closure of plant of M/s Aarti Drugs Ltd has given rise to imports.
- The petitioners have taken effective capacity in Proforma-IVA for calculation of capacity utilization. The capacity has declined during investigation period from 1,418 MT to 899 MT as compared to the base year because of plant closure due to restrictions imposed by Gujarat Pollution control Board. Therefore, there is no effect on capacity of the domestic industry due to dumped imports but have effect from other factor which is restrictions imposed by Gujarat Pollution Control Board.
- There is no effect on the production and capacity utilization of the domestic industry over the injury period. The production has declined because of plant closure of M/s Aarti Drugs Ltd due to restrictions imposed by Gujarat Pollution Control Board and it has also mentioned in the petition that M/s. Aarti Drugs has been utilizing its plant capacity fully to meet the demand of subject goods and therefore importing the subject goods for downstream product. Moreover, in any case capacity utilization has increased from 77% to 92% during investigation period. Therefore, there is no effect on production and capacity utilization of the domestic industry due to imports.

- The domestic industry has taken effective capacity utilization in order to get benefit of optimization. The rules for determination of NIP (Annexure-III) say that Authority has to take optimum capacity utilization during injury period so for getting higher duty it has done so.
- If the Authority takes effective capacity utilization for determination of NIP, then the expenses of the period when the plant remains closed should be excluded from the cost and same cost should be used for injury analysis as well.
- The domestic industry was in losses since 2000-01 and losses of domestic industry has increased from 100 in 2007-08 to 220 in investigation period while selling price of domestic industry was above the reference price duty during injury period. However, reference price duty was calculated on the non injurious price in the sunset review case. This shows performance of domestic industry has not improved due to inefficiencies.
- The domestic industry was in losses because of 2 MNI cost and which is higher as compared to the international price. Further, the cost of the domestic industry has increased as a result of increase in the conversion costs and due to decline in the production because of plant closure of M/s Aarti Drugs Ltd which has been admitted by the domestic industry in the petition that partly injury from conversion cost. So, increase in conversion cost should not be considered for injury analysis purpose which is due to other factor (plant closure) after considering other factor domestic industry would be in above than reasonable profit. Thus, the decline in these factors if any cannot be said to be on account of alleged dumped imports. Therefore, we submit that injury to the domestic industry is due to 2 MNI cost and conversion cost.
- It is not true that cost of sales increased significantly during the proposed period of investigation as compared to the previous year partly due to increase in raw material cost and partly due to increase in conversion cost as the international price of 2 MNI was Rs. 182.05 per Kg in 2009-10 which has declined to Rs. 181.84 per Kg in investigation period. In fact cost of subject goods should have declined during investigation period as compared to previous year. This means raw material cost (2 MNI) of domestic industry was high as compared to international price. Therefore, cost of 2 MNI and increase in conversion cost due to other factors should not be considered for cost computing of subject goods for injury as well NIP purpose as petitioner's cost is high due to inefficiencies.
- It has been contended that adjustment for closure of plant of M/s Aarti Drugs Ltd is to be made not only with respect to capacity but with respect to all the factors of injury. The analysis after making the adjustment would be appropriate and give fair results. All figures ought to have been adjusted, particularly, sales, inventories, wages, costs, profitability, extra-ordinary costs like re-start costs, material losses, etc.

- The inventory analysis should also be made with respect to closing stock which would indicate that there is no injury with respect to inventories. It is also submitted that closing stock of subject goods was 133 MT as on 31.12.2009 whereas this figure has reduced to 49 MT as on 31.03.2010. Therefore, monthly stocks should be checked.
- The market share of the domestic industry has declined during investigation period because of plant closure due to restrictions imposed by Gujarat Pollution Control Board resulting in increase in imports. Authority must consider that the consumers did not have any other option but to import the material, since the subject goods falls under the category of drugs. Therefore, non-availability of the same makes imports necessary and as M/s Aarti Drugs Ltd is the major producer of subject goods and used to do job work for M/s Unichem also, the closure of plant of ADL has given rise to imports.
- Likelihood of continuation or recurrence of dumping and Injury: The domestic industry has given the information for normal value, export price and dumping margin with a view to show that there is a dumping from the subject country. The Authority should take into consideration only the actual figures made available to them by the cooperating producer and exporter while calculating the dumping margin.
- The domestic industry has miserably failed to make out a case of current injury or any likelihood of future injury. The domestic industry has merely mentioned about excess capacities in China PR but no evidence has been placed on record in support of their claim. Thus, there is no likelihood of continuance or recurrence of injury to the domestic industry nor any evidence placed on record in support of their claim of continuance or recurrence of dumping and injury to the domestic industry.
- Causal Link: It is submitted that the domestic industry has not made any analysis with respect to effects of imports by M/s Aarti Drugs Ltd and their subsidiary company and plant closure of M/s Aarti Drugs Ltd. We would, therefore, submit that the analysis for these factors may also be made which would indicate that injury, if any, to the domestic industry is not caused by imports from subject country but due to other factors as stated above.
- In view of the fact that neither there is any injury to the domestic industry from imports nor has the domestic industry been able to prove the likelihood of injury, no case has been made out for extension of the period of duties which must be allowed to be terminated in terms of Section 9A(5).

Submissions made on behalf of the Domestic industry

16. The Domestic industry has, in brief, contended as follows:

- Metronidazole has a long history of continued dumping in the country for more than a decade. Despite imposition of the anti-dumping duty and further extension thereof post the Sunset review investigation by the Authority, there have been continued imports in significant volumes from China PR at dumped prices.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI.	Post-POI*
Imports Volume						
Subject Country-China PR	MT	522	506	740	1,133	1,049
Other Countries	MT	12	26	28	-	92
Total Imports	MT	535	532	769	1,133	1,141
Import price from China PR	Rs./Kg	324.41	435.67	401.39	412.20	420.83

*Post-POI means Jan-Jun 2011 (annualized)

- The significance and purpose of imposition of anti-dumping duties is that domestic industry gets increased market opportunity to sell its material at fair prices. However, in the present case, volume of dumped import is hardly affected by the imposition of the anti dumping duty. In fact, the volume of dumped imports has substantially increased.
- Revocation of anti-dumping duty in force is bound to result in intensified dumping of product from China PR. Further, there is a likelihood of injury to the domestic industry.
- The form of measure in place has made the entire anti-dumping duty imposed before a redundant exercise. The Chinese producers are able to continue to dump the material and the imported product does not attract anti-dumping duty. Resultantly, the domestic industry is gradually getting reduced to minority.
- Such continued/increasing dumped imports of the product clearly imply that:
 - Despite levy of anti-dumping duty, the dumped imports from the subject country have been increasing over the injury period. This volume would definitely surge, if the current anti-dumping duty is allowed to cease, and
 - Present anti-dumping duty form is required to be modified to fixed quantum of anti dumping duty.
- China PR is a major exporter of Metronidazole and is exporting the product to many countries and that these producers hold significant exporting capacities of the product under consideration.

- vi. There has been a significant increase and then decline in import prices on month by month basis. It would be seen that:
- (a) Metronidazole prices were significantly high during June-September 2008, dipped sharply in October 2008 to Rs. 260 per Kg and then increased in January 2009 to peak at Rs. 584 per Kg.
 - (b) The import prices, however, declined thereafter to remain at Rs. 400 per Kg from February 2009 to December 2010, except in November 2009 when the import price increased to Rs. 529 per Kg.
 - (c) Whereas the weighted average cost of sales of the domestic industry has increased by Rs. 97 per Kg during 2009-10 and the POI; the landed price of imports has increased by only Rs. 16 per Kg in the same period. This shows that the import prices have not increased in tandem with the increase in the cost. Further the selling price of the domestic industry has dropped by Rs. 8.43 per Kg in this period, in spite of significant increase in the cost.
- vii. Even with the ADD, the price of the imports is significantly undercutting the domestic price. Thus, rendering the ineffectiveness of the reference price recommended by the Authority in the previous investigation.
- viii. Price attractiveness of the Indian market - Petitioner submits that the landed value of imports is at a price which is lower than the selling price of Domestic Industry.
- ix. It is evident that the landed price of Chinese imports is lower than the present and potential selling price of domestic industry. The Chinese producers would therefore aggressively target Indian market in the event of cessation of duty. Thus, the Chinese product is likely to become cheaper, should the domestic industry charge fair price from the market.
- x. The petitioners have noticed that they have inadvertently mentioned name of M/s Unichem Ltd. in the list of importers. M/s Unichem Ltd. is not an importer of the subject product.
- xi. Volume of imports by M/s Aarti Drugs Ltd. has already been disclosed. On review of information earlier provided with regard to quantum of imports, it is found that there were some double accounting of imports and the actual import volume in period of investigation is only *** MT.
- xii. Relationship and ineligibility of M/s Aarti Drugs Ltd. has already been disclosed to the Authority. As regards imports made by the related company or relationship with the exporter, followings are relevant.
- xiii. Meaning of relationship as defined by the Designated Authority: In the matter of Anti-Dumping investigations relating to imports of circular weaving machines, the Authority has held that the sole domestic producer was not related to the foreign producer despite admitted 35% shareholding by the foreign producer. It would thus be seen that the Authority has considered that a party is not related even when it has

35% shareholding. In the instant case, the holding is only 33.11 %. It cannot be said that M/s Aarti Drugs Ltd. is related to the foreign producer.

xiv. Whether facts of the case justify exclusion of M/s Aarti Drugs Ltd.:

- (a) M/s Aarti Drugs Ltd. is a domestic manufacturer of the product. As stated earlier, the company was directed by the Pollution Control Board to restrict its production to certain levels. In view of this restriction on production and considering the requirement of material for its exports and requirement of material with its consumer, the need to provide material to its customers, M/s Aarti Drugs Ltd. imported the material utilizing its exports of Metronidazole.
- (b) M/s Aarti Drugs Ltd. has a related company namely M/s Suyash Laboratories Ltd. The company is related because it has three common directors and an investment of more than Rs.*** crores in *** shares. This company is engaged in manufacturing of API (Active Pharmaceutical Ingredient). In view of financial issues involved, M/s Aarti Drugs Ltd. has imported some material through M/s Suyash. The material in these cases were arranged by M/s Suyash and sold to M/s Aarti Drugs Ltd., on high sea sale basis. It is clarified that M/s Suyash has not filed bill of entries for clearance of the material.
- (c) M/s Aarti Drugs Ltd. has an investment of ***% in M/s Huanggang Yinhe Aarti Pharmaceutical Co. Ltd. (Yinhe). This company is engaged in manufacturing of, *inter-alia*, Metronidazole. However, petitioners submit that the Authority should hold that this investment does not tantamount to relationship. The final findings of the Authority in the matter of circular weaving machines are referred to and relied upon.
- (d) Details of imports made by M/s Aarti Drugs Ltd. have already been disclosed to the Authority. These imports included imports made by M/s Aarti Drugs Ltd. through M/s Suyash as well. On review of the imports, it is found that the company has inadvertently reported some imports more than once. The revised import statement has been provided to the Authority.
- (e) M/s Yinhe has not exported the product directly to the Indian parties. It would be seen that –
 - M/s Aarti Drugs Ltd. is an importer of the product under consideration and is related to M/s Suyash.
 - M/s Suyash has arranged some imports. However, M/s Suyash is not an importer of the product under consideration. M/s Suyash has only arranged these imports and has not filed bills of entries.
 - M/s Yinhe is not related to M/s Aarti Drugs Ltd., as the shareholding is only *** % and is not a majority shareholding. Notwithstanding, M/s Yinhe has not exported the product. Notwithstanding further, these imports have already been disclosed as imports made by M/s Aarti Drugs Ltd.
 - The imports by M/s Aarti Drugs Ltd. are under duty exemption schemes;
 - The company was importing the product even at the time of original investigation as also previous Sunset Review investigations. After due consideration, the Authority has considered M/s Aarti Drugs Ltd. as an eligible domestic industry in the Sunset Review investigations;

- M/s Aarti Drugs Ltd. has a related company, M/s Suyash, who has imported the product only on behalf of M/s Aarti Drugs Ltd., and who has not filed any bill of entry for clearance of material. M/s Suyash should not therefore be considered as an importer of the product;
 - M/s Aarti Drugs Ltd. had production restrictions during this period and therefore some imports by the company were made to meet requirement of its customers.
- xv. In view of the above, it is submitted that the Authority should continue to treat M/s Aarti Drugs Ltd. as an eligible domestic industry. Notwithstanding, the Authority may treat M/s Aarti Drugs Ltd. as ineligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) and hold that M/s Unichem Ltd. constitutes domestic industry within the meaning of the Rules.
- xvi. Petitioner submits that in view of arguments by the interested parties with regard to relationship and imports made by M/s Aarti Drugs Ltd., the Authority may kindly consider excluding M/s Aarti Drugs Ltd. from the scope of domestic industry. Resultantly, M/s Unichem Ltd. shall form the domestic industry and the Authority is requested to kindly consider injury to the domestic industry by adopting data of M/s Unichem Ltd.

Examination by the authority

17. Rule 2(b) under the AD Rules provides as follows:-

"domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers.

18. M/s Aarti Drugs Ltd. and M/s Unichem laboratories Ltd. (India), had filed the application in the instant matter alleging dumping of 'Metronidazole' originating in or exported from China PR and requested for review and continuation of the anti-dumping duties. It was stated that they represent the domestic industry as the other domestic producers of the subject goods have already stopped their production. Thus, as per information available on record, the Applicants account for the total Indian production of the subject goods. The Authority had requested the domestic producers of the subject goods to provide requisite information. In response thereto, only M/s Unique chemicals (a division of M/s J.B. Chemicals and pharmaceuticals limited) filed its reply stating that they were earlier manufacturing Metronidazole. However, they are no longer manufacturing this product and they have closed production of Metronidazole since December 2010 and they have been buying Metronidazole from M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. Hubei, China.
19. It is, however, noted that M/s. Aarti Drugs Limited has imported *** MT of the subject goods under the duty exemption schemes out of the total imports of *** MT

during the POI viz. 1st January 2010 till 31st December 2010. It has been contended by them that these imports were necessitated in order to meet their commitments.

20. Opposing interested party has filed its submissions, as mentioned above, contending, *inter alia*, that M/s. Aarti Drugs Limited should be excluded from ambit and scope of the domestic industry. The domestic industry has also filed its submissions on the subject contending, *inter alia*, that it should be included as a part of the domestic industry. Considering the submissions made by the interested parties regarding inclusion /exclusion of M/s. Aarti Drugs Limited and the quantum of imports of the subject goods made by M/s. Aarti Drugs Limited, the Authority is of the view that it would be appropriate to exclude M/s. Aarti Drugs Limited from the ambit and scope of the domestic industry in terms of Rule 2(b) of the AD Rules. As a consequence thereof, M/s. Unichem Laboratories constitutes as the domestic industry, being the only remaining producer of the subject goods and thus satisfy the requirement of Rule 2(b) of the AD Rules.

G. Dumping Determination

Submissions made by M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

18. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR, in brief, has submitted as follows:
- M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd has submitted that dumping determination should be done as per the co-operative respondent's data.
 - Constructed Normal Value: If the authority constructs the normal value for Chinese Metronidazole producers/exporters taking into account the international prices of major inputs, consumption norms of the responding Chinese producers/exporters, conversion costs and SGA expenses of the Indian domestic industry and a reasonable profit margin of 5%, it is requested that the Authority may consider the following elements and make appropriate adjustments when constructing the normal value to ensure a fair comparison between the normal value and export price:
 - a. The purpose of the constructed normal value is to construct an ex-factory domestic selling price of Metronidazole for Chinese producers/exporters.
 - b. M/s Unichem's production cost of subject goods of may be very high due to their inefficiencies or due to higher 2 MINL cost; and thus should not be considered for constructed normal value.
 - c. the Authority should use the consumption norms of raw material as provided by the cooperating Chinese producers/exporters to determine the Constructed Normal Value instead of the consumption norms of domestic industry which is suffering from inefficiencies.
 - d. in the present case the Authority should not consider the Finance Cost as part of cost for determination of constructed normal value as the domestic price of Chinese producer might get disregarded due to non-market economy status. However, the credit cost related to credit days has been deducted from export

price for arriving at net export price. Therefore, in case domestic price of Chinese producer/exporter is disregarded, the finance cost should not be considered in constructed normal value vis-à-vis export price.

Submissions made on behalf the Domestic industry

19. The Domestic industry in brief, has submitted as follows:

- **Constructed normal value** – The following submissions have been made:
 - (a) **Import price** – the import price of inputs from China cannot become international prices, particularly in the present case, as the Chinese producers have not been granted market economy status. Once Chinese producers are considered as non market economy companies for MTZ, they are non market economy companies for its raw materials as well. It is pointed out that the raw materials and finished products both are normally being produced by the same set up of companies in China. Thus, if Chinese companies are non market economy companies for MTZ, they are non market economy for 2MNI and MI as well. The authority may kindly construct normal value by considering the international prices of these inputs after excluding imports from China.
 - (b) As regards consumption norms, we submit that the same cannot be accepted if the company has been given non market economy treatment.
 - (c) As regards legal basis submitted by Hubei, we submit that the legal understanding of Hubei is that the purpose of normal value is to construct ex-factory domestic price of Chinese producers/exporters and not to construct ex-factory domestic price for Indian domestic industry. Referring to para 7 of Annexure 1 of the AD Rules, it has been contended that the normal value in case of non market economy companies shall not be based on domestic selling prices in such country. In fact, it shall be based on cost or price in market economic third countries, including India.
 - (d) With regard to the contention that the cost of production of Unichem may be high due to their inefficiencies, the domestic industry submit that (i) the argument is mere conjecture and is without evidence, (ii) Unichem is an efficient manufacturer of the product and various commodities in the Country. There is no legal basis for dubbing Unichem as an inefficient producer. In fact, the exporter should not be allowed to make such kind of wild statements which are not substantiated with evidence.
 - (e) Import price of 2MNI from China, in any case, cannot be adopted for the reason that if the Chinese producers are being given non market economy treatment for MTZ, the same producers are producers for 2MNI and MI as well. The authority can consider 2MNI import price from China only when it is found that the same is representative of international prices
 - (f) As regards reference to carbon black case, the same is without any legal and factual basis. It is quite possible that the Designated Authority found in that investigation that the consumption factors reported by the exporters were credible enough despite the non market economy treatment given. Since the issue concerns a highly disputed question of fact, the authority may not kindly refer to any other

investigation and may kindly come to an independent judgment considering facts and circumstances of present case.

- (g) As regards finance cost, the argument deserves to be rejected. Hubei appears to be considering that cost of production for the purpose of normal value includes finance cost only on account of credit allowed on sales. The finance costs included in determination of normal value are actually the cost towards the finances deployed by manufacturing organization in fixed assets and working capital. Further, the Designated Authority may kindly follow established practice in this regard.

Examination by the Authority

Normal value

20. The Authority sent questionnaires to the known exporters/producers from the subject country, advising them to provide information in the form and manner prescribed. In response thereto, only M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd, a producer & exporter from China PR has co-operated in this investigation by filing their questionnaires' response.
21. The Authority notes that in the past three years China PR has been treated as a non-market economy country in anti-dumping investigations by India and other WTO Members. China PR has been treated as a non-market economy country subject to rebuttal of the presumption by the exporting country or individual exporters/producers in terms of the AD Rules.
22. As per Paragraph 8 of Annexure I of the AD Rules, the presumption of a non-market economy may be rebutted, if the exporter(s) /producer(s) from China PR provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph (3) of Paragraph 8 and establish the facts to the contrary. The co-operating exporters/producers of the subject goods from People's Republic of China are required to furnish necessary information/sufficient evidence as mentioned in sub-paragraph (3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Authority to consider the following criteria as to whether:
 - the decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs, including raw materials, cost of technology and labour, output, sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard, and whether costs of major inputs substantially reflect market values;
 - the production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non-market economy system, in particular in relation to depreciation of assets, other write-offs, barter trade and payment via compensation of debts;
 - such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

- the exchange rate conversions are carried out at the market rate.

23. The Authority notes that consequent upon the initiation notice issued by the Authority; M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd. a Chinese producer/exporter has submitted the questionnaires' response including the market economy questionnaire's response and sought to rebut the non-market economy presumption. However, during the course of on-the spot investigation at the premises of the Chinese company, the company was not able to substantiate its MET claim and hence it decided to forego the same. The questionnaires' response was perused, wherein it has been, *inter alia*, stated that the goods sold in domestic market and goods exported to India are identical.

Determination of Normal value in respect of Exporters/Producers from China PR

24. As the only co-operative exporter/producer from China PR has not been able to rebut the MET presumption and instead has chosen to forego its MET claim and no other Chinese producer/exporter has submitted the questionnaires' responses and sought to rebut the MET presumption; the Authority has determined the Normal value in China PR on the basis of Para-7 to Annexure-I to the AD Rules.

25. Para 7 of Annexure I of the AD Rules provides that

"In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Accounts shall be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments".

26. As the presumption of non-market economy as enshrined in para 8(2) of Annexure I of the AD Rules remains un-rebutted; the Authority, therefore, has determined the Normal value in accordance with para 7 Annexure I of the AD Rules. In absence of sufficient information on record regarding the other methods as are stipulated in para 7 of Annexure I of the AD Rules, the Authority has determined the Normal value by adopting the method "any other reasonable basis".

27. In view of the above, the Authority has constructed the Normal value for China PR. It is noted that to manufacture the subject goods, major raw materials are Acetic Acid, 2-MNI, Sulphuric Acid, Ethylene Oxide and Caustic Soda. For construction of the Normal value the international prices of 2MNI, Acetic Acid and Sulphuric acid has been considered; whereas for other major raw materials- Ethylene Oxide and Caustic Soda, the Authority has relied upon efficient domestic producer's procurement price as their international prices are quite abnormal. Besides, the consumption factor, conversion costs, SGA expenses and the finance cost of efficient domestic producer have been considered. A reasonable profit margin of 5% has been added thereto. The Normal value so determined works out as *** USD/Kg.

Export Price

M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

28. The Authority notes that only one Chinese producer/exporter, namely M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., has submitted the questionnaires' response. On a perusal of the response. It has been noted that the company has exported *** MT of the subject goods to India during the POI. The adjustments claimed and as verified during the on-the-spot verification have been accepted on account of inland transportation, overseas freight, overseas insurance, handling expenses, Commission, Credit costs and bank charges. During the course of on-the-spot verification, it was further noted that no adjustment for VAT were made by the company, despite the fact that the company was paying VAT @ 17%. During the verification, the company claimed that they are getting VAT refund @ ***%. Hence, the differential of the VAT amount has also been adjusted. The net export price so worked out has been determined as *** US\$/Kg.

Non-co-operative exporters/producers

29. As no other exporter/producer has provided any information that can be used for determination of the export price, the Authority has determined the 'Export Price' on the basis of 'facts available' on record, based on least representative transactions, which works out as *** US\$/Kg.

H. Dumping Margin

30. On the basis of the Normal value and Export price so determined at ex-factory level; the dumping margin during the POI for all exporters/producers from China PR has been determined as follows:

Exporter/producer	Country	Dumping Margin (USD/Kg.)	Dumping Margin	Dumping Margin range
M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd	China PR	***	***	30 - 40

Any other	China PR	***	***	50 - 60
-----------	----------	-----	-----	---------

I. Continuation or recurrence of dumping:

Submissions made by the domestic industry:

31. The domestic industry has, in brief, contended as follows:

- In a situation where there are continued exports, the Authority must examine whether the same were at dumped prices. In case exports to India are not at dumped prices, it must be examined whether the exports to third country are at dumped prices and whether it appears that the export prices are reasonable and reliable to establish that there is no likelihood of dumping. In case exports to India are at dumped prices, it should be held that the exporters would continue to export the subject goods at dumped prices, in case of revocation of anti dumping duties. In case the current exports are at un-dumped prices, it must be examined whether the exporter is likely to maintain these prices in the event of revocation of anti-dumping duties. If the exporter is unlikely to maintain these prices in the event of revocation of anti-dumping duties, the Authority must determine the price at which the exporter is likely to export in the event of revocation of anti-dumping duties and thereafter determine whether those exports are at dumped prices. It is to be noted that landed value of China PR is far lower than even the benchmark price leave aside the selling price of the domestic industry and once the anti-dumping duty is revoked, the imports are likely to enter at a significantly lower price.
- In the present case, the exporters and producers from the subject country have continued to export the material at dumped prices, even after imposition of the dumping duty as may be seen from the table below:

Nature of Investigation	Dumping Margin (%)
Original	47.85%
Sun Set Review-I	68.67%
Present Investigation	29.08%

- Petitioner submits that the above-mentioned data would establish the likelihood of dumping in case of subject country.

A. Dumping margins determined in all previous investigations relating to the product concerned

- The Authority has conducted two anti-dumping investigations concerning imports of Metronidazole from China PR. Both, previous investigations i.e. original

investigations as well as sunset review investigation have established existence of significant dumping.

- In the current Period of Investigation also, the Dumping Margin is quite significant. Further, there is likelihood that once the duty is revoked, the dumping would intensify. Conclusion can be drawn on the basis of increased volumes of dumped imports in injury period from the subject country. This clearly establishes that the dumping is likely to continue and indeed intensify in the event of revocation of present anti dumping duty.
- Sufficient information has been provided in respect of the dumping margins that continue to be significant. In the previously concluded investigation also, the Authority had found significant dumping margin and concluded the investigation with the imposition of the anti-dumping duty on the imports of the subject goods from the subject country.

B. Excess Production Capacities in the subject country

- Exporters in the subject country have capacities far in excess of Indian demand, considering that there are significant exports from subject country to various countries. The table below, shows production capacities of some of the Chinese producers:

S.N.	Producers In China	Capacity/ Supply Ability (MT per annum)
1	Hubei Hongyuan Pharmaceuticals Co. Ltd.	5,000
2	Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd.	5,000
3	Hangzhou Tiankai Import and Export Co. Ltd.	5,000
4	Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd.	1,000
5	China Foodpharm Group Co. Ltd.	7,200
6	Shijiazhuang Viture Import Export Trading Co. Ltd.	500

- There is continued dumping from the producers and exporters from subject country, which would become more aggressive once the duty in force expires. The intensity of dumping is likely to increase in the event of revocation of the anti-dumping duties. Thus, dumping is likely to continue at increased level in the event of revocation of anti-dumping duties.

C. Price attractiveness of the Indian market

- Landed value of imports are at a price which is lower than the selling price of Domestic Industry.

Particulars	Unit	POI
Landed Value of imports	Rs./Kg	449.68
Net Sales Realization of Domestic Industry*	Rs./Kg	***
Cost of sales of the domestic industry*	Rs./Kg	***
Target selling price of the domestic industry (DPCO notified price)	Rs./Kg	526.00

**Assuming that only Unichem represents Domestic industry*

- It is evident from the table above that the landed price of Chinese imports is lower than the present and potential selling price of Domestic Industry. The Chinese producers would therefore aggressively target Indian market in the event of cessation of duty. Thus, the Chinese product is likely to become cheaper, should the domestic industry charge fair price from the market.

D. Increase in market share of imports held by the subject country in the Indian market

Market Share in demand	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI
Subject country	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
Other Countries	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16
Domestic industry	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
Other Indian Producer	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14

- It is submitted that the market share held by China PR, during the injury period has not only been significant but also very high. In fact, significant share in the Indian market is being held by China PR. In spite of duty in force, the share held by China has not declined. On the contrary, the market share of dumped imports has increased.

E. Significant increase in the value and volume of import from Subject Country

- It can be seen that there has been a significant increase in the volume and value of import of the subject goods from the subject country. This increasing trend signifies that once the duty is revoked, the dumping would intensify.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI
Imports – Volume						
China PR	MT	522	506	740	1,133	1,049
Other Countries	MT	12	26	28	-	92
Total Imports	MT	535	532	769	1,133	1,141
Imports- Value						
China PR	Rs. Lacs	1,694	2,203	2,972	4,670	4,415
Other Countries	Rs. Lacs	46	106	146	0	503
Total Imports Value	Rs. Lacs	1,740	2,309	3,118	4,670	4,918

- It can also be seen that the rate at which the import from China is increasing is much higher than that of other countries. In fact, import from other countries in the period of investigation is nil. Thus; it can be concluded that, revocation of Anti Dumping Duty will make the condition more vulnerable for the Domestic Industry.

F. Export orientation of producers and exporters in subject country

- It is submitted that the exporters from China PR have very high export orientation worldwide. The export percentage of the Chinese companies varies from 30%-100%. Hence, the dumping and injury is likely to recur at aggravated level in case the existing anti-dumping duties are terminated at this stage.

G. Price undercutting without anti dumping duty in force

- On a comparison of the landed price of imports without anti dumping duty with that of the selling price of the domestic industry, it would be seen that significant price undercutting exists. Hence, it can be concluded that, once the anti-dumping duty is revoked, there exists a very strong likelihood of recurrence of dumping. It may be seen from the data that the benchmark anti dumping duty is far lower than the current selling price of the domestic industry.

H. Even if one of the condition is satisfied, duty cannot be revoked

- Out of the above conditions discussed, it is not necessary that all conditions should exist for continuation of duty. There are numerous cases wherein the duty has been continued, if one or more parameters were satisfied.
- Given the facts of the instant case, and considering the above mentioned parameters, it is submitted that the dumping is likely to continue and consequent injury to the domestic industry is likely to be caused in the event of revocation of anti-dumping duty.

Submissions made by M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd

32. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd, in brief, has contended as follows:

- a) The claim of likelihood of dumping and injury to the responding industry is based on mere conjectures.
- b) Dumping in third country is not a valid ground in law.
- c) Mere surplus capacity of exporter cannot lead to a conclusion that there is imminent danger of material injury.

Examination by the Authority

33. In terms of relevant provisions, the following aspects need to be examined in a Sunset review investigation:

- Whether the dumping is continuing; and if so, whether it is likely to continue in the event of cessation of the anti-dumping duties;
- In case where dumping did not continue, whether the dumping would recur in the event of cessation of the anti dumping duties;

34. The AD Rules do not prescribe any specific methodology to examine the likelihood of dumping in a Sunset review investigation. However, in case there is a significantly positive dumping margin in respect of exports of the subject goods during the POI; then it is likely that dumping would continue in case of cessation of anti-dumping duty in force, unless the facts state otherwise. However, in case there have been no exports of the subject goods during the POI; then it would not mean that there is no likelihood of recurrence of dumping in case of cessation of anti-dumping duty in force. In such cases, other relevant factors are required to be examined, for instance, evidence, if any, regarding propensity of dumping, that may be determined by considering the exports of the subject goods in third country markets.
35. In the instant matter, the subject goods have been imported from the subject country during the period of investigation in significant volumes. In fact, the volumes of the subject goods from the subject country have been increasing over the injury period. It is noted that these goods have been exported at dumped prices and are significantly undercutting the prices of the domestic industry. In case, the anti-dumping duties are allowed to expire, the volume of the subject goods at dumped prices is likely to increase. This view is further buttressed, considering the unutilised capacities to produce the subject goods in China PR, which has not been disputed by any interested party.
36. In view of the above, the Authority notes that the subject goods are likely to continue to be dumped, if the present anti dumping duties is allowed to cease. Besides, cessation of the anti-dumping duty is likely to lead to increased volumes of imports of the subject goods from the subject country at dumped prices.

Injury

Submissions made by interested parties and the Examination thereof

M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR

37. M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd., China PR, in brief, has submitted as follows:
- Job work got done by Unichem Laboratories Ltd.- M/s Unichem is a small producer of subject goods in India and some production activity is carried out by M/s Aarti also on job work basis and that possibly the company has shown separate capacities for both these production. Therefore, the Authority should look into the same.
 - Capacity Utilization – the applicant industry has claimed capacity as confidential information in their submission dated 23.04.2012. Therefore, it is requested that the Authority should segregate and examine the injury caused by job work if M/s Unichem has not fully utilized their plant capacity of subject goods during the injury period.
 - Cost of Production – M/s Unichem were carrying out two types of production of subject goods during the injury period (i.e. job work and own production). Therefore, the Authority is required to compare the cost between own production and cost of job work production of M/s Unichem during POI. This is important to ensure injury to the applicant industry is not because of their small capacity or inefficiencies. If there is

higher cost of own production due to small capacity or their inefficiencies, the Authority should set aside the higher cost of production caused by inefficiencies while conducting injury examination.

- **Price Effect:** The landed price from China PR has declined from Rs.470 per Kg in 2008-09 to Rs. 433 per Kg in 2009-10 whereas selling price of applicant are showing increasing trend in the same period. Thus, the selling prices of applicant industry have increased in a situation when landed prices have declined. This reflects an inverse relationship and shows no correlation between landed prices vis-à-vis domestic selling prices. Thus, the imports from China PR have not affected the domestic prices.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Landed Price	Rs./Kg	358	470	433	445
Change	Rs./Kg	-	112	-37	12
Selling Price of Unichem	Rs./Kg	***	***	***	***
Change	Rs./Kg	-	59	17	-

- **Causal Link:** while landed prices have declined during 2009-10, the selling prices of domestic industry have increased clearly shows inverse relationship not to speak of causal link.

Submissions made on behalf of the domestic industry

38. The domestic industry, in brief, has submitted as follows:

Preliminary Submissions: Rule 2(b) of the AD Rules defines 'Domestic Industry' as *the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term 'Domestic Industry' may be construed as referring to the rest of the producers only....*

Production of the participating companies constitutes a major share in Indian production. Hence, the participating company constitutes "Domestic Industry" pursuant to Rule 2 (b) of the AD Rules. The opposing parties have argued that M/s Aarti Drugs Ltd should not be considered as a part of the domestic industry. While there is no import made by Unichem, M/s Aarti Drugs Ltd has provided detailed information with regard to imports made by it.

The Designated Authority may, as an alternative, consider M/s Unichem as eligible domestic industry and determine injury to the domestic industry based on M/s Unichem data alone and has also presented the injury information assuming that only M/s Unichem Laboratories is considered as domestic industry.

Segregation of Injury Information

Referring to Annexure II (iv) to the AD Rules, it has been submitted that M/s Unichem is a multi product company and has provided relevant information in respect of like article to the extent feasible and separately available. However, in those situations where the information is not separately available in respect of the like article, because separate identification of that information is not reasonably available, information has been provided in respect of narrowest group/range of products, which includes the like article and for which the necessary information is available and can be provided.

It has been contended that while conducting review investigation, the Authority is required to consider the extent to which any improvement in the performance of the domestic industry is related to the anti-dumping duty in force and whether the domestic industry is vulnerable to the injury if the existing duties are allowed to expire. In a sunset review investigation, injury analysis consists of the consideration of the economic situation of the domestic industry at the time of the original investigation vis-à-vis the post investigation developments in the economic situation of the domestic industry.

Further, in order to determine the current situation of the domestic industry; the domestic production, production capacity and capacity utilization, sales, stocks, employment, consumption, market share, price trends, profitability, investments and other factors are required to be considered. And if, as a result of this analysis, it is found that the imports are continuing to cause injury to the domestic industry, it can be concluded that the expiry of the duty in force would only lead to a further deterioration of an already weakened domestic industry. In a situation where there have been no imports, an examination with regards to the likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of expiry of the anti dumping duty in force is required to be conducted.

It has been contended that the Authority had conducted original and sunset review investigations, wherein it concluded that the domestic industry has suffered continued material injury. This may kindly be considered with regard to injury to the domestic industry in the current period.

- a) The demand of the product under consideration has increased throughout the injury period;
- b) Imports of the product under consideration have increased throughout the injury period with a significant increase during 2009-10 and thereafter in POI. However the imports from third countries have declined to the extent that there were no imports from third countries during POI.
- c) Imports increased significantly in absolute terms despite imposition of anti dumping duties.
- d) Imports increased significantly in relation to production and consumption of the product in India.
- e) Share of imports has remained very significant in relation to demand/consumption in India.
- f) Domestic Industry has claimed that they have been prevented from utilizing its capacities to the fullest extent

- g) The market share of China in total imports has significantly increased throughout the injury period and accounts for 83% of total imports during POI whereas that of other countries declined throughout the injury period.
 - h) Even after the existence of the current anti-dumping duty, imports from the subject country are undercutting the domestic prices.
 - i) The production of the domestic industry declined throughout the injury period with a significant decline during POI.
 - j) The capacity utilization of the domestic industry also showed the same trend as that of production.
 - k) The sales of the domestic industry declined throughout the injury period.
 - l) Market share held by Chinese producers in demand kept on increasing throughout the injury period, whereas the share of the Domestic Industry declined constantly in the injury period.
 - m) Despite anti dumping duty being in force, the Domestic Industry has not been able to earn profits. Should the current anti dumping duties cease, the domestic industry would be forced to sell its product at a price comparable to import prices. This would mean significant financial losses, negative return on investment and significant cash losses.
 - n) Return on investment and cash profits have followed the same trend as that of profitability..
 - o) The employment levels have remained constant throughout the injury period. Wages paid have, however, declined during POI. The productivity per day declined in 2008-09, increased in 2009-10 and then remained constant during POI.
 - p) The level of inventories have declined till 2008-09 but thereafter significantly increased during POI clearly showing the inability of domestic industry to sell its products in the market owing to low priced imports from subject country.
 - q) Growth of the domestic industry in terms of sales, production, capacity utilization, profits, return on investment and cash profits all are adverse.
 - r) The present situation clearly establishes that the imports would further increase from the subject country which will further intensify dumping of the subject goods in the Indian market in the event of revocation of anti-dumping duties.
 - s) The reason for increase in imports is Benchmark form of duty becoming ineffective.
 - t) Net Fixed Assets as a basis for determination of capital employed is incorrect and the Authority should consider net present value of the plants or at least gross fixed assets.
 - u) The amount of return on capital employed should be considered having regard to the age of the plant.
 - v) The fixed expenses should not be optimized based on production in some other year. The production of the product over the years is directly dependent on the product mix and therefore it would not be appropriate to conclude that the company has inefficiently utilized production capacities. The petitioner requests Authority to consider the actual level of plant utilization in the period of investigation
- **Job work got done by Unichem** – There is no basis for the argument that Unichem is a small producer of the subject goods. Production of Unichem constitutes 29.36% of Indian production. In fact, on several occasions, it has been held that those domestic producers whose collective output is more than 25%, they constitute a major proportion. Such being the case, labelling Unichem as a small producer is without any legal and factual basis. On the contrary, production by Unichem constitutes a major

proportion in Indian production. The quantum of job work were done by Unichem has steeply declined over the injury period. Hubei has argued that the company may have separate capacities for own production and job work production. It is clarified that the company has not installed capacities for getting production on job work basis. The question of capacity utilization for job work got done shall not arise. The domestic industry has provided separate information on job work.

- As regards cost of production, it is submitted that the Authority is required to consider actual costs incurred. No inference can be drawn by comparing cost of production in the job work and cost of production on own manufacturing, as the per unit cost of production during the relevant period directly influences the actual operations. If own production was not there, the fixed expense being incurred by the company and at present charged to own production would have been borne by job work; and vice-versa. Therefore, no interference can be drawn by inter-se comparison of job work production and own production.
- As regards possible inefficiencies or possible higher cost due to small capacities, the argument is without basis. There is no evidence that there are inefficiencies. The Authority may not kindly proceed based on conjecture and surmise. Since the statement is unsubstantiated with evidence, the same may be rejected on this ground itself.
- The capacity utilization of the company is not so low, nor is the cost of production abnormally high due to lower capacity utilization. Reference in this regard has been made to the decisions of the CESTAT in *Virchow laboratories ltd. vs Ministry of Finance*, 2002 (141) E.L.T. 60 (Tri. - Del.); *M/s. Nippon Zeon Co. Ltd., Japan & Others v. Designated Authority* [1997 (96) E.L.T. 126 (T)] ; *Rishiroop Polymers Pvt. Ltd. versus Designated Authority* 2000 (119) E.L.T. 157 (Tribunal)
- The price effect – The claim made by Hubei with regard to no price effect deserves to be rejected. Firstly, the domestic industry is already suffering significantly financial losses (because of benchmark form of duty). Should the present anti dumping duty be withdrawn, the financial losses suffered by the domestic industry would increase further. The selling price of the domestic industry is below the DPCO levels. Since the landed price of imports is below (a) cost of production, (b) selling price of the domestic industry, (c) DPCO price, (d) non injurious price; it follows that the cessation of the anti dumping duty shall have adverse price effect on the domestic industry.

It is also pointed out that landed price of imports increased in 2008-09 and the import volumes declined (it is reiterated that significant imports are under advance licence and therefore in any case there imports were made against export orders of the domestic industry). Further, the landed price of imports declined in 2009-10 and the import volumes increased. Import price increase in the POI is only marginal and the same were still lower than the prices prevailing in the POI. The increase in selling price of the domestic industry in 2009-10 is only reflective of the impact of increase in import price in 2008-09. Even when the import price in 2009-10 declined vis-à-vis preceding year, the same is still higher than the selling price in 2007-08.

Examination by the Authority

39. As regards contentions relating to improvement in all injury factors; the same have been appropriately dealt with in herein below:

40. The Authority notes that it has adopted its consistent practice to examine and evaluate the injury data over the injury period. However, in a SSR investigation, the Authority assesses whether the cessation of the duties is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and consequent injury.
41. The Authority has examined the injury parameters objectively taking into account the facts and the submissions made by the interested parties as follows:
42. Annexure-II of the AD Rules provide for an objective examination of both (a) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like articles; and (b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such articles. With regard to the volume effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India. With regard to the price effect of the dumped imports, the Authority is required to examine whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress the prices to a significant degree, or prevent price increases, which would have otherwise occurred to a significant degree.
43. For the purpose of current injury analysis the Authority has examined the volume and prices effects of imports of the subject goods from the subject country on the domestic industry and its effect on the prices and profitability to examine the existence of injury and causal link between dumping and injury, if any.

Volume Effect

Assessment of Demand

44. The apparent consumption of the subject goods in India may be defined as the sum of domestic sales of Indian producers and imports from all countries. The relevant details in this regard are as follows:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI *
Assessed Demand	MT	1,531	1,407	1,802	1,867	1,782
Sales of Domestic industry including captive	MT	227	234	277	268	175
Sales of other Indian Producer	MT	770	641	757	466	466
Imports – China PR	MT	522	506	740	1,133	1,049
Imports – Other countries	MT	12	26	28	-	92

Market share in Demand						
Domestic Industry	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
Other Indian Producers	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14
China PR	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
Other Countries	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16

**Post-POI means Jan-Jun, 2011(annualized)*

45. Apparently, the consumption of the subject goods has increased over the injury period, with a slight decline in 2008-09 (claimed to have occurred due to recession). It is seen that the sales of domestic industry declined in 2008-09 and then increased in 2009-10; but the sales volume declined once again in the period of investigation. Whereas the volume of dumped imports of the subject goods from the subject country increased significantly during the period of investigation. While no significant change in the trend in respect of Demand and imports is noticed in the post-POI period, there has been sharp decline in the domestic sales volume of the domestic industry during post-POI.

Import Volume and Market Share

46. With regard to volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports either in absolute terms or relative to production or consumption in India. In this regard, Annexure II (ii) of the AD Rules provides as under:

"While examining the volume of dumped imports, the said authority shall consider whether there has been significant increase in the dumped imports either in absolute terms or relative in production or consumption in India"

47. The information regarding imports and market share is indicated in the table given below.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI*
Imports-China PR	MT	522	506	740	1,133	1,049
Imports-Other	MT	12	26	28	-	92

Countries						
Total	MT	535	532	769	1,133	1,141
Market Share in Imports-China PR	%	97.66	95.07	96.31	100.00	91.94
Market Share in Imports-Other Countries	%	2.34	4.93	3.69	-	8.06

**Post-POI means Jan-Jun., 2011(annualized)*

48. It may be seen from the above Table that the volume of dumped imports both in terms of absolute and relative figures increased significantly during POI as compared to the base year. The same trend has been noticed in the case of volume of imports in the post-POI period.
49. The above mentioned situation exists, despite the existence of anti-dumping duty. The domestic industry has contended that if the market of Metronidazole would have been fair, it should have recovered from the past ill-effects of dumping. However, continued presence of the dumped imports has prevented it from gaining the market share to the extent it could have gained in the normal circumstances. Besides, inability of the domestic industry to produce to the extent of its installed capacities also shows the adverse effect of the dumped imports on the performance of the domestic industry. In case the anti-dumping duty in force is allowed to cease, the volume of dumped imports are likely to increase further.

Price Effect

Price Undercutting

50. With regard to the effect of dumped imports on prices, the Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports when compared with the price of like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. The following Table indicates the Net Selling price of the domestic industry, Landed price of the dumped imports and the price undercutting.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI*
Reference	Rs./Kg	405.06	455.25	480.10	461.61	452.44

price						
Net Sales Realization	Rs/KG	***	***	***	***	***
Landed price of imports	Rs/KG	357.83	469.32	432.40	444.05	453.34
Price undercutting	Rs./Kg	***	***	***	***	***
Price undercutting	Range %	10-20	0-10	10-20	5-15	5-15

**Post-POI means Jan-Jun, 2011*

51. It is seen that the landed price of the imports of the subject goods even with anti-dumping duties in force, is below the net selling prices of the domestic industry, thereby signifying significant price undercutting. In this case, the anti dumping duty in place is in the form of reference price, which is significantly lower than the net selling price of the domestic industry. Thus, the imports are likely to further undercut the domestic prices, in case the anti-dumping duties are allowed to cease. It is further seen that the landed price of the subject goods from the subject country is significantly below the non-injurious price of the domestic industry thereby implying price under selling.

Economic Parameters affecting Domestic Industry

52. As per Annexure II to the AD Rules, the Authority is required to examine the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned, which includes an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including natural and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments. Accordingly, various economic parameters of the domestic industry have been analyzed as follows:

Sales, Capacity, Production, and Capacity Utilization

53. The performance of the domestic industry in respect of sales, capacity, production, and capacity utilization has been as follows:

	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI*
Gross Demand	MT	1,531	1,407	1,802	1,867	1,782

23 58 927 12-14

Capacity	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	100	100	100
Own Production	MT	***	***	***	***	***
Production under loan	MT	***	***	***	***	***
Total production	MT	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	105	114	85	113
Capacity Utilization (Own production)	%	***	***	***	***	***
Trend	Index	100	78	116	116	161
Domestic Sales including captive consumption	MT	227	234	277	268	175

**Post-POI means Jan-Jun, 2011(annualized)*

54. It is seen that despite an overall increase in the demand over the injury period, the sales of the domestic industry declined in the period of investigation. Even the production of the domestic industry declined in the POI, despite that it had the capacity to produce more. The domestic industry has contended that its performance should have improved considering a) that the Government had earlier imposed anti dumping duty on the subject goods and (b) the demand for subject goods has been increasing. In such a scenario, the domestic industry should have increased its production by leaps and bounds; but it could not increase its production in spite of the increase in demand due to continued presence of the dumped subject goods offered by the producer/exporters from the subject country. It is thus seen that in spite of imposition of anti dumping duty and overall rising demand of the subject goods in India, the domestic industry has not been able to improve its production and sales and utilize its capacity to the fullest extent. It is further seen that in the post-POI period, though the capacity utilisation has improved, the domestic sales has declined.

Market Share

55. It is seen that the market Share of China PR has remained significantly high throughout the injury period. There has been an increase of nearly 30% in the market share of China PR from the base year to the POI. Further, while the market share of China PR has increased, but the share of the domestic industry has declined during the injury period, as would be evident from the following:

Market share in Demand	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI	Post-POI*
China PR	%	34.09	35.93	41.08	60.68	58.88
Other	%	0.82	1.86	1.57	-	5.16

Countries						
Domestic Industry	%	14.81	16.66	15.35	14.38	9.82
Other Indian Producer	%	50.28	45.54	42.00	24.94	26.14

**Post-POI means Jan-Jun., 2011*

Profit/Loss, Cash Flow, Return on Capital Employed

56. Information with regards to profits, selling price, return on capital employed of the domestic industry is as follows:

Particulars	Unit	2007-	2008-	2009-10	POI
Selling price	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	113	117	117
Cost of Sales	Rs./Kg	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	114	105
Profit on domestic sales	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-86	-143	-111
Profit before interest & tax	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-86	-143	-112
Cash Profit	Rs Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-85	-143	-111
Return on Capital employed	%	***	***	***	***
Trend	Index	-100	-66	-75	-60

57. The Authority notes that while the cost of sales increased by 5% in POI as compared to base year, the selling price has increased by 17% in POI as compared to base year. However, the domestic industry continued to remain in losses and in fact the losses have increased in the POI as compared to the base year.

58. The following table shows the details of cost of sales, selling price, landed value, profit/loss for the PUC in POI and post POI.

Particulars	Unit	POI	Post-POI*
-------------	------	-----	-----------

Cost of Sales	Rs/KG	***	***
Selling price	Rs/KG	***	***
Landed price of imports	Rs/KG	444.05	453.34
Profit/loss	Rs/KG	***	***
	Rs. Lacs	***	***
Profit/loss if the domestic industry were to match its selling price with the landed price of imports	Rs/KG	***	***
	Rs. Lacs	***	***

59. A perusal of the above data shows that the domestic industry has not been able to realize its costs of sales and if it were to sell the subject goods at prices matching the landed value of the imported goods due to cessation of duty, the Domestic Industry would suffer further significant financial losses. If the above situation occurs, the return on investment and cash profit would further worsen. Thus, cessation of anti-dumping duty is likely to cause significant adverse effect on the prices of the domestic industry.

Inventories

60. The following Table gives the details of inventory of the domestic industry during the injury period.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Average Stock	MT	12	12	15	53

61. It may be seen from the above table that while the inventory level during initial two years remained constant, it had increased sharply in POI indicating that domestic industry was not in a position to liquidate its stock due to dumped imports.

Employment, Wages and Productivity

62. The following Table shows the details of employment, wages and productivity per employee of the domestic industry during the injury period.

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Employment	Nos.	***	***	***	***

Trend	Index	100	100	102	102
Wages	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	160	89
Productivity per employee	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	77	115	114

63. It is seen that the domestic industry is a multi-product company. The number of employees has almost remained constant throughout the injury period. While the Wage cost had increased in 2009-10, it had declined in the POI. Similarly, while Productivity per employee had increased in 2009-10, it had marginally declined in the POI.
64. The following Table shows the growth of the domestic industry during the injury period:

Particulars	Unit	2007-08	2008-09	2009-10	POI
Growth Compared to Previous Year					
Production (MT)	%	-	5	9	-25
Sales Volume (MT)	%	-	10	20	-2
Selling price (Rs./KG)	%	-	13	4	-1
Cost of sales (Rs./KG)	%	-	-0.13	14	-7
Average stock (MT)	%	-	1	27	243
Return on Capital employed (% in negative)	%	-	54	-14	24

65. The domestic industry has registered a significantly negative growth both in terms of volume and price parameters. While the growth in most of the parameters, such as sales volume, production volume and profitability was positive in 2009-10, it had declined significantly in the period of investigation.

Magnitude of Dumping Margin

66. It is seen that the dumping margins are not only more than de-minimis but also significant. The cessation of the duties is likely to lead to continuation of dumping.

Conclusion on Injury

67. In view of the above, it is noted that:

- i. Imports from China PR have increased over the injury period and continue to command a majority share;
- ii. Volume of dumped imports is quite significant in relation to production and consumption in India;
- iii. There has been continued dumping of the subject goods from China PR and the dumping is likely to continue and increase if the anti dumping-duty is allowed to cease.
- iv. The domestic industry has not been able to utilize its capacity to the fullest extent and also increase its domestic sales in POI, despite increase in the demand.
- v. The selling price of the domestic industry increased up to 2009-10 and then declined in the period of investigation. Price undercutting has been significantly positive during the entire injury period;
- vi. The performance of the domestic industry in terms of production, domestic sales, market share, profits, return on investments, cash flow, etc. has deteriorated, whereas the same should have normally improved after imposition of anti dumping duties;

Likelihood of Continuation or Recurrence of Injury**Submissions made by the domestic industry**

68. The domestic industry has stated that in a review investigation, the Authority is required to examine the probable consequence of the expiry of the duty in force. There might be a situation where improvement in the present performance of the Domestic Industry post imposition of anti dumping duty is due to anti dumping duty being in force. In such a case, the Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury to the Domestic Industry apart from examination regarding improvements in the performance of the Domestic Industry. Further, in a case where the Domestic Industry might already be suffering injury, the Authority is required to examine whether likely dumping from subject country is likely to cause or intensify injury to the Domestic Industry. The domestic industry has further referred to the decision of the CESTAT in the matter of *Thai Acrylic Fibre Co. Ltd. v. Designated Authority* (Final Order No. AD/5/2010(PB), dated 30-4-2010 in Appeal No. AD/4/2009), wherein the Hon'ble Tribunal, *inter alia*, held the view "With respect to the injury determination, if the anti-dumping duty has had the desired effect, the condition of the Domestic Industry would be expected to have improved during the period the anti-dumping duty was in effect. Therefore, the assessment whether injury will continue, or recur, would entail a counter-factual analysis of future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers.

Thus the Designated Authority has to address the question as to whether the Domestic Industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted."

69. With regard to the likelihood of continuation of Injury, the domestic industry has drawn the attention of the Authority to Section 9 (A) 5 of Customs Tariff Act and to Article 11.3 of the WTO agreement in this regard. It has been submitted that the purpose of sunset review is to determine whether or not the expiry of the measures would likely to lead to continuation or recurrence of dumping and Injury. In a review investigation, the Authority is required to examine what would be the consequence of the expiry of the duty in force. This is a potential examination. Therefore, present performance of the Domestic Industry is relevant only to the extent that the same shows the existence or otherwise of continued injury. Improvement in the present performance may be due to anti dumping duty in force and in such a case, the Designated Authority is required to examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry. In a situation where the Authority holds that there is no continued injury to the Domestic Industry, the Authority should examine likelihood of recurrence of injury to the domestic industry in the event of expiry of the anti dumping duty in force and that in spite of the anti dumping duty being in force, the domestic industry has registered adverse performance in the period of investigation; there is a great likelihood of the injury to the Domestic industry in the event the anti dumping duty is revoked.
70. While the foregoing establishes that the present anti dumping duties should be extended further, it is submitted that the responding exporters must establish that dumping is unlikely to continue or recur in the event of revocation of anti dumping duties. Information that the exporter must provide to the Authority in order to establish no likelihood of continuation of dumping in the event of revocation of duty has earlier been provided with the petition. Unless the exporters establish on the basis of this information that dumping is unlikely to continue, intensify or recur in the event of revocation of anti dumping duties, it must be held that the dumping and consequent injury would continue or recur or intensify in the event of revocation of anti dumping duties. Reference in this regard has been made to a few decisions of the CESTAT relating to review investigations. It is evident from these decisions that in following situations, the inescapable conclusion would be that the dumping would cause injury to the domestic industry in the event of revocation of anti dumping duties.
 - (a) the price undercutting without prevailing anti dumping duties is positive;
 - (b) if the price undercutting from a particular country is negative, the Authority is required to consider whether the imports are likely to have price suppressing or depressing effect on the domestic industry.
 - (c) the landed price of imports is below not only selling price of the domestic industry but also non injurious price of the domestic industry.

The domestic industry has contended that the conditions stated above prevail in the instant case and therefore, the revocation of antidumping duties shall lead to likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury.

71. The domestic industry has stated the following to establish that there is a strong likelihood of continuation of injury in case of revocation of anti dumping duty.
72. Volume of imports between original period and subsequent periods has significantly increased. Besides there are excess production Capacities in the subject country as would be evident from the table below that production capacities of some of the Chinese producers are quite significant:

S.N.	Producers in China PR	Capacity/Supply Ability (MT per annum)
1	Hubei Hongyuan Pharmaceuticals Co. Ltd.	5,000
2	Hefei TNJ Chemical Industry Co. Ltd.	5,000
3	Hangzhou Tiankai Import and Export Co. Ltd	5,000
4	Hangzhou Ruijiang Chemical Co. Ltd	1,000
5	China Foodpharm Group Co. Ltd	7,200
6	Shijiazhuang Viture Import Export Trading Co. Ltd	500

73. Considering the known capacities available with some of the Chinese producers (nearly 24,000 MT), the Indian demand of less than 2,000 MT can be easily met entirely by dumped imports. Once the anti dumping duty is revoked there is a strong likelihood that the entire Indian demand may be catered by the Chinese producers. There is continued dumping from the producers and exporters from subject country, which would become more aggressive once the duty in force expires. The intensity of dumping is likely to at best increase in the event of revocation of anti dumping duties. Thus, dumping is likely to continue at increased level in the event of revocation of anti dumping duties.
74. **Price attractiveness of the Indian market:** Landed value of imports are at a price which is lower than the selling price of Domestic Industry. It may be mentioned that the landed price of Chinese imports is lower than the present and potential selling price of the Domestic Industry. The Chinese producers would therefore aggressively target Indian market in the event of cessation of duty. Thus, the Chinese product is likely to become cheaper, should the domestic industry charge fair price from the market. In the event of revocation of anti dumping duty, the Chinese producers will be able to increase their profitability and at the same time offer attractive lower prices to Indian importers and consumers. to switch over from Indian producers to Chinese exporters.

Actual state of affairs of the domestic industry during the period under review

75. The actual state of injury is evident from the submissions on injury above. The existing form of anti dumping duty has remained ineffective. Further there is a likelihood of continuation of injury in case no relief is granted.
76. The domestic industry has stated that the market share held by China PR, during the injury period has not only been significant but also very high. In spite of duty in force, the share held by China has not declined. On the contrary, the share of dumped imports has increased in the POI and continues to remain at the same level in the post-POI also.
77. It has been further stated that there has been a significant increase in the volume and value of import of the subject goods from the subject country and this increasing trend shows that once the duty is revoked, the dumping would intensify further.
78. It can also be seen that the rate at which the import from China is increasing is much higher than that of other countries. In fact, import from other countries in the period of investigation is nil. Further, the imports from China PR have continued in the post POI period at the same level and at dumped prices. Thus, it can be concluded that, revocation of Anti Dumping Duty will make the condition extremely vulnerable for the Domestic Industry.
79. **Export orientation of producers and exporters in subject country:** The domestic industry has stated that the exporters from China PR have very high export orientation worldwide. The export percentage of the Chinese companies varies from 30%-100%. Hence, the dumping and injury is likely to recur at aggravated level in case the existing anti-dumping duties are terminated at this stage.
80. **Price undercutting without anti dumping duty in force:** On comparison of the landed price of imports without antidumping duty with that of the selling price of the Domestic Industry, it would be seen that significant price undercutting exists. Hence, it can be concluded that, once the anti dumping duty is revoked, there exists a very strong likelihood of recurrence of dumping. It may be seen from the data that the benchmark anti dumping duty is far lower than the current selling price of the domestic industry.
81. **Vulnerability of the Domestic Industry:** The Domestic Industry has further mentioned that it continued to suffer injury from the dumped imports for quite some time as confirmed at the time of original investigation as well as previous sunset review investigation. It has been further submitted that Domestic Industry is vulnerable to injury from dumped imports. Current levels of import volumes and dumping margins from the subject country creates great possibility that expiry of duty will result in intensified dumping of subject goods from the subject country in the Indian market given the fact that subject country holds excessive capacities.
82. With regard to causal link, the domestic industry has drawn reference to Article 3.5 of the Anti-dumping Agreement and to Paragraph (v) of Annexure II of the Anti-dumping Rules. It has been contended that the causal link has already been established in the original investigation. In the present review investigations, the

Authority has to examine whether revocation of anti dumping duty would lead to continuance or recurrence of dumping and injury. Thus an examination of whether cessation of anti dumping duties would lead to continuation or recurrence of injury involves such an analysis that a positive finding would be recorded only if cessation of anti dumping duties would lead to continuation or recurrence of injury. This clearly establishes that a positive finding of injury would be recorded only in case there is a relationship between cessation of anti dumping duties and recurrence or continuation of injury. There exists a causal relationship between the likelihood of continuation or recurrence of dumping and likelihood of continuation or recurrence of injury, as would be seen from the submissions below.

- A. Volume and value of imports not sold at dumping prices:** - The domestic industry is facing injury from dumped imports entering into the country from China PR. There have been insignificant imports in the injury period and no imports in the period of investigation from other countries.
- B. Contraction in demand:** - The injury statement enclosed with these submissions contains information with regard to demand of the product under consideration over the entire injury period. It would be seen that the demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period except 2008-09. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
- C. Changes in the patterns of consumption:** - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is unlikely to contribute to the injury to the domestic industry.
- D. Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
- E. Developments in technology:** - Technology for production of the product has not undergone any change nor there are any likely changes in coming future. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
- F. Export performance:** - The petitioner exports the product under consideration. However, information relating to domestic sales only has been taken into consideration for assessment of injury to the extent possible.
- G. Performance of other products produced and sold by the domestic industry:** - Petitioner is a multi product company. However, information has been provided with respect to the product under consideration.

83. The domestic industry has further submitted that once it is shown that (a) there is a volume and price effect from dumped imports and (b) the effects of injury caused by dumped imports, the only basis on which to conclude that the injury is not caused by the dumped imports are through non-attribution analysis. As the listed known other factors do not establish that injury has been caused by those other factors, the only inescapable conclusion is that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports from the subject country.

Examination by the Authority

84. It is seen that the subject goods continue to be dumped from the subject country and the same continues to cause material injury to the domestic industry. It is further noted that despite the anti-dumping duty being in force, the domestic industry has not been able to earn profits. There is significant undercutting and underselling and should the current anti dumping duties are allowed to cease, the domestic industry might be forced to sell its product at a price comparable to import prices, which would mean significant financial losses and further decline in the return on investment to the domestic industry. Besides, there are significant capacities in the subject country to produce the subject goods. Thus, the Authority notes that there is likelihood of continued dumping from the subject country and the consequent injury to the domestic industry, should the anti-dumping duty is allowed to cease.

J. Causal Link

85. The Authority has examined the submissions with regard to the significance and relevance of causal link in a Sunset review investigation. It is important to note that under Section 9A(5) of the Act, the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties. Accordingly, as indicated in Para 67 and 84, the Authority has concluded that the dumped imports are causing injury to domestic industry and they are likely to continue and cause injury if antidumping duty were to be revoked. Notwithstanding this, the Authority has examined whether other parameters listed under the AD Rules have caused injury to the Domestic Industry.
- (a) **Volume and value of imports not sold at dumped prices:** - The domestic industry is facing injury from dumped imports entering into the country from China PR. There have been insignificant imports in the injury period and no imports in the period of investigation from other countries.
 - (b) **Contraction in demand:** - The Authority notes that the demand of the product under consideration has shown a positive growth throughout the injury period except 2008-09. Hence, contraction in demand is not a possible reason, which could have contributed to injury to the domestic industry.
 - (c) **Changes in the patterns of consumption:** - The pattern of consumption with regard to the product under consideration has not undergone any change. Change in the pattern of consumption is therefore could not have contributed to the injury to the domestic industry.
 - (d) **Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers:** - There is no trade restrictive practice, which could have contributed to the injury to the domestic industry.
 - (e) **Developments in technology:** - Technology for production of the product has not undergone any change. Developments in technology are, therefore, not a factor of injury.
 - (f) **Export performance:-** The domestic industry exports the product under consideration. However, information relating to domestic sales only has been taken into consideration for assessment of injury.

- (g) **Performance of other products produced and sold by the domestic industry:** - The domestic industry is a multi-product company. However, injury analysis has been made with respect to the product under consideration.
- (h) **Productivity:-** It is observed that the productivity of the domestic industry per day has increased during the injury period and therefore is a not a factor for the injury to the domestic industry.
- (i) **DPCO Price:** - The Authority notes that the Central Government vide notification No. S.O. 1944(E) dated 4.8.2008 has fixed the maximum sales price of Metronidazole at Rs.526/ per Kg. Therefore, the Authority holds that the injury caused to the domestic industry is partly due to the maximum sales price notified by the Government.

Magnitude of Injury and Injury margin:

86. The non-injurious price of the subject goods produced by the domestic industry as determined by the Authority has been compared with the landed value of the exports from the subject country for determination of injury margin during the POI. Thus compared, the injury margin is worked out as under:

Particulars	Unit	M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd	China PR - Others
NIP	Rs./Kg	***	***
Landed Price	Rs./Kg	***	***
Injury Margin	Rs./Kg	***	***
Injury Margin	%	***	***
Injury Margin	Range %	60 - 70	80 - 90

87. The Authority notes that the Central Government vide notification No. S.O. 1944(E) dated 4.8.2008 has fixed the maximum sales price of Metronidazole at Rs.526/ per Kg. Since the injury caused to the domestic industry is partly due to the maximum selling price notified by the Government, the Authority has considered this price for the purpose of working out injury margin that may be attributed to the dumped imports.

Particulars	Unit	M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd	China PR - Non-co-operative exporters/producers
DPCO Price	Rs./Kg	526.00	526.00

Landed Price	Rs./Kg	***	***
Injury Margin	Rs./Kg	***	***
Injury Margin	%	***	***
Injury Margin	% Range	10 - 20	25 - 35

K. CONCLUSIONS

88. Having regard to the contentions raised, information provided and submissions made by the interested parties and facts available before the Authority as recorded in the above findings and on the basis of the above analysis of the state of continuation of dumping and consequent injury and likelihood of continuation/recurrence of dumping and injury, the Authority concludes that: the subject goods are entering the Indian market from the subject country at dumped prices and dumping margin is significant. It is seen that the subject goods continue to be exported to India at dumped prices inspite of the existing anti-dumping duty. It is noted that even at present, that is, when the anti-dumping duties are in force, the price undercutting and price underselling are significant. Should the domestic industry attempt to match the same, it would have a significant adverse impact on the price parameters. Alternatively, it would have injury on volume parameters. Hence, injury to the domestic industry is likely to recur, in case the present anti-dumping duty is allowed to cease. It is further noted that as per information available on record, the anti-dumping duty is required to be extended and modified.

L. RECOMMENDATIONS

89. Having concluded as above, the Authority is of the opinion that the anti-dumping measure is required to be extended and the quantum of anti-dumping duty is required to be modified and extended in respect of imports of the subject goods from the subject country as specified in the duty table below.
90. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of anti-dumping duty equal to the lesser of the margin of dumping and the margin of injury, so as to remove the injury to the domestic industry. The Authority notes that for the last 10 years the AD duty for this product has been on reference price basis but the situation of the domestic industry remains highly fragile and it continues to be in losses. Apparently, the reference form of the duty has not been effective. Therefore, considering the facts and circumstances of this case, the Authority is of the view that it would be appropriate to recommend imposition of anti-dumping measure in fixed form basis. Accordingly, the antidumping duty equal to the amount indicated in Col 8 of the table below is recommended to be imposed concerning all imports of the subject goods originating in or exported from the subject country from the date of notification to be issued in this regard by the Central Government.

Duty Table

Sl. No	Heading/ Sub-heading	Description of goods	Country of Origin	Country of Exports	Producer	Exporter	Duty Amount US\$/Kg
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	29332920	Metronidazole	China PR	China PR	M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd	M/s Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd	1.49
2.	29332920	Metronidazole	China PR	China PR	Any	Any	2.57
3.	29332920	Metronidazole	China PR	Any	Any	Any	2.57
4.	29332920	Metronidazole	Any	China PR	Any	Any	2.57

91. Landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 and all duties of customs except duties under sections 3, 3A, 8B, 9 and 9A of the Customs Tariff Act, 1975.
92. An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Customs Tariff Act.

VIJAYLAXMI JOSHI, Designated Authority